



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 पौष 1938 (श0)
(सं0 पटना 12) पटना, सोमवार, 9 जनवरी 2017

सं० 1822 (H)
उद्योग विभाग

संकल्प

1 सितम्बर 2016

विषय:— राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

बिहार सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि यह राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, परंतु राज्य के समावेशी आर्थिक विकास में द्वितीयक प्रक्षेत्र अर्थात् उद्योगों का योगदान समान रूप में महत्वपूर्ण है, अतः इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। राज्य में निवेश के वातावरण में अग्रतर सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक पहल किए गए हैं तथा 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर लक्षित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 का सूत्रण किया गया है। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति आधारभूत संरचना पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रगतिशील तकनीक पर विशेष बल देते हुए भविष्य में विकास के मुख्य प्रक्षेत्रों को वरीयता प्रदान करना, कौशल विकास, एक संशोधित संरचित सहायता का पैकेज एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास अर्थात् निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में समाज के वंचित समूहों के उत्थान एवं महिला उद्यमियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनके लिए विशेष सहायता के पैकेज का प्रावधान किया गया है। नीति में इसके कारगर कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं उद्यमियों की शिकायतों को दूर किए जाने का सुपरिभाषित प्रावधान किया गया है। इस प्रकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए समेकित पहल है तथा इसमें बिहार आने वाले निवेशकों के लाभों के लिए विस्तृत प्रावधान है।

1. परिचय —बिहार भारत के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि में बिहार के जी0एस0डी0पी0 में वार्षिक 10.5 प्रतिशत की दर से निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक परिवर्तन की गति एवं पैमाने में वृद्धि देखी गयी है जो सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक घरेलु सुधार कार्यक्रम का परिणाम रहा है। इसमें सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण बात कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी में सुधार एवं सरकारी व्यय के साथ सार्वजनिक निवेश के सुधार में परिवर्तन रहा है। इन सभी परिवर्तनों ने राज्य में निजी निवेश एवं अधिक से अधिक उद्योग प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान की है।

बिहार के पूर्वी और उत्तरी भारत में, कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाह के रूप में, कच्चे माल के स्रोतों और पड़ोसी राज्यों से खनिज भंडार के बंदरगाहों के उपयोग एवं विशाल बाजार की उपलब्धता की वजह से एक अनूठा स्थान है एवं इससे राज्य को विशेष लाभ प्राप्त है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है एवं यह सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में फल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार बड़े पैमाने पर जल संसाधन में संपन्न है। जमीनी और सतह के पानी दोनों के रूप में राज्य में प्रत्येक वर्ष 1009 m.m.s औसत वर्षा होती है। राज्य की प्रमुख नदियों में गंगा मुख्य नदी है, जो हिमालय में अपने स्रोतों के साथ सहायक नदियों से जुड़ी हुई है। कुछ अन्य प्रमुख नदियों में से सरयू, गंडक, बुढ़ीगण्डक, बागमती, कमला और महानन्दा है। राज्य में प्रभावी औद्योगिक श्रम का एक बड़ा आधार है, जो राज्य के औद्योगिक विकास एवं उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला के रूप में राज्य को एक आदर्श स्थल बना रही है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, स्वास्थ्य आदि राज्य में तेजी से बढ़ते उद्योगों में से कुछ हैं। राज्य में कृषि उपस्कर एवं छोटे मशीन विनिर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय उर्जा आदि क्षेत्रों के विकास के लिए पहल कर योजना भी बनाई गई है।

बिहार पूरे जोश के साथ प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है। पर्याप्त सड़कों के अभाव में कोई राज्य अपने आर्थिक विकास में वृद्धि के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों को पटना की राजधानी से जोड़ने के क्रम में यह संकल्प लिया है कि लोग एक स्थान से राज्य के किसी भी जगह अधिकतम समय छह घंटे में दुरी तय कर वे राजधानी तक पहुँच सकते हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी किये हैं एवं परिणाम के रूप में सड़कों और पुलों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार ने "बिहार सड़क संसाधन सुरक्षा नीति, 2013" को अपनाया है ताकि बढ़ती सड़क नेटवर्क के बेहतर रख रखाव को सुनिश्चित किया जा सके।

बिहार राज्य में राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) की कुल लंबाई 4253 किमी है (2015 तक)। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा डबल लेन सड़कों का है दूसरे तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग का राज्य के आर्थिक विकास में सामरिक महत्व है। क्योंकि यह राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 4595 किमी है (2015 तक)। इसके नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए तीव्र गति से प्रयास भी किए जा रहे हैं।

स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे जो कि बिहार के कुछ जिलों यथा—कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया एवं पटना से होकर गुजरती है। ये जिले शाखा सड़कों के माध्यम से इस हाईवे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जिससे राज्य के अंदर एवं दूसरे राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बाजार एवं मांग के आधार पर उत्पादों को भेजना सुलभ हो पाता है। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, जिसकी लंबाई 204 कि० मी० है, को और चौड़ा किया जा रहा है।

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर भी बिहार राज्य से होकर गुजरती है एवं बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के साथ जोड़ती है, जो राज्य में उद्योगों के निवेश के लिए बेहतर है। इससे काफी कम परिवहन लागत के साथ कम समय में तैयार उत्पादों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाहों तक परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है।

राज्य सरकार ने उर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है, जिसके तहत वर्ष 2016-17 तक 1330 मेगावाट, वर्ष 2017-18 तक 3310 मेगावाट तथा 2021-22 तक 7270 मेगावाट बिजली की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जो राज्य के लिए पर्याप्त होगी। इस क्रम में उर्जा विभाग द्वारा अपनी परिकल्पना को हकीकत में बदलने के लिए बिहार राज्य उर्जा उत्पादन निगम लि०, (BSPGCL) द्वारा संयुक्त उपक्रम के तहत देश के प्रतिष्ठित कंपनियों यथा—नेशनल थर्मल पावर कॉ० (NTPC) एवं नेशनल हैड्रो पावर कॉ० (NHPC) के साथ इकरारनामा किया गया है। इसके तहत राज्य में अवस्थित बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं यथा नवीनगर स्टेज-1, बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय तथा बांका के विभिन्न चरणों को प्रारंभ किया जाना है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत राज्य की जरूरतों के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर से उर्जा की आवश्यकता कम होगी एवं राज्य उर्जा की आवश्यकताओं में पूर्ण करने में आत्मनिर्भर होगा।

राज्य के औद्योगिकरण के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नतीजतन भूमि अधिग्रहण का महत्व काफी बढ़ जाता है। उद्योगों तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती मांग को पूरा किये जाने के क्रम में 1500 करोड़ रुपये के निधिकोष के माध्यम से लैंड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये किया गया। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमि बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस मद में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को 1650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कलस्टर आधारित दृष्टिकोण के तहत चमड़ा, छोटी मशीनरी, प्लास्टिक कपड़े, जूट एवं वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिये जाने एवं विशेष कलस्टर एवं MSME उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

बिहार राज्य में निवेश की सुविधा के लिए एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यप्रणाली/उद्यम को अपनाया जा रहा है जिससे राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुछ मुलभूत सुधार के उपाय किए गये हैं, यथा शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन विभिन्न श्रम

कानूनो के तहत एकल एकीकृत प्रणाली, उद्योगो के जोखिम के आधार पर निरीक्षण अनुपालन प्रणाली, विभिन्न श्रम कानूनो/समकालीक संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान।

वर्तमान औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य में उद्योगो के लिए अनुकूल माहौल बनाने एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम निवेश करने के लिए लागू किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में यानि खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटी मशीनरी उत्पादन, आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक एवं रबर, अक्षय उर्जा, चमड़ा एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में उद्योगो की स्थापना के साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधनो के महत्तम मूल्य संवर्धन एवं राजस्व पैदा करने तथा रोजगार सृजन करना है। इस नीति का मसौदा विभिन्न उद्योग संघो, उद्योगो के प्रतिनिधियों, निवेशक, विषय विशेषज्ञो के साथ गहन बातचीत एवं उनके विचार को समायोजित करने के उपरांत तैयार किया गया है। यह उम्मीद है कि इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगीकरण के साथ रोजगार सृजन और समग्र विकास होगा।

2. हमारी दृष्टि, मिशन एवं रणनीति।-

2.1 हमारी दृष्टि।-संतुलित क्षेत्रीय एवं सतत विकास की प्राप्ति हेतु राज्य के तुलनात्मक खूबियों को बढ़ाकर एवं नियोजन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाकर बिहार को सबसे अधिक अधिमानता वाला राज्य के रूप में स्थापित करना।

2.2 हमारा मिशन।-

- 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर की प्राप्ति किया जाना।
- राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं "मेक इन इंडिया" पहल के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।
- सभी आर्थिक प्रक्षेत्रों में कुल मिलाकर 05 लाख लोगो के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किया जाना।
- 15 हजार करोड़ रूपये का वास्तविक निवेश आकर्षित किया जाना।
- राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च स्तर का आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना।
- निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक समरूप कर क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन को दूर किया जाना।
- समाज के उच्च प्राथमिकता वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगो, युद्ध विधवाओं, एसिड हमले के पीड़ितों तथा तीसरे लिंग के उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना।
- राज्य सरकार के "7 निश्चय" अन्तर्गत 1.50 करोड़ कुशल युवाओं के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों का कौशल विकास सुनिश्चित किया जाना।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना एवं "जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट" उत्पादन कार्यशैली को अपनाया जाना।

2.3 हमारी रणनीति।-हम वैसे निवेशको के साथ काम करेंगे जो भविष्य में बिहार के गतिशील अर्थव्यवस्था की हमारी दृष्टि से सहमत है, जो सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने को उद्यत है। विशेषकर हमारी रणनीति निम्नप्रकारेण है:-

- वैसे निवेशको को प्रोत्साहित करना जो कृषि उत्पाद में मूल्यवृद्धि करते हैं तथा कृषको की आमदनी को खाद्य फसलों के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण द्वारा बढ़ोतरी करते हैं, विशेषकर फलो, सब्जियों एवं फसलों को।
- हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए बड़े बाजार की तलाश कर कारीगरों के परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाना।
- बिहार को कुशल श्रम के श्रोत के रूप में अधिमानता दिलाने हेतु कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जाना, कुशल श्रम का देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अत्यधिक कमी का पूर्वानुमान है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उपक्रमो को उनके सीमित भूमि की आवश्यकता तथा प्रति इकाई पूंजी एवं उर्जा, अधिक श्रम शक्ति की क्षमता के कारणवश अधिमानता प्रदान किया जाना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र में कलस्टर विकास को प्रोत्साहित किया जाना।
- स्थानीय उत्पाद, स्थानीय कौशल एवं स्थानीय खपत आधारित उद्योगो पर जोर देना।

- कम उर्जा खपत एवं कम प्रदूषण वाले उद्योगों को अधिमान प्रदान करना।
 - प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता-औद्योगिक कारिडोर (ए0 के0 आई0 सी0) अन्तर्गत प्रस्तावित समेकित उत्पादन क्लस्टर अन्तर्गत वृहद प्रक्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य सरकार इकाईयों की स्थापना हेतु समुचित भूमि की तलाश में निवेशको को सहायता प्रदान करेगी जबकि उनसे यह अपेक्षा होगी कि इन निरूपित क्षेत्रों के बाहर इकाईयों अपने स्तर से भूमि प्राप्त कर सकेंगे।
 - हेरिटेज पर्यटन के विकास के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाना जिसके लिए राज्य बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करता है।
 - नई सुविधाओं के विकास और/अथवा विद्यमान सुविधाओं के सार्वजनिक निजी भागीदारी रूप में प्रबंधन में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना।
 - सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में आने वाले निवेशों में आपूर्ति के लिए आनुषंगिक इकाईयों का विकास करना।
 - निवेशको के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में पेश आ रही समस्याओं/कठिनाईयों को मात्र एक मंच से दूर करने के लिए उद्योग संबाद पोर्टल की स्थापना किया जाना।
- 2.4 नीति का दायरा।—नीति निम्न शर्तों के साथ राज्य में सभी नई इकाईयों के लिए लागू होगा :-**
- (क) किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमें उत्पादन कार्य के परिणाम स्वरूप मूल्यवर्द्धन नहीं होता है, इस नीति अन्तर्गत विचारणीय नहीं होगा। इकाईयों जो मात्र व्यापारिक कार्यकलापों में संलग्न हैं, वे इस नीति के दायरे में नहीं आयेगी।
- (ख) व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाईयां जो सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) द्वारा कभी काली सूची में डाली गई हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।
- (ग) व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाईयां जो पूर्व में कभी भी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए डिफॉल्टर घोषित किया गया है तथा इनके विरुद्ध राज्य सरकार का कोई बकाया हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- (घ) इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन उन्हीं निवेशों के लिए अनुमान्य होंगे जो राज्य में किए गए हैं।
- (ङ) किसी प्राकृतिक आपदा अथवा व्यापार के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता है।
- (च) यह नीति विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए मान्य है, परंतु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा अकेले अथवा निजी भागीदारी में किए गए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए अनुमान्य नहीं है।

3. हमारी प्राथमिकता के प्रक्षेत्र।—बिहार में कुछ प्रक्षेत्रों यथा खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, पर्यटन, आदि में प्राकृतिक फायदे हैं और राज्य सरकार, अधिकतम रोजगार सृजन सुनिश्चित करने यथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु इन फायदों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहेगी। प्राथमिक प्रक्षेत्रों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है :

- 3.1 खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र।—**बुनियादी तौर पर एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारणवश बिहार में मानव उपयोग हेतु प्रसंस्कृत किये जाने वाले कच्चे सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने वाला बृहत कृषि एवं पशु उत्पादन आधार है। इन प्राकृतिक फायदों के बावजूद, खाद्य प्रसंस्करण का स्तर काफी निम्न है और एक टिकाउ उपभोगता बाजार प्रदान करते हुए राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण स्तर को विकसित करने की भरपूर संभावना है। आगे, नगरों और ग्रामीण बिहार में बढ़ती हुई आय तथा परिवर्तित हो रहे जीवन-यापन व्यवस्था उपभोगता मांग को प्रसंस्कृत खाद्य की ओर खींच रहा है। अतएव, राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक टिकाउ अवसर प्रदान करता है और इस राज्य के औद्योगिकीकरण अभियान में अग्रणी भूमिका अदा करने की संभावना प्रदान करता है। प्रदान की जानेवाली प्रमुख उत्पाद के इन प्रक्षेत्रों में हमारी कुछ रणनीतिक फायदे इस प्रकार हैं।

प्रमुख कृषि उत्पादें	हमारी रणनीतिक फायदें
खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन	(क) विगत 5 वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2014 के दौरान राज्य में अनाजो का उत्पादन स्तर वार्षिक तौर पर 5.65 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में राज्य का अनाज उत्पादन 143.21 लाख टन था जो देश में सबसे अधिक

	<p>है।</p> <p>(ख) हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं: चावल : 82.41 लाख टन, गेहूँ : 35.70 लाख टन, मक्का : 24.78 लाख टन, दाल : 4.28 लाख टन तथा तेलहन : 1.27 लाख टन¹।</p> <p>(ग) बिहार में मक्का की उत्पादकता देश कि सभी राज्यों से अधिक है।</p>
<p>फल (आम, अमरुद, लीची तथा केला) और सब्जी आलू, बंदगोभी फूलगोभी, ओकरा)²</p>	<p>(क) सब्जियों के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान पहला है।</p> <p>(ख) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं – आलू : 63.46 लाख टन, प्याज : 12.47 लाख टन, फूलगोभी – 10.03 लाख टन, टमाटर : 10.46 लाख टन। अन्य सब्जियाँ जैसे बंदगोभी, भिंडी, गाजर और मटर का भी उत्पादन होता है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।</p> <p>(ग) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण फल हैं :- केला-15.27 लाख टन, आम- 12.72 लाख टन, अमरुद- 3.7 लाख टन एवं लिची 1.98 लाख टन।</p> <p>(घ) राज्य अपने लीची पैदावार हेतु भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विख्यात है और यहाँ पल्प, जूस, पल्प स्लैब, नेक्टार, जैम, जेली इत्यादि हेतु इकाई स्थापित करने की वृहद संभावना है।</p>
<p>मखाना</p>	<p>(क) मखाना/गोरगॉन नट राज्य का एक विशेष उपज है जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के खाद्य-पदार्थों में किया जा सकता है तथा इसका समुचित विपणन कर अच्छे दाम में बेचा जा सकता है।</p> <p>(ख) मखाना/गोरगॉन नट काफी पोषक एवं प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ है। इसकी तुलना मछली/मीट में उपलब्ध प्रोटीन से की जा सकती है। चीन में कच्चे मखाना बीज पाउडर को बच्चों के भोजन का एक अनिवार्य अंग माना जाता है।</p>
<p>पशु उत्पादो (दूध, मांस मछली, अंडे शहद)</p>	<p>(क) राज्य में कुल पशुधन जनसंख्या 329.38 लाख है और इसके काफी बढ़ने की उम्मीद है।³</p> <p>(ख) कुल पशुधन की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत दुधारु पशुओ की है जिसमें गाय 122.31 लाख, बकरी 121.53 लाख और भैंस 75.67 लाख है।</p> <p>(ग) 79.172 लाख टन प्रतिदिन की औसत उत्पादन के साथ दूध राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भोजन उत्पादों में से एक है और इसके प्रसंस्करण के बहुत बड़े अवसर हैं।</p> <p>(घ) भैंस, बकरी और मुर्गी की बड़ी आबादी राज्य में मांस प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।</p> <p>(ङ) राज्य में 1071000 हेक्टेयर अथवा 2677000 एकड़ जलक्षेत्र है। इसमें तालाब (95,000 हेक्टेयर) आक्सबो लेक (9,000 हेक्टेयर), रिजम्वायर्स (26,000 हेक्टेयर) एवं वेट लैण्ड (9.41 लाख हेक्टेयर) है। राज्य में नदियों की कुल लंबाई 3,200 कि० मी० है। राज्य की विशाल जल संपदा ताजा मछली के प्रसंस्करण की सुविधाओं/इकाईयों के लिए लाभप्रद संभावना प्रदान करती हैं। वर्ष 2014-15 में राज्य में विभिन्न जल श्रोतों से औसत मछली उत्पादन 5 लाख टन वार्षिक था।</p> <p>(च) बिहार देश में शहद के 4 सबसे बड़े उत्पादको में एक है और प्रतिवर्ष शहद का लगभग 6500 मे० टन उत्पादन करता है। शहद आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक होता जा रहा है और पौष्टिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। कम निवेश की आवश्यकता और अधिक राजस्व क्षमता की वजह से संभावित पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच इसकी पहली पसंद होने की संभावना है।</p>

¹ सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक उत्पादन के हैं।

² सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक उत्पादन के हैं।

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र।—इस नीति के तहत प्रोत्साहन राशि लेने के उद्देश्य हेतु नीचे विवरणित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्राथमिक प्रक्षेत्रों के अंतर्गत माना जायेगा।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन प्रसंस्करण	<p>(क) स्टार्च एवं मवेशी तथा/या पॉल्ट्री फीड के उत्पादन हेतु इकाई सहित, 100 टी0पी0डी0 से अधिक की स्थापित क्षमता की मक्का प्रसंस्करण की इकाईयों।</p> <p>(ख) 100 टी0पी0डी0 से अधिक की स्थापित क्षमता की अन्य अनाज प्रसंस्करण /आंटा/स्टार्च/डफ मिक्सेज, ब्रेकफास्ट फूड मैनुफैक्चरिंग इकाई।</p> <p>(ग) दाल प्रसंस्करण इकाई</p> <p>(घ) तेलहन प्रसंस्करण हेतु आधुनिक इकाई/बिहार से स्थानीय तौर पर प्राप्त किये गए कच्चे सामग्री से निष्कर्षण यानि चावल भूसी तथा वनस्पतियों यथा सोयाबीन, सैफपलावर/सनपलावर/सरसो/मूंगफली आदि। साथ ही बोविन/भेड़/बकरी/मछली/समुद्री पशुओं आदि से निष्कर्षित वसा एवं तेलों से वनस्पति ऑयल मैनुफैक्चरिंग। खाद्य तेलों, खाद्य तेल रिफाइनिंग आदि हेतु सौल्वेंट निष्कर्षण इकाई।</p> <p>नोट:— बिना किसी सारगर्भित मूल्य वर्धन शॉर्टिंग, विलनिंग एवं पैकेजिंग में शुद्ध रूप से संश्लिप्त प्रसंस्करण इकाईयों को इस संवर्ग के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।</p>
फल एवं वनस्पति (एफ0 एण्ड वी0) प्रसंस्करण	<p>(क) सभी प्रकार के फूड एण्ड बिवरेज प्रसंस्करण इकाई (आई0 क्यू0एफ0 / ब्लास्ट फ्रीजर/स्पाइरल फ्रीजर आदि का इस्तेमाल करते हुए डिहाइड्रेटेड एवं फ्रोजेन एफ एण्ड वी की मैनुफैक्चरिंग इकाईयों सहित)</p> <p>(ख) प्याज, मशरूम आदि जैसी वनस्पतियों का डिहाइड्रेशन एवं पाउडरिंग।</p> <p>(ग) लीची प्रसंस्करण की इकाई (उदाहरण के लिए लीची पल्प, जूस, पल्प स्लैब्स, जैम, जेली, बिवरेज, नेक्टार, कैन्डीज, पाउडर आदि की मैनुफैक्चरिंग हेतु इकाईयों)</p> <p>(घ) स्थानीय प्रकार के आम का पल्प, जूस, पल्प स्लैब्स, जैम जेली, बिवरेज, नेक्टार, कैन्डीज, पाउडर आदि में प्रसंस्करण की इकाई (अन्य राज्यों या देशों से आयात की गई आम गुठों का इस्तेमाल करने वाली इकाईयों प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।)</p> <p>(ड.) केला प्रसंस्करण की इकाई (उदाहरण के लिए केला चिप्स, पल्प, पाउडर, शिशु खाद्य, जैम जेली, केला फूल सब्जियाँ, केला तना की सब्जियाँ एवं अचार आदि)</p> <p>(च) मखाना प्रसंस्करण की इकाई (मखाना पॉप्स, जायकेदार तथा/या भुना गया मखाना स्नैक्स, आर0टी0सी0 खीर, बेबी फूड आदि बनाने हेतु इकाई)</p>
दूध प्रसंस्करण तथा डेयरी उत्पाद मैनुफैक्चरिंग	<p>(क) 50 हजार लीटर प्रति दिन से अधिक की स्थापित क्षमता वाली दूध प्रसंस्करण इकाई।</p> <p>(ख) पास्चराइज्ड दूध, दूध पाउडर (एसएमपी0), आईसक्रीम पाउडर, कंडेस्ड दूध, शिशु खाद्य, दूध क्रीम, मक्खन, मक्खन दूध, लस्सी, योगुर्ट, चीज, घी, खोआ, आईसक्रीम, कुल्फी, फ्लेवर्ड दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों की मैनुफैक्चरिंग हेतु इकाईयों।</p> <p>(ग) अन्य राज्यों या देशों से आयात की गई दूध पाउडर से उत्पादों का मैनुफैक्चरिंग करने वाली इकाईयों प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। केवल राज्य के भीतर दूसरे इकाई द्वारा विनिर्मित दूध पाउडर से अथवा उनलोगों के द्वारा प्राप्त दूध से विनिर्मित उत्पादें इस संवर्ग के अंतर्गत रियायत हेतु पात्र हैं।</p> <p>नोट:— प्राथमिकता प्रक्षेत्र में विचार हेतु इकाईयों को इन क्षेत्रों में दूध अधिग्रहण नहीं करना होगा जहाँ कॉम्पेड द्वारा दुग्ध सहकारी संचालित है।</p>
मधु प्रसंस्करण	प्राकृतिक मधु प्रसंस्करण इकाई
मांस, पॉल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण	(क) मांस, पॉल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयों (उदाहरण के लिए फ्रेश, चिल्ड एवं फ्रोजेन मछली, फिश फिलेट्स एण्ड पीसेज, फिश क्यूर्ड अथवा स्मोकड, मानव उपयोग हेतु योग्य फिश मील, भेड़ या बकरी जैसे घरेलु दूधारु

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
	पशुओं का फ्रेश एवं चिल्ड मांस, पॉल्ट्री मीट का मांस एवं खाने योग्य पोल्ट्री मीट के ओफल, सूखे अंडे इत्यादि।) (ख) आधुनिक बूचड़खाना तथा वध-स्थल
मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण	(क) मसालों के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाई (उदाहरण के लिए मसालों का एक्सट्रैक्ट्स एसेंस एवं कंसेंट्रेट्स, पाउडर तथा पेस्ट मैनुफैक्चरिंग आदि) (ख) फूड पलेवर, कलर्स, ओलियोरेजिन्स की निष्कर्षण इकाई (ग) जड़ी बूटी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य और कल्याण के भोजन की खुराक
चाय प्रसंस्करण	चाय प्रसंस्करण की आधुनिक इकाईयाँ
अन्य खाने योग्य तैयार व्यंजन	(क) बिस्किट्स/कूकीज आदि के निर्माण करने हेतु आधुनिक इकाई। (ख) आधुनिक बेकरी इकाई (यथा ब्रेड, पैस्ट्रीज एवं केक्स निर्माण) (ग) आईसक्रीम उत्पादन हेतु आधुनिक इकाई (घ) चॉकलेट एवं गैर-चॉकलेट आधारित कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए आधुनिक इकाई। (ङ) फ्रोजेन या नन-फ्रोजेन तथा खाने हेतु तैयार (आर0टी0इ0) पैक किये गए मिल्स एण्ड स्नैक्स, पकाने हेतु तैयार (आर0टी0सी0) खाद्य, पाउडर्ड इनर्जी कन्सेंट्रेट, इंस्टैंट ड्रिंक कन्सेंट्रेट इत्यादि के उत्पादन करने हेतु इकाई।
ईख प्रसंस्करण	(क) चीनी उत्पादन। (ख) इथनॉल उत्पादन।
वेयरहाउसिंग	(क) फल पकाने वाला कक्ष। (ख) कन्ट्रोल्ड एटमोस्फियर (सी0 ए0)/मोडिफाइड एटमोस्फियर (एम0 ए0) चैम्बर्स, कोल्ड रूम्स/डीप फ्रीजर्स /प्रि-कूलिंग चैम्बर्स (ग) बहुआयामी शीत भंडारण सुविधा/आधारभूत संरचना के साथ-साथ प्रि-कूलिंग चैम्बर्स, राइपनिंग चैम्बर्स, सी0ए0/एम0ए0 चैम्बर्स, कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, बल्क चिलर्स इत्यादि, साथ ही शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक व्यवस्था। (घ) आधुनिक अनाज साइलो/भंडारण।
सामान्य/व्यवसाय विकास सेवाएं	(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र से संबंधित शोध एवं विकास सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/जाँच प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र/उद्भवन केन्द्र/कौशल विकास केन्द्र, इत्यादि। (ख) खाद्य संयंत्र निर्माण (ग) प्रदीपन इकाई

नोट :-

- इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।
- दूसरे राज्यों या देशों से आयातित खाद्य सामग्रियों को पैकेजिंग/रि-पैकेजिंग के उद्देश्य से स्थापित इकाइयों/उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत विचार नहीं किया जायेगा।
- अगर एक इकाई/उद्यम एककृत तरीके से कैपटीव उपयोग के उद्देश्य से दो या अधिक तरह की सुविधायें स्थापित करती है, तो इन सुविधाओं को एक एकल परियोजना माना जायेगा और सुविधाओं में हुए संयुक्त व्यय को अनुदान गणना के लिए विचार किया जायेगा। प्राथमिकता अथवा अप्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत इकाइयों/ उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य/मूल सुविधा के प्रकृति के अनुसार होगा। यथा- कोर सुविधा।

4. अगर कोई इकाई क्षमता विस्तार/सुविधा परिवर्धन इत्यादि के माध्यम से गैर प्राथमिकता क्षेत्र से प्राथमिकता क्षेत्र में विस्थापित होती है तो यह प्राथमिकता क्षेत्र के अनुसार प्रोत्साहन का उपभोग प्राथमिकता वाले भाग के हिस्से तक करेगी।
5. मनुष्यों/जानवरों के उपयोग योग्य खाद्य पदार्थ की विनिर्माण करने वाली इकाइयों जिसमें मुख्य घटक के रूप में कोई अनाज,फल एवं सब्जी अथवा कोई प्रसंस्कृत/संरक्षित वस्तु (पल्प सारकृत द्रव्य इत्यादि) नहीं हो जो अनाज/फल एवं सब्जी से बने हों उन्हें गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में विचार किया जायेगा।
6. मुख्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधा के उप उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित होने वाले इकाइयों को अनुदान के लिए गैर प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र अन्तर्गत माना जायेगा अगर उप उत्पाद के प्रसंस्करण से बने अन्तिम उत्पाद मनुष्यों/जानवरों के उपभोग हेतु योग्य खाद्य पदार्थ न हो। अगर अन्तिम उत्पाद मनुष्यों/जानवरों के उपभोज्य योग्य हो तो उसे उपर्युक्त सूची के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

3.2 पर्यटन प्रक्षेत्र।—अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों को देखते हुए बिहार में पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएँ हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार की बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति इसके प्राचीन और वर्तमान जीवित सभ्यता, जो कि संसार के दो महान धर्मों बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म दिया है। बिहार हिन्दु, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम की धार्मिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। बिहार में एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ सम्पन्न विशाल शक्तिशाली मगध साम्राज्य की शक्ति का एक आधार थी। यह नालन्दा और विक्रमशीला, प्राचीन विश्वविद्यालयों की भूमि है। जहाँ से संसार के विभिन्न देशों से विद्यार्थियों के माध्यम से सुदूर और विस्तृत क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ है। इन दो प्राचीन विश्वविद्यालयों के अवशेष, प्राचीन वस्तुएँ और कलाकृतियाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य भर में अलग-अलग परिदृश्य और संस्कृति विरासत, प्रकृति वन्य जीवन, कल्याण एवं अन्य अद्वितीय उत्पादों की अपनी ताकत भर में विभिन्न उत्पाद के पेशकश की धनी/चित्रय वनिका है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा की गई मुख्य उत्पादों की पेशकश निम्नवत है—

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाम
अध्यात्मिकता	<p>बिहार में पर्यटन के लिए पारंपरिक रूप से अध्यात्मिक रुचि के स्थानों पर जाकर यात्रियों के भ्रमण के अच्छे आसार हैं। इस पहलु पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कुछ चिन्हित पर्यटन सर्किट निम्न प्रकार हैं—</p> <p>(a) बुद्ध सर्किट:— बोधगया (गया), राजगीर (नालन्दा), नालन्दा, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़ (पूर्वी चम्पारण), लौरिया अरेराज (पूर्वी चम्पारण), केशरिया (पूर्वी चम्पारण), विक्रमशीला (भागलपुर), जहानाबाद</p> <p>(b) सूफी सर्किट:— मनेरशरीफ (पटना), खानकाह मुजीविया (पटना), मित्तन घाट (पटना), हाजीपुर करबला (वैशाली), हसनपुर (नालन्दा), बीबी कमाल साहिब (जहानाबाद), बड़ी दरगाह (नालन्दा), छोटी दरगाह (नालन्दा)</p> <p>(c) जैन सर्किट:— वैशाली, राजगीर (नालन्दा), पावापुरी (नालन्दा), नाथनगर (भागलपुर), मन्दार हिल (बाँका), चम्पानगर (भागलपुर), कुन्दलग्राम (नालन्दा), समोसारण (नालन्दा) एवं लछौर (जमुई)</p> <p>(d) रामायण सर्किट:— बाल्मिकीनगर (प0 चम्पारण), प्रेतशीला (गया), अहिल्या स्थान (दरभंगा), सीतामढ़ी, काको (जहानाबाद), सीताकुण्ड (सीतामढ़ी), सिंहेश्वर (सहरसा), रामशीला (गया), बक्सर, गिद्धेश्वर (जमुई),</p> <p>(e) शक्ति सर्किट:— मुण्डेश्वरी स्थान (कैमूर), चण्डी स्थान (मुंगेर), उग्रतारा स्थान (महिषी, सहरसा), आमि (सारण), थावे (गोपालगंज), ताराचण्डी स्थान (रोहतास), बखोरापुर (भोजपुर), श्यामाकली (दरभंगा), भगवती स्थान (नयानगर, मधेपुरा), बड़ी पटनदेवी (पटना), छोटी पटनदेवी (पटना), मतस्यगंधा रक्तकाली टेम्पल (सहरसा), उच्चैठ (मधुबनी)</p> <p>(f) सिख सर्किट:— पटना साहिब (पटना सिटी, पटना), बाललीला साहब (पटना), गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा (गायधाट, पटना), गुरुनानक कुण्ड (राजगीर, नालंदा), आरा, कटिहार, गया एवं सासाराम, भागलपुर, गुरु का बाग (पटना सिटी, पटना), गुरुद्वारा पक्की संगत (मुंगेर), गुरुद्वारा हंदी साहेब (दानापुर, पटना)</p> <p>(g) गाँधी सर्किट:— मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भितिहरवा आश्रम (पश्चिमी चम्पारण), वृन्दावन (पश्चिमी चम्पारण), सदाकत आश्रम (पटना), गाँधी संग्रहालय (पटना)</p>

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाभ
	<p>(h) शिव सर्किट— गुप्ताधाम (कैमूर), बैजूधाम (गया), कोटेश्वर धाम (गया), सिंघेश्वर धाम (मधेपुरा), कुशेश्वर स्थान (दरभंगा), सिंहेश्वर स्थान (जहानाबाद), अजगैबीनाथ (सुल्तानगंज, भागलपुर), अशोक धाम (लखीसराय), गरीबनाथ (मुजफ्फरपुर), महेन्द्रनाथ (सारण), ब्रह्मेश्वरनाथ (बक्सर)</p> <p>(i) मण्डार एवं अंग सर्किट— मुंगेर, भागलपुर एवं बाँका</p> <p>(j) कांवरिया रूट— सुल्तानगंज (भागलपुर) से बाँका</p>
संस्कृति और विरासत	<ul style="list-style-type: none"> • बिहार में विस्तृत संरक्षित स्मारकों की सरणी है। विश्व विरासत स्थल और अनेक अन्य स्थल जैसे नालन्दा के भग्नावशेष एवं विक्रमशीला (संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालय) जो विश्व विरासत स्थलों की क्षमता रखते हैं। • संरचनाओं की मौलिकता को बनाये रखते हुए ऐतिहासिक इमारतों को परिवर्तित इमारतों के साथ विशेष विरासत जोन के रूप में विकसित किया जा सकता है। • हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्किजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया और दूसरे राज्य सरकारों के समन्वय से संग्रहालयों का उन्नयन और विकास, नव उद्घाटित बिहार संग्रहालय एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। • बिहार के हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्य से शिल्पग्राम (क्राफ्ट भिलेज) और हस्तशिल्प बाजार पर्यटक स्थलों के नजदीक प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ग्रामीण/गाँव	<p>ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कला तथा शिल्प के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। उदाहरण स्वरूप टेहटा (जहानाबाद), नेपुरा (नालंदा), रंती एवं जितवरपुर (मधुबनी), पत्थरकट्टी (गया), नाथनगर (भागलपुर) इत्यादि कार्यरत गाँव ग्रामीण पर्यटन के विकास के रूप में लक्षित किया जा सकता है।</p>
कल्याण	<p>योगा और राजगीर तथा मुँगेर के सल्फर जल गर्म जल के झरनों को एक्वाथेरापी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह बिहार का अधिकतम अनोखा पर्यटन संभावना हो सकता है। यह बिहार की सबसे अनोखी पर्यटन मानसिक एवं आध्यात्मिक शारीरिक हर आयाम से समग्र चिकित्सा और व्यक्ति के कायाकल्प की पेशकश उत्पाद हो सकती है।</p>
पारिस्थितिकी और वन्य जीवन	<p>संभावना योग्य पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य को एकीकृत कर परिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चिन्हित पर्यटन स्थलों में से कुछ हैं – राजगीर (नालंदा), भीमबांध अभ्यारण्य (मुंगेर), कैमूर अभ्यारण्य (कैमूर), गौतमबुद्ध अभ्यारण्य (गया), नकटीधाम (जमुई), गोगाविल अभ्यारण्य (भागलपुर), कांवर झील (बेगुसराय), घोड़ाकटोरा झील (नालंदा), काकोलत झरना (नवादा), तेलहार झरना (रोहतास), गैन्टिक डाल्फिन अभ्यारण्य (भागलपुर) एवं वाल्मिकी नेशनल पार्क (पश्चिमी चम्पारण)</p>
गंगा आधारित	<ul style="list-style-type: none"> • पटना, भागलपुर इत्यादि के किनारे ऐतिहासिक स्थलों को जल मार्ग के सहारे विकसित करने के लिए गंगा एक अद्वितीय पर्यटक उत्पाद हो सकता है। • डोल्फिन को देखना राज्य के लिए एक दूसरा अद्वितीय पर्यटक उत्पाद है जिसे सुदृढ़ किया जा सकता है।
साहसिक	<p>विभिन्न प्रकार के जलीय खेल जैसे रीवर राफ्टिंग, पारासेलिंग इत्यादि को अधिक आर्थिक अवसर के रूप में विकसित किया जा सकता है।</p>
मेला एवं महोत्सव	<p>बिहार के पास अद्वितीय घटनाओं— मेला और महोत्सव हैं, जैसे सोनपुर मेला, छठ पर्व, सौराठ सभा, राजगीर महोत्सव और बौद्ध महोत्सव समुचित सुविधा के विकास के उपरांत घरेलू के साथ-साथ अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।</p>
सिनेमा	<p>बिहार के पर्यटन स्थलों पर फिल्म सूटिंग को सिंगल विन्डो क्लियरेंस के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन के साथ प्रासंगिक सरकारी अधिसूचना के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए।</p>
व्यंजन आधारित	<p>* राज्य के अमीर पाक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बिहार के व्यंजन पाक को बढ़ावा दिया जा सकता है।</p>

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाभ
	* फूड फेस्टिवल के आयोजन के माध्यम से राज्य की अद्वितीय व्यंजन जैसे- खाजा, लाई, बेलग्रामी, तिलकुट, लिट्टी-चोखा, सत्तु और मखाना के उत्पाद आर्थिक अवसर उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं।

वर्तमान में ये चिन्हित उत्पाद एवं सर्किट विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना एवं सेवा सम्बन्धित निवेश केलिए अछूते पड़े हैं। इन चिन्हित सर्किट के अतिरिक्त राज्य में बहुत से भौगोलिक क्षेत्र जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से भविष्य में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग के विभिन्न प्रक्षेत्रों में वर्तमान एवं संभावित निवेश संभावना तथा भविष्य में अवसर एवं बहुत संख्या में रोजगार के अवसर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने निवेश प्रोत्साहन नीति में इस क्षेत्र के विकास एवं बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उसे थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में विचार किया गया है। इसलिए नीति में इस प्रक्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं।

पर्यटन प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र।—पर्यटन प्रक्षेत्र के निवेश प्रोत्साहन हेतु प्राथमिकता क्षेत्र निम्नवत है—

क्षेत्र	निवेश के अवसर
परिवहन	* पर्यटन स्थल पर टैक्सी परिचालन। * कैब परिचालन/पर्यटन स्थल पर रेडियो टैक्सी * टूरिस्ट सर्किट पर लकजरी कार एवं कोच बस का परिचालन * टूरिस्ट सर्किट पर एयर टैक्सी एवं हेलीकॉप्टर सेवा * विशेष पर्यटन ट्रेन, नौका एवं स्टीमर इत्यादि।
आवासन	* होटल, मोटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, होम स्टे इत्यादि (चिन्हित पर्यटन स्थल से 10. कि०मी० क्षेत्र के अन्तर्गत)। * सराय/ एकत्रित होने के लिए सुविधा/टेन्टेड आवासन हेरिटेज होम्स इत्यादि
परिश्रमण तथा यात्रा	पर्यटक स्थल पर ट्रेमल एजेन्सीज, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट टैक्सी इत्यादि।
एम०आई०सी०ई० सुविधा	पर्यटक स्थल पर मिटिंग हॉल, सभा स्थल, इभेन्ट आयोजक इत्यादि।
मानव संसाधन संस्थान	होटल प्रबन्धन संस्थान, फूड काफ्ट संस्थान, ट्रेमल एण्ड ट्रेड संस्थान, मानव प्रशिक्षण संस्थान, टूरिस्ट गाईड, प्रशिक्षण केन्द्र, पर्यटन प्रक्षेत्र के शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रबन्धन संस्थान।
यादगार वस्तुओं की दुकान	पर्यटक स्थल पर हस्तशिल्प दुकान, यादगार वस्तुओं की दुकान, संजातिय बूटिक, परम्परागत आभूषण दुकान इत्यादि।
राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य राजमार्गों के किनारे सुविधाएँ	पर्यटक स्थल पर सड़क किनारे सामान्य सुविधा केन्द्र, रेस्तराँ, जलपान केन्द्र, ढावा, पे एण्ड यूज शौचालय, उपयोगी वस्त्रों की दुकाने, वाहन पड़ाव स्थल और राज्य में निर्मित हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद की दुकानें।
कल्याण केन्द्र	पर्यटक स्थल पर आयुर्वेद केन्द्र, कल्याण स्पा, उपचार केन्द्र, योगा विश्वविद्यालय इत्यादि।
नदी आकर्षण	कूज, फ्लोटिंग रेस्तराँ, फ्लोटिंग कॉटेज, जलीय क्रीडा, शीभर राफ्टिंग, पैरा सेलिंग, मनोरंजन की सुविधा जैसे मछली पकड़ना/डोल्फिन दर्शन इत्यादि।
मनोरंजन	पर्यटन स्थल पर मनो विनोद पार्क, वाटर पार्क, प्रकरण पार्क, शिल्पग्राम, रज्जू मार्ग, विज्ञान केन्द्र, संग्रहालय, तारामंडल इत्यादि।
सिनेमा	फिल्मसिटी

नोट — 1. इस नीति अन्तर्गत पर्यटक स्थल से तात्पर्य है वैसे स्थान (जिला या प्रखण्ड या गाँव) जैसा कि उपर्युक्त सारणी में उल्लेखित है, जो विभिन्न "पर्यटन खण्ड" एवं "हमारे सामरिक लाभ" की सूची में हों के राजधानी क्षेत्र में हो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के लाभ से अलग रखा जायेगा।

2. इकाइयों / उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची को उपयुक्त ढंग से संशोधित कर सकती है।

3.3 लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र।—बिहार की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यद्यपि कृषि की उच्च लागत और फसलो की उत्पादकता यानि कृषि लागत एवं उत्पादन के बीच के सम्बन्ध देश के एवं अन्य राज्यों/विश्व औसत की तुलना में एक सतत समस्या रही है। सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने, साथ-साथ उच्च उपज देने वाली बीज का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरक एवं खेती के बेहतर तकनीक का उपयोग, आधुनिक कृषि संयंत्र कृषि उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार सर्वोत्तम स्तर के यांत्रिकीकरण के लिए बिहार में कम लागत पर कृषि का माहौल बनाना अनिवार्य है।

हाल में बिहार के खेतों में आधुनिक कृषि औजार का उपयोग काफी बढ़ा है। बिहार के कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकीकरण एक अभिन्न हिस्सा है। राज्य सरकार पावर टीलर्स, ट्रैक्टर, स्पेयर्स, ओसावन मशीन, पावर वीडर, पावर थ्रेसर पर केन्द्र संपोषित योजनान्तर्गत प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। जीरो टीलेज यंत्रों जो छोटे और सीमांत किसानों के भूमि जोत लिए अधिक उपयुक्त है, उसे ध्यान दिया जाना है। आसानी से प्रोत्साहन उपलब्ध होना, किसानों का, विकासात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक उपकरणों का उपयोग राज्य में सामान्य सा हो रहा है। विद्युतीकरण में हुई वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत आधारित कृषि यंत्र, पम्प के उपयोग में वृद्धि हुई है। राज्य में कृषि यंत्र का बाजार उच्च विकास को दर्शाता है जिसमें भविष्य में भी अधिक वृद्धि की संभावना है। सदा बढ़ते हुए घरेलू उपयोग बाजार और राज्य में इस क्षेत्र में अबतक नगण्य निवेश को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बिहार सरकार द्वारा कृषि से जुड़े लघु संयंत्र विनिर्माण को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है।

लघु संयंत्र विनिर्माण क्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र।—लघु संयंत्र विनिर्माण के मूल्य संवर्धन हेतु निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र निम्नवत है:—

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
भूमि/बीज शैया की तैयारी	ट्रैक्टर, पावर टीलर्स, लेवलर्स—हल, हैरो, रोटेवेटर, कल्टीभेटर, रीजर, डोजर, स्क्वेपर्स।
बीजारोपण/पौधारोपण/ बुआई	ड्रील, सीडर, प्लान्टर, डीबलर, ट्रांस प्लांटर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील्स, जीरो टीलेज मशीन।
स्प्रेयिंग और डस्टिंग उपकरण	वीडर्स, कोनोवीडर्स, टीलर्स, स्प्रेयर्स, डस्टर्स, मिस्ट ब्लोअर्स।
फसल कटाई	हार्वेस्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, पाटेटो डीगर्स, रीपर, सेलर सिक्ल/स्ट्रौरीपर्स
पोस्ट हार्वैष्ट उपकरण	बीज निष्कर्षक/डीहस्कर/हॉलर/डी हॉलर, क्लीनर, ग्रेडर, ड्रायर वीनोअर्स, ट्रेलर्स, ग्रेन बीन्स।
सिंचाई	डीजल पम्प, विद्युत पम्पसेट, सोलर पम्पसेट, स्प्रिंकलर्स, ड्रीप इरीगेशन, उपकरण, एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाईप इत्यादि।
लघु संयंत्र और पार्ट पूर्ण	ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल पार्ट पूर्णों की अनुषंगी इकाई, डीजल एवं विद्युत मोटर संयंत्रों की अनुषंगी इकाई, साईकिल निर्माण।
सामान्य /व्यवसाय विकास सेवाएं	अनुसंधान एवं विकास सुविधा/कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला/जाँच प्रयोगशाला, डीजाइन स्टूडियो/प्रोटोटाइप फैसिलिटी, प्रशिक्षण केन्द्र/ इनक्यूबेशन सेन्टर/स्कील डेवलॉपमेंट सेन्टर

नोट:—

- इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।
- पार्ट/पूर्णा निर्माण करने वाली इकाई जिसका सीधा उपयोग अन्य लघु संयंत्र बनाने वाली इकाइयों में सीधे तौर पर होती है वैसी इकाइयों को भी प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किया जायेगा।

3.4 सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र।—ग्लोबली सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग हार्डवेयर क्षेत्र सहित संसार में सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली उद्योग है। इसे वर्ष 2020 तक लगभग 2.4 ट्रिलियन यूएसडी तक पहुँचने की उम्मीद है। केवल भारतीय बाजारों में वर्ष 2020 तक इसकी माँग 400 विलियन यूएसडी से अधिक पहुँचने की सम्भावना है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का महत्व केवल अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी उद्योगों का अभिन्न अंग हो गया है। यह रोजमर्रा के जीवन में सभी क्षेत्रों में सार्थक पैठ रखता है। अतः यह स्थापित हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिक/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें के क्षेत्र में वृद्धि कृषि, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, ऊर्जा, दूरसंचार, ग्रामीण विकास/पर्यटन, टेक्सटाइल क्षेत्र में भी वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रक्षेत्र अभी भी उपर उठने की स्थिति में है और बांछित दिशा में बढ़ने की स्थिति में है। यह अनेक उद्यमों तथा स्टार्ट अप के लिए असीम संभावना रखता है। राज्य में शिक्षित युवा, सस्ते कामगार की उपलब्धता इस क्षेत्र में निवेश के लिए स्पष्ट रूप से लाभप्रद है। राज्य सरकार द्वारा भी बिहटा (पटना) तथा राजगीर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु अधिसूचित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र।—राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में चिन्हित निवेश के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत है:—

क्षेत्र	निवेश के अवसर
सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें	<ul style="list-style-type: none"> * सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, सॉफ्टवेयर तथा सेवायें। * सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर तथा सेवाएँ। * सूचना प्रौद्योगिकी, आधारित सेवायें, बैंक ऑफिस, ऑपरेशन/ बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग(बीपीओओ)/ नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग(केओपीओओ), कॉल सेन्टर, डिजिटल कंटेन्ट डेवलपमेंट एनीमेशन इत्यादि।
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण	<ul style="list-style-type: none"> * कम्प्यूटर्स * कम्प्यूटर बाह्य तथा अन्य ऑफिस उपकरण * सर्वर और स्टोरेज डिवाइस * नेट वर्किंग * ऑटोमोटीव इलेक्ट्रॉनिक्स * मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स * इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स
अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	<ul style="list-style-type: none"> * मोबाईल, डीटीएच टीलीवीजन, रेडियो एवं कंजूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
विद्युत उपकरण	<ul style="list-style-type: none"> * मोटर्स, पम्प, फैन उपभोक्ता वस्तुएँ यूपीएस इत्यादि

नोट:— इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.5 टेक्सटाइल प्रक्षेत्र।—टेक्सटाइल प्रक्षेत्र जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान, विनिर्माण आउट-पुट, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय के सहारे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करता है। इस प्रक्षेत्र का योगदान औद्योगिक उत्पादन में 14 प्रतिशत भारतीय जीडीपी में 4 प्रतिशत तथा देश के निर्यात आय में 13 प्रतिशत है। टेक्सटाइल प्रक्षेत्र भारत वर्ष में रोजगार सृजन का सबसे बड़े श्रोतों में से एक है। यह सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

बिहार में घरेलू वस्त्र उद्योग और दूसरे मूल्य संवर्धन क्रिया-कलाप के लिए प्रचुर सम्भावनायें हैं। बिहार में वस्त्र उद्योग में सिल्क एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। सिल्क उत्पादन में बिहार प्रसिद्ध रहा है।

बिहार का भागलपुर जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केन्द्र रहा है। भागलपुर का तसर सिल्क बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है, जिसमें लाभकारी मूल्य प्रदायता की सम्भावना है। वर्ष 2014-15 में बिहार में लगभग 60 टन सिल्क का उत्पादन हुआ है। राज्य में जूट दूसरा फाइबर उत्पाद है। वर्ष 2014-15 में बिहार में लगभग 1420 हजार टन जूट का उत्पादन हुआ है। निबन्धित एसपीओभी सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि० के माध्यम से रू० 42.36 करोड़ की निवेश से मरंगा पूर्णिया में एक जूट पार्क की स्थापना की जा रही है।

पी0पी0पी0 मोड में राज्य सरकार द्वारा 44.30 एकड़ भूमि अंशदान के रूप में तथा रू0 2.00 (दो) करोड़ अनुदान स्वरूप दिया गया है। इस जूट पार्क में वर्तमान में दो इकाई सर्वश्री तिरुपति कोमोडिटीज प्रा0लि0 तथा सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है और कार्यरत है। वे जूट यार्न जूट ट्वाइन, जूट के कपड़े और अन्य जूट उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं। बिहार में 14000 पावरलूम हैं, जो मुख्य रूप से भागलपुर, गया और बांका जिले में अवस्थित हैं। उनके मुख्य उत्पाद सूती चादर, बेड सीट, फर्नीचिंग क्लोथ इत्यादि हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केन्द्र नाथनगर, भागलपुर में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 120 पावर लूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वस्त्र उद्योग एक उच्च श्रम घनिष्ठ उद्योग है। बिहार में करीब एक लाख बुनकर हैं जिनकी जीविका का साधन धागों एवं वस्त्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। बुनकर समुदाय को पाया जाना वस्त्र उद्योग के लिए कुशल और अर्द्धकुशल कारीगर की उपलब्धता के रूप में एक महत्वपूर्ण सम्पदा है। सतत जूड़े बुनकर समुदाय के अतिरिक्त बड़ी संख्या में युवा भी (विशेषकर युवतियाँ) इस प्रकार की उत्पादक रोजगार के अवसर के प्रतीक्षा में उपलब्ध हैं। जैसा कि वस्त्र निर्माण उद्योग उन्हें सिलाई, कटाई और अन्य दूसरे तरह के टेलरिंग कार्य का अवसर प्रदान करते हैं।

टेक्सटाइल प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र।—राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण निम्नवत किया गया है—

क्षेत्र	निवेश के अवसर
रेशा उत्पादन/स्पिनिंग/बुनाई/निटिंग/प्रसंस्करण	(a) सूती/जूट/सिल्क/केला एवं अन्य प्राकृतिक रेशा उत्पादन (b) मानव निर्मित धागों एवं फिलामेंट का उत्पादन (c) यार्न स्पिनिंग (d) पावरलूम एवं बुनाई (e) यार्न एवं कपड़ा प्रसंस्करण
पोशाक एवं घरेलू टेक्सटाइल का उत्पादन	(a) बुने हुए पोशाक का निर्माण (b) होजियरी आइटम का निर्माण (c) साड़ी (d) दरी एवं अन्य घरेलू टेक्सटाइल
टेकनीकल टेक्सटाइल का निर्माण	निम्नांकित कोटि में से कोई आइटम का निर्माण (a) एग्रोटेक(कृषि, उद्यान एवं वानिकी इत्यादि) (b) बिल्डटेक (भवन एवं निर्माण इत्यादि) (c) क्लोथटेक(जूते एवं वस्त्र के तकनीकी वस्तुएँ इत्यादि) (d) जियोटेक(जियो टेक्सटाइल एवं सिविल इन्जीनियरिंग इत्यादि) (e) होमटेक(कम्पोनेन्ट ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाइल तथा पलोर कोभरिंग इत्यादि) (f) इन्डटेक(फिल्ट्रेशन, विलनिंग तथा अन्य औद्योगिक उपयोग इत्यादि) (g) मेडीटेक(हाइजिन तथा मेडिकल इत्यादि) (h) मोबाईलटेक(आटोमोबाईल, सिपिंग, रेलवे तथा एरो स्पेस इत्यादि) (i) औयकोटेक(वातावरण सुरक्षा इत्यादि) (j) पैकटेक(पैकेजिंग इत्यादि) (k) प्रोटेक(व्यक्तिगत तथा सम्पति सुरक्षा इत्यादि) (l) स्पोर्टटेक(स्पोर्ट एण्ड लीजर इत्यादि)
पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ हस्तकरघा तथा खादी टेक्सटाइल प्रोडक्ट	हस्तकरघा एवं खादी के उत्पादों हेतु पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा

नोट:— इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.6 प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र।—प्लास्टिक एवं रबर एक बहु उपयोगी उत्पाद है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के दूसरे उत्पाद के पैकेजिंग, हॉस्पीटलों में जीवन रक्षक उपकरणों के पैकेजिंग में किया जाता है। त्वरित वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा बढ़ते हुए उपभोक्ता के कारण अत्यधिक बदलाव आया है तथा घरेलू तौर पर प्लास्टिक उद्योग को बढ़ने के लिए प्रचुर अवसर मिला है। बिहार की अधिकांश आबादी कृषि कार्य में लगी है। यद्यपि भूमि काफी उपजाऊ है, फिर भी किसान अत्यधिक रूप से मानसून पर निर्भर रहने के कारण कम उत्पादकता और लागत पर कम आय की समस्या से ग्रसित रहते हैं। प्लास्टिक उद्योग उनके लिए उत्पादकता में सुधार तथा मानसून

पर निर्भरता को कम करने का उपाय दिया है। विद्युत आपूर्ति में बढ़ोतरी से विद्युत पम्प तथा सिंचाई प्रणाली का उपयोग बढ़ा है। इन विद्युत जल पम्पों के लिए संवितरण पाइप के कारण प्लास्टिक पाइप का मांगबढ़ा है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक उद्योग से बहुत से लाभ जैसे उत्पादकता में वृद्धि, पानी की हानि में कमी, मिट्टी के कम संसर्ग के कारण साफ सुथरे उत्पाद मिले हैं। औद्योगिक आकलन के अनुसार 35-40% भारतमें उत्पादित खाद्य उत्पाद आधारभूत संरचना में कमी तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में कमी के कारण बर्बाद होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में होता है जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, जीवन काल में सुरक्षा होती है। यह प्रक्षेत्र प्लास्टिक की मांग में वृद्धि के कारण अग्रणी वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक घरों को जल आपूर्ति से जोड़ने से सम्बन्धी राज्य सरकार के कार्यक्रम में जलापूर्ति के वितरण हेतु प्लास्टिक पाइप की आवश्यकता होगी। इस प्रकार राज्य में प्लास्टिक एवं रबर उद्योग के विकास की प्रचुर संभावना है।

प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्र।—राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में निवेश हेतु प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत चिन्हित किये गये हैं:-

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सिंचाई हेतु उत्पाद	आई0एस0आई0 मानक के पी0भी0सी0 पाइप का निर्माण, निकास पाइप, ड्रीपर्स इमीटर्स, भाल्व, फीटिंग नोजल, यूभी फिल्म, पौधों की सुरक्षा हेतु जाल, क्रेट्स, नली इत्यादि
पैकेजिंग तथा खाद्य पदार्थ के भण्डारण हेतु उत्पाद	पैकेजिंग/खाद्य पदार्थ के लिए टेट्रा पैक, कन्टेनर्स, बैग इत्यादि
जलआपूर्ति हेतु उत्पाद	आई0एस0आई0 मानक पी0भी0सी0/सी0पी0भी0सी0 पाइप निर्माण
विद्युत फीटिंग	पी0भी0सी0 पाइप एवं इलेक्ट्रिकल फीटिंग
ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स	ऑटोमोबाइल के प्लास्टिक के पार्ट पूर्ण
चिकित्सा आपूर्ति	डिसपोजेबुल सिरिंज, ग्लोब्स ब्लड संग्रहण हेतु पाउच कैथेटर/पाइप इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग।
भवन निर्माण	भवन निर्माण के लिए प्लास्टिक एवं रबर के सामान।
स्पोर्ट्स एवं अवकाश	स्पोर्ट्स एवं अवकाश के लिए रबर एवं प्लास्टिक विनिर्माण
प्लास्टिक टेस्टिंग	प्लास्टिक टेस्टिंग प्रयोगशाला आइ.एस.ओ./आइ.इ.सी. 17025 मानक द्वारा प्रमाणित।

नोट— इकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.7 अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र।—बिहार जिसकी विद्युत प्रक्षेत्र में शिखर घाटा 669 मेगावाट है, जो अब तक मुख्य रूप से केन्द्रीय जेनेरेशन स्टेशनों पर निर्भर है। वर्तमान में राज्य मुख्यतः विद्युत जेनेरेशन के लिए परम्परागत ऊर्जा श्रोत पर निर्भर है। विद्युत की कमी जो भविष्य के विकास/औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 203 किलोवाट आवर है जो राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है और भविष्य में मांग और भी बढ़ेगी। राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास को देखते हुए विद्युत के महत्व को महसूस करती है और इस खाई को कम करने के लिए बड़े पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने हेतु कदम उठाये गये हैं, जो मुख्य रूप से परम्परागत श्रोत पर निर्भर है। अभी वे स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। ये बड़े पावर प्रोजेक्ट को चालू होने में लम्बा सगर्भता समय है, जबकि मांग लगातार बढ़ेगा जिससे राज्य में आवश्यकता पूर्ति हेतु अनोखा अवसर नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमापीय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रदान करेगा। बिहार में ग्रामीण ऊर्जा की संभावना 12.559 गीगावाट (सोलर 11.2 गीगावाट, बायोमास गैसीफायर/कोजेनेरेशन 619 मेगावाट, बगासे कोजेनेरेशन 300 मेगावाट, विन्डपावर 144 मेगावाट, अनुपयोगी वस्तु से ऊर्जा 73 मेगावाट इत्यादि) की सम्भावना है जो अभी भी बढ़ने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त सोलर ऑफ ग्रीड उपयोग के लिए भी बहुत बड़ी सम्भावना है जैसे एस0पी0भी0 पम्प, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि। यह अक्षय ऊर्जा मोडूलर प्रोडक्ट उत्पादन के लिए आरई प्रोजेक्ट के लिए असीम संभावना दर्शाती है।

अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्र।—निम्न प्रकार की सुविधायें/इकाइयों प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किये जायेंगे।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सोलर पावर	सोलर-फोटोभोल्टाईज और सोलर थर्मल पावर जेनेरेशन सोलर हाईब्रीड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में सोलर का उपयोग।
बायोमास	बायोमास और बायोगैस प्रोजेक्ट, बायोमास हाईब्रीड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बायोमास का उपयोग।
हाइडेल पावर	छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (25 मेगावाट तक)
अन्य	सुगर एवं अन्य उद्योगों में कोजेनेरेशन वेस्ट आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना नगरपालिका और औद्योगिक वेस्ट सहित/विन्ड पावर परियोजना। = ग्रामीण ऊर्जा मोड्यूलर प्रोडक्ट विनिर्माण।

नोट:— इकाइयों/उद्योगों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.8 हेल्थकेयर प्रक्षेत्र।—बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संकेतांक जैसे शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर) 42, मातृ मृत्यु दर(एम0एम0आर0) 219 कुल प्रजनन दर (टी0एफ0आर0) 3.5 इत्यादि जो राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक है और यह राज्य के निम्न स्वास्थ्य स्तर को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य सुविधा के साधन पर पहले से ही अत्याधिक बोझ है जो आधारभूत संरचना और आवश्यक स्वास्थ्य आवश्यकताओं यथा मानव संसाधन, उपकरण, दवाइयाँ और अन्य उपभोग्य वस्तुओं के सुदृढीकरण की दिशा में है और इस प्रकार वे वर्तमान में अकेले पूरे जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार से सुविधायें समुचित नहीं है जो वर्तमान समय में पूरी जनसंख्या को हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी कर सके। हेल्थ केयर के समीक्षोपरांत इस प्रक्षेत्र में आधारभूत संरचना में कमी को निम्नवत दर्शाया गया है:—

प्रकरण	आवश्यकता	वर्तमान स्थिति (कार्यरत)	कमी
मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल	40	09	31
जिला अस्पताल	38	36	02
अनुमंडलीय अस्पताल	212	44	168
रेफरल हॉस्पिटल	70	57	13
सामुदायिक हेल्थ सेन्टर	838	0	838
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,314	533	2,781
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,787	1,350	1,437
उप स्वास्थ्य केन्द्र	20,997	9,729	11,268

इसके अतिरिक्त राज्य में बहुत कम प्राइवेट होस्पिटल है। अधिकांश व्यवस्थित प्राइवेट हेल्थकेयर संस्थान पटना राजधानी शहर में ही सीमित है। सेकेंडरी तथा टर्सियरी हेल्थकेयर सेवा लेने के लिए रोगी को पटना आना पड़ता है। राज्य की अधिकांश हेल्थकेयर आवश्यकता व्यक्तिगत निजी प्रैक्टिसनर्स द्वारा संचालित नर्सिंग होम द्वारा पूरी की जाती है, जो सामान्य हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी करता है। इनमें से बहुत कम विशेष सेवाओं को प्रदान करता है। इसलिए राज्य में हेल्थकेयर उद्योग के लिए निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप की अत्याधिक आवश्यकता एवं प्रचुर संभावना है।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की प्राथमिकतायें।—राज्य सरकार के प्राथमिकताओं को सुदृढ करने के मद्देनजर सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाने, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित घटक की पहचान की गयी है:—

क्षेत्र	निवेश के अवसर
रोगी स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें	स्पेशलिटी अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, अति आधुनिक ट्रामा सेन्टर
आपातकालीन चिकित्सा सेवा	मोबाईल मेडिकल युनिट, बल्ड बैंक
मानव संसाधन विकास/कौशल विकास सेवा	मानव संसाधन विकास/कौशल विकास केन्द्र (अस्पताल सेवाओं, जैव चिकित्सा रख-रखाव आदि),

विनिर्माण इकाईयाँ	दवाएं
विनिर्माण इकाईयाँ के उपकरण और आपूर्ति	चिकित्सा उपकरण, रोगी मॉनिटर, अनेस्थेसिया मशीन, सर्जिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो-सर्जिकल उपकरण आदि, सेवा उपकरण यथा रक्त संग्रह ट्यूब, दस्ताने, कैथेटर, मूत्रविज्ञान डिस्पोजेबल उत्पाद, एंडोस्कोप (माउथ पीस)
अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन सेवायें	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन इकाई
शिक्षण संस्थान	ग्रेड-A नर्सिंग कॉलेज

नोट :- उपर्युक्त सूची में इकाईयाँ/उद्यम साकेतिक रूप में दी गयी हैं एवं राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रवार सूची में उपयुक्त पुनरीक्षण कर सकती है।

3.9. चमड़ा प्रक्षेत्र।—चमड़ा प्रक्षेत्र में रोजगार, उत्पादन में वृद्धि और निर्यात की अपार सम्भावनाएँ हैं। भारत इस प्रक्षेत्र के माध्यम से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। बिहार में चमड़ा प्रक्षेत्र में निवेश की विशाल सम्भावनाएँ हैं। बहुतायत में कच्चे माल (राज्य में उत्पादित पशुचर्म और खाल के संदर्भ में) के साथ सस्ते एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमसंसाधन की उपलब्धता और उत्पादित सामाग्रियों के खपत के लिये राज्य एक विशाल घरेलू बाजार के रूप में भी है, यह संभावित निवेशकों को तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धा दोनों को लाभ का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन के रणनीतिक लाभ के कारक इस प्रकार हैं:—

प्रमुख घटक	हमारे रणनीतिक लाभ
कच्चे खाल एवं खाल की उपलब्धता	<p>(क) बिहार में देश के कुल गोजातीय जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत हैं। 2012 के पशुधन की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन की जनसंख्या 329.38 लाख थी। जनगणना के अनुसार गाय की जनसंख्या 122.31 लाख, भैस की जनसंख्या 75.67 लाख, बकरी की जनसंख्या 121.53 लाख बिहार देश के कुल बकरी की आवादी में तीसरे स्थान पर है, जो लगभग 12 प्रतिशत है। 2017 की जनगणना में बिहार के आकड़ों की स्थिति में काफी सुधार होगा।</p> <p>(ख) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (सी0एल0आर0आई0) द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण के आधार पर बिहार में सालाना 2.64 मिलियन गोजातीय कच्चे खाल तथा 5.09 मिलियन गोजातीय खाल पैदा करता है। राज्य अच्छी गुणवत्ता के बकरी की खाल, गाय खाल और भैस के बछड़े की खाल के लिये जाना जाता है। बकड़ी का खाल छोटे आकार का होने के कारण बच्चों की अच्छी गुणवत्ता वाली चमड़ों के उत्पाद बनाने हेतु सबसे उत्तम कच्चा माल है। इन उत्पादों को ज्यादातर निर्यात किया जाता है।</p> <p>(ग) एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जिले से 3 ट्रकों में भरकर लगभग 7-8 हजार अदद बकरी की खाल एवं 2-3 हजार अदद गौ खाल अन्य स्थानों को भेजा जाता है। राज्य में अवस्थित चमड़ों की इकाईयों द्वारा अधिकतर कच्चा माल कोलकाता, कानपुर और चेन्नई भेजा जाता है, जिससे बिहार लाभ से वंचित रह जाता है।</p>
श्रम की उपलब्धता	<p>(क) चमड़ा उद्योग एक अत्यधिक श्रम आधारित उद्योग है। इस उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक लघु कुटीर और कारीगर क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, इनमें से अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र के हैं। इस असंगठित लघु, कुटीर इकाईयों की मुख्य ताकत समाज के कमजोर वर्गों से सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता की बजह से है। इस प्रक्षेत्र में प्रमुख रूप से महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है।</p> <p>(ख) बिहार की बड़ी आबादी एवं बढ़ती जनसंख्या ही देश का सबसे बड़ा श्रम आधार भी है।</p> <p>(ग) वर्तमान में राज्य के पटना, गया, नालंदा/बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर आदि जिलों, जहाँ कारीगरों द्वारा चमड़ों के जूते निर्माण का कार्य किया</p>

	जाता है। इस प्रकार उपलब्ध कुशल श्रम को आसानी से चमड़ों की इकाइयों में नियोजित किया जा सकता है।
घरेलू बाजार की उपलब्धता	चमड़ा प्रक्षेत्र अन्तर्गत उत्पादित लगभग सभी वस्तुएं दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं। इस प्रकार इन उत्पादों की खपत की दर बहुत अधिक है। बिहार राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की बड़ी आवादी इस तरह के उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीय बाजार/मांग पैदा करते हैं। बड़े बाजार के आस-पास स्थित चमड़े की इकाई तत्काल दोनों पैमाने और लागत में कमी का लाभ ले सकते हैं।

चमड़ा प्रक्षेत्र की प्राथमिकतायें—चमड़ा उद्योग के अन्तर्गत मुख्य रूप से वैसी इकाईयाँ आती हैं, जो अर्द्धनिर्मित चमड़े और चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन में शामिल होती हैं। राज्य सरकार द्वारा कच्चे माल के प्रसंस्करण से तैयार सामान के निर्माण से संबंधित श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिये काफी ध्यान दिया गया है। इकाईयों को थ्रस्ट श्रेणी के तहत निम्न रूप से सुविधाओं का प्रस्ताव है :—

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
चमड़े के उत्पादों के निर्माण	(क) चमड़े के जूते, चमड़े के चप्पल और अन्य चमड़े के जूतों वस्तुओं के निर्माण (ख) चमड़ों के जूते के घटकों का निर्माण (ग) चमड़े के कपड़ों का निर्माण (घ) असबाब के लिए चमड़ा (ङ) चमड़े की वस्तुओं के निर्माण (जैसे लेबल, टैग, बेल्ट, बैंक, पर्स हाथ के दस्ताने और अन्य सामान और फैशन आइटम के लिए) (च) ऑटोमोबाइल (कार आदि) और फर्नीचर के असबाब का निर्माण (छ) घोड़े के काठी एवं साज-सज्जा उत्पादन
भंडारण	आधुनिक नियंत्रित/गैर नियंत्रण तापमान वाली भंडारण व्यवस्था एवं कच्ची खाल एवं त्वचा तथा अन्य चमड़ों के सामान हेतु प्रशीतन व्यवस्था, भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था।
व्यवसाय विकास सेवाएं	शोध एवं अनुसंधान सुविधा, डिजाइन स्टूडियो/प्रोटोटाइप, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा

नोट:— इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार प्राथमिक प्रक्षेत्र की सूची में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

इन सभी के अतिरिक्त, बिहार सरकार सी0 एस0 आई0 आर0 /सी0 एल0आर0आई0 के द्वारा विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेगी। इन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली इकाईयों/गतिविधियों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से थ्रस्ट एरिया के रूप में समझा जायेगा।

सी0एस0आई0आर0/सी0एल0आर0आई0 द्वारा विकसित महत्वपूर्ण ग्रामीण प्रौद्योगिकी की सूची निम्नलिखित है:—

- लेदर मोजरी/जूती फूटवियर
- लेदर कोल्हापूरी फूटवियर
- सामान्य फूटवियर (जूते)
- लेदर फूटवियर (सैंडल/चप्पल)
- लेदर पपेट निर्माण
- लेदर सामग्री
- लेदर बोर्ड
- पशु शव (Caracass) का संग्रहण एवं इसका उपयोग।

नोट:— इकाईयों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार किसी अन्य प्रकार के प्रौद्योगिकी को सूची में शामिल करने के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकती है।

3.10 तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र—वर्तमान में बिहार में 13 विश्वविद्यालय के साथ 262 सरकारी महाविद्यालय और 231 स्थानीय निकाय के महाविद्यालय बिहार सरकार से संबद्धता प्राप्त हैं। यद्यपि तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या सीमित है और मात्र 10 अभियंत्रण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं। बिहार में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की कमी के कारण राज्य के हजारों छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा जारी रखने के लिए दूसरे राज्यों यथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान पलायन करते हैं। यह राज्य को उच्च शिक्षा के केन्द्र (HUB) के रूप में विकसित करने के अवसर से विमुख करता है। राज्य के 38 जिलों में से 25 जिलों शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2017 तक GER का लक्ष्य 30 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा के लिए निर्धारित किया है। इस प्रक्षेत्र में यह बहुत बड़े पैमाने पर निवेश (Investment) को आकृष्ट करेगा। वर्तमान में बिहार का GER 13 प्रतिशत है। एक गणना (इस्टीमेट) के अनुसार राज्य को उच्चतर शिक्षा में नामांकन के राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य में 373 सामान्य महाविद्यालय (कला, विज्ञान, वाणिज्य), 236 अभियंत्रण महाविद्यालय, 139 चिकित्सा महाविद्यालय, 253 शिक्षण महाविद्यालय, और 163 बहुप्रावैधिकी (पॉलिटेक्निक) संस्थानों की आवश्यकता है। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि राज्य में नए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अपार संभावना है। बिहार में गरीबी रेखा के उच्च दर के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश परिवार भी अपने बच्चों को बिहार से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु भेजते हैं और राज्य से बाहर जाने एवं आवासीय व्यवस्था के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता है। इसलिए यदि राज्य में अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित होते हैं तो संस्थानों की अधिक आवश्यकता के कारण उनके फलने-फूलने के पर्याप्त अवसर हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र राज्य में रोजगार सृजन में भी मदद करेगा क्योंकि अधिकतर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से शैक्षणिक टाउनशीप का विकास होगा, जिससे उसमें रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अतएव छोटे व्यापारियों एवं युवा उद्यमियों के लिए अनेक प्रकार के रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।

शिक्षा प्रक्षेत्र के प्राथमिक प्रक्षेत्र :- तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र में निम्नांकित सुविधाओं/इकाइयों को प्राथमिक प्रक्षेत्र में रखा जायेगा :-

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
तकनीकी शिक्षा	अभियंत्रण महाविद्यालय और पोलिटेक्निक संस्थान (ए0आई0सी0टी0ई0 एक्ट के तहत निबंधित)
कौशल विकास	उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरण के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाला तकनीकी कौशल विकास केन्द्र (बी0एस0डी0एम0 या उद्योग विभाग से सूचीबद्ध)

नोट:- ईकाइयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार प्राथमिक प्रक्षेत्र की सूची में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

4. व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय (Ease of Doing Business Reform)

4.1 भूमिका।—राज्य सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं अत्यधिक नौकरियों के अवसर तैयार करने के क्रम में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिवद्ध है। राज्य में व्यवसाय के सरलीकरण में सुधार के लिए एवं राज्य भर में औद्योगिक ईकाइयों को राज्य में परेशानी मुक्त प्रवेश एवं संचालन के लिए मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत एवं सरलीकृत करने पर जोर देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। व्यवसाय के सरलीकरण के अंतर्गत किए गए सुधारों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

4.1.1 सूचनाओं की उपलब्धता

- उद्योग संवाद पोर्टल (www.udog.bihar.gov.in)— “निवेशकों के लिए एकल मंच”, जो राज्य के सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों/नियमों/नीतियों, परिपत्रों/सूचनाओं/अधिसूचनाओं की जानकारी प्रदान करता है।
- निवेशकों को विभिन्न अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति हेतु आवेदन में सुविधा के लिए संबंधित विभागों की वेबसाइट पर विस्तृत प्रक्रिया/निर्देशपुस्तिका जिसमें आवेदन समर्पित किए जाने से आवेदन के अनुमोदन तक सभी लागू कदमों का समावेश किया गया है, का प्रकाशन किया गया है।
- सभी आवश्यक कागजातों की व्यापक जाँच सूची जिसे आवेदन के भाग के रूप में समर्पित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

4.1.2 औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढीकरण

- उद्योग संवाद पोर्टल (www.udog.bihar.gov.in)— निवेशकों के शिकायत निवारण के लिए एकल मंच। यह मंच सीधे प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से सम्पर्क करने का विकल्प प्रदान करता है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तीव्र गति से परियोजना मूल्यांकन एवं स्वीकृति की सुविधा के लिए पैनलबद्ध परियोजना प्रबंधन एजेंसियाँ (PMAs)
- बिहार लोक सेवा अधिनियम के अधीन सेवाओं के गैर-अनुपालन पर नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई।
- सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया, अभिलेखों की आवश्यकता एवं विभिन्न मंजूरीयों यथा बिजली कनेक्शन, वैंट पंजीकरण, व्यवसाय कर पंजीकरण आदि की क्लियरेंस की समयसीमा को कम करना।

4.1.3 श्रम संबंधित सुधार।—राज्य सरकार द्वारा श्रम संबंधी सुधार हेतु उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं—

- फैक्ट्री अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस (नवीकरण सहित) के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- आवेदन ट्रेकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत करने हेतु स्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य करने के साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा।
- विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के लिए एकल संयुक्त निरीक्षण और एकल वार्षिक रिटर्न की सुविधा।
- पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त ईकाइयों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा।
- सुस्पष्ट परिभाषित निरीक्षण प्रक्रिया, निबंधित ईकाइयों का जोखिम आधारित ऑनलाइन निरीक्षण अनुपालन जिसमें निरीक्षकों का आवंटन स्वतः शामिल होगा, इत्यादि।

4.1.4 कर संबंधी सुधार।—कर से सम्बन्धित सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं—

- मूल्यवर्धित कर, पेशेवर टैक्स, इन्ट्री टैक्स, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर निबंधन की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- आवेदन ट्रेकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य किया जाना।
- पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा।
- निबंधित तथा अस्वीकृत विक्रेता (डीलर) के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा।
- 60 दिनों के अंदर विक्रेता (डीलर) के खाते में वैट की वापसी।
- ऑडिट कार्य हेतु विक्रेताओं (डीलर्स) को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा चिन्हित करना (सार्वजनिक प्रकाशित जोखिम मानकों पर आधारित)।

4.1.5 पर्यावरण संबंधी सुधार।—राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित सुधार हेतु उठाए गए कुछ मुख्य सुधारात्मक कदम निम्न प्रकार हैं—

- वायु एवं जल अधिनियम के तहत Consent to establish (CTE) स्थापित करने के लिए सहमति एवं Consent to operate (CTO) संचालित करने के लिए सहमति के लिए ऑनलाइन सहमति प्रबंधन प्रणाली; Hazardous Waste Rules के तहत प्राधिकरण।
- आवेदन ट्रेकिंग की सुविधा एवं CTE/ CTO/ प्राधिकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य करने के साथ प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा।
- Green Category के उद्योगों को CTO एवं CTE प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट।
- CTO की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाना।
- अनुपालन निरीक्षण की आवश्यकता को कम करना— **Green:** 5 वर्षों में 1 बार, **Orange:** 3 वर्षों में 1 बार; एवं **Red:** प्रत्येक वर्ष में 1 बार।

4.2. भावी दिशाएं (Way Forward)।—निर्धारित समय-सीमा में एवं पारदर्शी तरीके से निवेशकों को आवश्यक वैधानिक अनापत्ति और स्वीकृति उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच सुगम प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बिहार में व्यवसाय को सुगम तरीके से चलाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाएंगे :—

- एकल खिड़की शोधन प्रणाली।**— वैधानिक संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके एक नई एवं सरल एकल खिड़की शोधन प्रणाली (Single Window Clearance System) लाई जाएगी। ऑन लाईन तंत्र के माध्यम से अनुदान के ऑन लाईन आवेदन, समायोजन एवं प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।
- समान आवेदन पत्र (Common Application Form) की व्यवस्था।**— अनापत्ति निर्गत करने वाले सभी अभिकरणों के साथ समन्वय बनाने के लिए एक समान आवेदन पत्र (Common Application Form) को लाया जाएगा। समान आवेदन पत्र वेब आधारित होगा और धीरे-धीरे इसे भारत सरकार E-biz Portal (www.ebiz.gov.in) के साथ संबद्ध किया जाएगा ताकि संभावित निवेशक एक ही स्रोत से सभी प्रकार के अनापत्ति प्राप्त कर सकें।

- **प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी का प्रावधान**— उद्योग विभाग पी0एम0ए0 को सूचीबद्ध करेगी जो सक्षम समिति को निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्णय लेने के साथ-साथ निगरानी और प्रगति से अवगत कराने हेतु तकनीकी सहायता के साथ सचिवीय सेवा उपलब्ध करायेगा। निवेशकों के निवेश प्रस्तावों का सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु पी.एम.ए. एकल सम्पर्क बिन्दु होगा।
- **बियाडा अधिनियम में संशोधन**— बिहार सरकार वर्तमान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की समीक्षा करेगी तथा औद्योगिक क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु इसके विधिक ढाँचे को और सुदृढ़ करने हेतु इसमें संशोधन करेगी।
- **बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS ACT-2011) के अंतर्गत उद्योग से संबंधित सेवाओं का आच्छादन**— अनुरोध का समयबद्ध निष्पादन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निवेशक से सम्बन्धित अतिरिक्त सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 की परिधि में लाया जाएगा।
- **स्वप्रमाणन की व्यवस्था**— नए एकल खिड़की प्रणाली में स्वप्रमाणन का प्रावधान किया जाएगा, जिसकी ईकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के बाद अधिकृत प्राधिकार औचक जाँच कर सकते हैं।
- **कानून एवं प्रावधान का युक्तिकरण**— राज्य में श्रम कानून के अनुपालन को ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है। फिर भी इसके अनुपालन को यथासंभव सरल बनाने के लिए औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर समीक्षा की जाएगी।
- **अनुश्रवण एवं परिवाद समाधान प्रणाली**— इस नीति में लोक शिकायत से संबंधित विषय को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की परिधि में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग वर्तमान में वेब आधारित प्रणाली (www.udyog.bihar.gov.in) को सुदृढ़ करेगी जहाँ सुझाव और शिकायतों को सीधे औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को सम्बोधित करते हुए भेजा जा सकता है।

5. औद्योगिक निवेश हेतु आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण

- 5.1— परिचय**—विकसित औद्योगिक भूखण्ड, गुणवत्तायुक्त बिजली, दक्ष परिवहन प्रणाली आदि सहित उच्चस्तरीय गुणवत्ता के आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करना इस नीति के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं। राज्य में व्यवसाय और उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत सुविधाएँ कुंजी हैं, राज्य में वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
औद्योगिक भूमि	<p>(क) भूक्षेत्र के हिसाब से बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है। यहाँ भूमि की स्थलाकृति प्रकृति के कारण भारतवर्ष के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कुल भूमि का अनुपात कृषि उपयोग हेतु अधिक है। राज्य के संपूर्ण भूक्षेत्र का लगभग 57 प्रतिशत भूक्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ की जीविका का मुख्य श्रोत कृषि है और राज्य की आबादी को आवास एवं अन्य उपयोग हेतु भूखण्ड की आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि की व्यवस्था करना या खुली भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करना सरकार के लिए चुनौती है।</p> <p>(ख) बिहार में ईकाइयों को भूमि/औद्योगिक भूखण्ड आवंटित कराने के लिए बियाडा प्रमुख अभिकरण है। बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में है। वर्तमान समय में 50 औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक भू-सम्पदा / वृहत औद्योगिक भूखण्ड / विकास केन्द्र / मेगा औद्योगिक पार्क बियाडा के अधीन है।</p> <p>(ग) दिसम्बर, 2015 तक बियाडा ने कुल 5851 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है जिसमें से 3324 एकड़ भूमि विभिन्न निवेशकों को आवंटित किए गए हैं। आधारभूत संरचना आदि के लिए भूमि को स्वीकृत किए जाने के बाद 182 एकड़ भूमि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त है। बियाडा द्वारा विशेषतः विनिर्माण इकाइयों हेतु भू-खण्ड आवंटित किये जाते हैं।</p> <p>(घ) बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं यथा—सड़क, बिजली, पानी एवं नाली आदि की व्यवस्था को विकसित कर भूखण्ड का</p>

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
	<p>आवंटन करती है। दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1544 ईकाइयों कार्यरत अवस्था में है।</p> <p>(ड) राज्य सरकार के द्वारा राज्य में निम्नांकित पार्क की स्वीकृति दी गई है जहाँ पर विकसित भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध है:-</p> <p>(क) प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क- यह पार्क खगड़िया जिला में स्थापित हो रही है। यह 98 एकड़ में फैला हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह पार्क चालू हो जाने की संभावना है।</p> <p>(ख) पुनरासर जूट पार्क- यह देश का एकमात्र जूट पार्क है। यह पूर्णिया जिला में अवस्थित है। यह 44.30 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में यह पार्क चालू है।</p> <p>(ग) आई0टी0, आईटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क- राज्य सरकार के द्वारा राजगीर में 100 एकड़ और बिहटा (पटना) में 25 एकड़ जमीन आई0टी0, आईटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क के लिए कर्णांकित किया गया है।</p> <p>(घ) लेदर क्लस्टर- 11 एकड़ भूखण्ड में विस्तृत यह मुजफ्फरपुर में अवस्थित है।</p> <p>(ङ) गार्मेन्ट निर्माण पार्क- 25 एकड़ भूखण्ड में विस्तृत यह बिहटा (पटना) में अवस्थित है।</p> <p>औद्योगिक ईकाई की स्थापना हेतु इन सभी पार्कों में औद्योगिक ईकाई स्थापित करने हेतु पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना उपलब्ध है।</p>
ऊर्जा	<p>(क) मार्च, 2015 में बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता 3704.63 मेगावाट थी। इसमें से 83.5 प्रतिशत कोयला आधारित थर्मल पावर से, 14.12 प्रतिशत हाइड्रो पावर से और शेष 2.3 प्रतिशत गैर पारंपारिक ऊर्जा स्रोत से है।</p> <p>(ख) स्वामित्व के हिसाब से केन्द्रीय प्रक्षेत्र का हिस्सा 77.9 प्रतिशत, निजी क्षेत्र/IPP का 14.7 प्रतिशत और राज्य प्रक्षेत्र का 7.4 प्रतिशत हिस्सा है।</p> <p>(ग) राज्य सरकार ने लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि हेतु उर्जा क्रय का करार किया है ताकि राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एक समस्या के रूप में नहीं रहे। उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि के फलस्वरूप बिहार में प्रतिव्यक्ति उर्जा की खपत बढ़कर वर्ष 2012-13 में 145 KWH से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 203 KWH हो गया है। यह दो वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है जो देश के सभी राज्यों से अधिकतम है।</p> <p>(घ) राज्य में 13 लघु जलीय विद्युत परियोजनाएँ वर्तमान में चालू है जिनकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है वर्तमान में बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन राज्य में और अधिक लघु जलीय परियोजना की संभावना की तलाश में जुटा है। 17 योजनाओं में संभावना तलाशी का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>(ङ) बिहार सरकार ने राज्य में उर्जा क्रय हेतु ओपेन एसेस की अनुमति प्रदान की है। ग्रीड से संबद्ध सोलर रूफटॉप, फोटोभोल्टाईक प्रणाली से नेट मीटरिंग व्यवस्था की अनुमति दी गयी है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं। कैप्टिभ उपयोग, ग्रुप कैप्टिभ उपयोग और तृतीय पक्ष को बिक्री हेतु सोलर उर्जा के संग्रहण के प्रावधान के लिए भी अधिसूचना जारी किया गया है।</p>
सड़क	<p>(क) वर्तमान में बिहार में लगभग 2.26 लाख कि0मी0 सड़क की लंबाई है इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4595 कि0मी0 है। राष्ट्रीय उच्चपथ का लगभग 68 प्रतिशत दोहरीकरण और बहुपथ के हैं जबकि 32 प्रतिशत एकल एवं इन्टरमीडिएट लेन सड़क हैं।</p> <p>(ख) बिहार में राजमार्ग की लंबाई लगभग 4253 कि0मी0 है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत डबल लेन, 20 प्रतिशत सिंगल लेन और 15 प्रतिशत इन्टरमीडिएट</p>

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
	<p>लेन वाले सड़क है।</p> <p>(ग) राज्य में जिला स्तरीय सड़क का बड़ा जाल है। प्रधान जिला सड़क की लंबाई लगभग 10,634 कि०मी० है जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग (54 प्रतिशत) की चौड़ाई 3.75 मी० है। प्रधान जिला सड़कों में से 4897 कि०मी० को इन्टरमीडिएट या 02 लेन की चौड़ाई वाले सड़क में तब्दील कर दिया गया है। वैसे सड़क जिन्हें चौड़ीकरण की जानी है उसमें सतह समतलीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार प्रधान जिला सड़क के 5175 कि०मी० को इन्टरमीडिएट लेन के लिए न्यूनतम मापदण्ड 5.50 मी० की चौड़ाई वाले सड़क में उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है।</p> <p>(घ) वर्तमान में राज्य में लगभग 2.07 लाख कि०मी० ग्रामीण सड़क है। सभी ग्रामीण सड़कों को धीरे-धीरे विभिन्न योजनाओं यथा मु० मं० ग्राम संपर्क योजना, प्र० मं० ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत पक्की सड़क में उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।</p>
रेलवे	<p>(क) बिहार में रेलवे का 3,638.73 कि० मी० का सघन तंत्र है। राज्य के सभी जिले रेल तंत्र से अच्छी तरह से जुड़े हैं। राज्य के अधिकांश जिले देश के मुख्य शहरों से रेल तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं।</p> <p>(ख) राज्य के अंदर दो मुख्य रेल पथ गुजरते हैं:-</p> <p>I- दिल्ली-गौहाटी रेल पथ वाया छपरा-बरौनी-कटिहार</p> <p>II- दिल्ली-कोलकाता रेल पथ वाया आरा, बक्सर, पटना, ग्रैण्ड कॉर्ड पथ वाया गया सहित।</p> <p>(ग) बिहार में हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों में फैले 5230 ट्रैक किलोमीटर तथा 3624 रूट किलोमीटर के विस्तृत तंत्र पर नियंत्रण करता है।</p> <p>(घ) अभी हाल फिलहाल में रू० 7000 करोड़ की लागत वाली रेल-सह-सड़क पुल की 3 बड़ी परियोजनाएँ चालू हुई हैं। ये रेल-सह-सड़क पुल राज्य के अंदर परिवहन सुविधाओं में काफी सहयोगी साबित होंगी।</p> <p>(ङ) राज्य में पटना मेट्रो रेल परियोजना का भी क्रियान्वयन गति पर है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गई है एवं इस पर सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान कर दी गयी है।</p>
हवाई मार्ग	<p>(क) बिहार के पटना में एक घरेलू हवाई अड्डा और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और राँची के लिए कई घरेलू हवाई उड़ान हैं।</p> <p>(ख) बिहार में हवाई उड़ान की संख्या बढ़ाकर 2014-15 में 11054 हो गई है। विगत दो वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 10.5 लाख से 12 लाख हो गई है और माल टुलाई भी 4849 टन से 5198 टन तक बढ़े हैं।</p>

5.2. नीति के प्रभावी अवधि में आधारभूत संरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उपाय।-राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए नीति के प्रभावी अवधि में सरकार के द्वारा निम्नांकित उपाय प्रस्तावित हैं-

5.2.1 प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परियोजना के लिए रिक्त औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन।-नीति के प्रभावी अवधि में बियाडा भविष्य में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड (लगभग 182 एकड़) को अर्हता प्राप्त परियोजनाओं को आवंटित करना सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त रिक्त भू-खण्ड विनिर्माण करने वाली इकाइयों को आवंटित किया जायेगा। सरकार भी औद्योगिक पार्कों में उत्पादन करने वाली इकाइयों को भू-खण्ड का आवंटन करने में सहायता प्रदान करेगी।

5.2.2 बियाडा द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार।- (क) बियाडा राज्य के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा अनुमान है कि कुल 5000

एकड़ भूमि का अधिग्रहण और उसका विकास बियाडा द्वारा इस नीति की प्रभावी अवधि में आगामी 3 से 5 साल में किया जाएगा। इसके लिए भूमि बैंक से सरकारी भूमि को बियाडा को सम्बद्ध और हस्तांतरित किया जाएगा। नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त बजट का उपबंध किया जाएगा। इसके बाद बियाडा उक्त भूखण्ड को उत्पादन करने वाली औद्योगिक ईकाइयों के लिए उपयोगी बनाने हेतु विकसित करेगी तथा अंतिम दर अधिसूचित किया जाएगा जिसके आधार पर औद्योगिक ईकाइयों को भू-खण्ड उपलब्ध होगा।

(ख) नीति निर्धारण के तहत बियाडा द्वारा नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाइयों को ही भूमि आवंटित की जायेगी। बियाडा के द्वारा भूमि के आवंटन के उद्देश्य और प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है तथा औद्योगिक ईकाइयों के प्रकार एवं प्रदूषण स्तर के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का कर्णांकन संबंधी अधिसूचना भी निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार समय समय पर बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटित किये जाने वाले उद्योगों के प्रकार संबंधी अधिसूचना जारी कर सकेगी।

(ग) नीति निर्धारण के तहत बियाडा के द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाइयों को आवंटित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाई के लिए आवंटित 25 प्रतिशत भूखण्ड में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु ईकाइयों के लिए तथा 25 प्रतिशत मध्यम ईकाइयों की स्थापना के लिए होंगे।

5.2.3 रुग्ण एवं बंद ईकाइयों से भूमि की वापसी।—जहाँ कहीं भी संभव होगा सरकार वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में से रुग्ण एवं बंद ईकाइयों से भूमि को वापस लेने का पूरा प्रयास करेगी। बियाडा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए “एक मुश्त भुगतान” की प्रक्रिया लागू कर सकती है।

5.2.4 भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा: “आओ बिहार” योजना

(क) राज्य में औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के लिए भूमि हेतु निजी क्रेता एवं विक्रेता की सुविधा के लिए राज्य सरकार की “आओ बिहार” एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी।

(ख) इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिनके पास 2 एकड़ या अधिक भूमि का स्वामित्व है और अपनी भूमि को उद्योग या संस्थान की स्थापना के लिए बिक्री करना चाहता है, अपनी भूमि का विवरण “आओ बिहार” पोर्टल पर सूचीबद्ध करा सकता है। इच्छुक क्रेताओं को सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि क्रय के इच्छुक उद्यमी पोर्टल पर भूमि को खोज सकते हैं। राज्य सरकार अपने तंत्र के माध्यम से उद्यमी को भूमि के स्वामित्व के सत्यापन में सहायता करेगी ताकि क्रेता भूमि क्रय कर सकें।

(ग) राज्य सरकार का दायित्व मात्र सहायक के रूप में होगा। भूमि के दर निर्धारण और भूखण्ड के आवंटन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

5.2.5 एयर कारगो कॉम्प्लेक्स की स्थापना।—निर्यात आधारित औद्योगिक ईकाइयों के उत्पाद एवं नष्ट होने वाली कृषि उत्पाद के राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन के लिए पटना एवं गया में एयर कारगो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इस नीति की अवधि में इसे स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

5.2.6 कन्टेनर फ्रेट टर्मिनल।—राज्य में दो स्थानों फतुहा एवं बिहटा में कन्टेनर फ्रेट टर्मिनल है। बिहार सरकार इन टर्मिनलों में उपलब्ध सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रयास करेगी।

5.2.7 अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर एवं आई0एम0सी0 को बढ़ावा।—भारत सरकार के द्वारा इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कौरिडोर के साथ अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर का विकास प्रस्तावित है। प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर राज्य के तीन जिले यथा गया, जमुई और बांका होकर गुजरेगी। बिहार सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए बिहार सरकार प्रस्तावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी और जरूरी इन्टरभेंशन प्लान करेगी। अबतक बिहार सरकार के द्वारा डोभी, गया जिला को आई0एम0सी0 के लिए चिन्हित किया गया है।

5.2.8 गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि :-

(क) वर्तमान में बिहार में निम्नांकित चार नए विद्युत उत्पादन ईकाइयों का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर बिहार का केन्द्रीय क्षेत्र पर विद्युत की निर्भरता में कमी आएगी।

I- नवीनगर स्टेज 1 प्लांट— यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। इस विद्युत परियोजना के लिए प्रति ईकाई 660 मेगावाट क्षमता वाली 03 ईकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

II- बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय की विद्युत परियोजनाएँ— चौसा (बक्सर) में प्रति ईकाई 660 मेगावाट क्षमता की दो ईकाइयों वाली विद्युत परियोजना के निर्माण के

लिए सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा एन0एच0पी0सी0 और एन0टी0पी0सी0 के साथ भी प्रति ईकाई 660 मेगावाट वाली 02 थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए एकरारनामा सम्पन्न किया गया है। पीरपैती (भागलपुर) की ईकाई का निर्माण एन0एच0पी0सी0 द्वारा जबकि कजरा (लखीसराय) का निर्माण एन0टी0पी0सी0 द्वारा किया जाएगा।

III- अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (बांका) – बांका में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2500 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है।

IV- मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट (पश्चिमी चंपारण)– इस विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर है। इसकी क्षमता 800 किलोवाट है।

(ख) राज्य सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे निर्वाह विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी उद्योग जो 132/220 के0बी0ए0 फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को बिजली की कटौती से मुक्त किया जाएगा जबतक कि ग्रीड की सुरक्षा के लिए वैसा करना आवश्यक न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन एवं वितरण प्रणाली का समुचित उन्नयन किया जाएगा।

(ग) 33/11 के0भी0ए0 सब स्टेशनों के सभी फीडर जिनके उपर 75 (पचहत्तर) प्रतिशत से अधिक विद्युत भार है, औद्योगिक फीडर के रूप में जाने जायेंगे तथा विद्युत कटौती से विमुक्त होगा। यदि अन्य श्रेणी के उपभोक्ता इन फीडरों से सम्बद्ध हैं तो उन्हें इससे अलग करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

(घ) ओपन एसेस पॉलिसी–राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ओपन एक्सेस पॉलिसी के अंतर्गत विद्युत उपभोग की अनुमति होगी। यह बड़े विद्युत उपभोक्ताओं, जिनका 01 मेगावाट या अधिक विद्युत लोड है, को खुले बाजार से सस्ते दर पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान करेगी। यह उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर विद्युत खरीदने और बाजार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सहायक होगा।

5.2.9 गैस पाईप लाईन तंत्र की स्थापना—औद्योगिक विकास हेतु स्वच्छ उर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एक गैस ग्रीड विकसित किया जायेगा। राज्य में औद्योगिक और घरेलू मांग के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

राज्य सरकार गैल एवं अन्य तेल कंपनियां, जो देश के पूर्वी समुद्री तटबंध से प्रस्तावित प्राकृतिक गैस लाइन का तंत्र बिछाने से संबद्ध हैं, के साथ समन्वय स्थापित करेगी। पाइपलाईन के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों, विशेषकर औद्योगिक स्थानों वाले क्षेत्र में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य में गैस पाइपलाईन तंत्र की स्थापना हेतु बिहार सरकार एवं आई0ओ0सी0 तथा बिहार सरकार एवं गैल के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) भी हस्ताक्षरित हुए हैं। गैल का प्रमुख गैस पाइपलाईन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिला होकर गुजरेगी।

5.2.10 एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर को प्रोत्साहन—सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना—

(क) वर्तमान औद्योगिक नीति एम0एस0एम0ई0 क्लस्टरों के विकास के महत्व को पूरा देती है और इसलिए इसके सर्वांगीण प्रोत्साहन के लिए सचेष्ट है। राज्य में अनेक कार्यरत एवं संभावनायुक्त एम0एस0एम0ई0 क्लस्टर विद्यमान हैं, उदाहरणस्वरूप—

- i- ब्रास और ब्रॉन्ज मेटल यूटेन्सील उद्योग क्लस्टर, परेब, जिला—पटना
- ii- सी0एफ0एल0 और लीड बल्ब, पटनासिटी, जिला—पटना।
- iii- लेदर फुटवीयर, पटनासिटी, जिला—पटना
- iv- मखाना, चार जिलों में (दरभंगा मुख्य केन्द्र)/दरभंगा।
- v- चर्म उत्पाद क्लस्टर, जिला—सारण (छपरा)
- vi- अगरबत्ती निर्माण क्लस्टर, जिला—गया
- vii- लहठी (लाह) क्लस्टर, जिला—मुजफ्फरपुर।
- viii- लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला—मुजफ्फरपुर
- ix- ब्रास और जर्मन सिल्वर यूटेन्सील क्लस्टर, जिला—पश्चिमी चंपारण
- x- चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला—पूर्वी चंपारण
- xi- चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला—लखीसराय
- xii- पीतल ब्रास एल्वाय यूटेन्सील क्लस्टर, जिला—वैशाली
- xiii- लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला—नालंदा
- xiv- रेडिमेड परिधान क्लस्टर, पटनासिटी, जिला—पटना

- xv- सिलाव का खाजा क्लस्टर, जिला-नालंदा
 xvi- मीठा और नमकीन खाजा क्लस्टर, जिला-मधेपुरा।
 xvii- बाँस आधारित सामग्रियों का निर्माण क्लस्टर, जिला-मधेपुरा।
 xviii- हस्तकरघा और खादी (पोस्ट प्रोसेसिंग) क्लस्टर।
 xix- हस्तशिल्प क्लस्टर।
 xx- लघु संयंत्र एवं मशीनरी निर्माण क्लस्टर औरंगाबाद, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण)।
- (ख) कार्यरत, नये या सम्भावना युक्त क्लस्टरों, इनमें से किसी में भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। खासकर सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में। क्लस्टर एक्टर तकनीकी दृष्टि से भी कमजोर है तथा इन क्लस्टरों में तकनीकी और कौशल उन्नयन की नितान्त आवश्यकता है।
- (ग) बिहार सरकार ने क्लस्टरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना नाम की एक विशेष योजना वर्ष-2013 में प्रारम्भ की है। सरकार वर्तमान नीति काल में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रयास करेगी।
- (घ) केन्द्र सरकार के प्रासंगिक योजना के अंतर्गत उद्योग क्लस्टर जैसे- एम0एस0एम0ई0 मंत्रालय की लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) और डी0आई0पी0पी0 की आई0आई0यू0एस0 योजना जैसी उद्योग क्लस्टरों को भी राज्य सरकार आवश्यक सहायता देगी।

5.2.11 निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहन।-

- (क) वर्तमान नीति, राज्य में औद्योगिक भूखण्ड/भूमि और अन्य आधारभूत संरचना संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए निजी सहभागिता की भूमिका को पूर्णरूपेण स्वीकार करती है।
- (ख) बिहार सरकार में निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में "निजी औद्योगिक पार्क की नीति" लागू किया है। यह नीति वर्तमान औद्योगिक नीति के अभिन्न हिस्सा के रूप में होगी और सरकार कुछ संशोधनों/परिवर्तनों के साथ वर्तमान नीति अवधि में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगी। विशिष्ट प्रक्षेत्र के पार्कों की स्थापना को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी, विशेष रूप से प्राथमिक प्रक्षेत्रों को (उदाहरणस्वरूप- फूड पार्क, लेदर पार्क, आई0टी0 पार्क, टेक्सटाइल पार्क इत्यादि)
- (ग) इस नीति के तहत बिहार सरकार निजी औद्योगिक पार्कों के प्रवर्तकों (Promoters) को प्रोत्साहन देगी। निजी औद्योगिक पार्क को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एवं शर्तों का उल्लेख अध्याय 6 (अनुच्छेद 6.7) में किया गया है।

6. प्रोत्साहन हेतु सामान्य पैकेज।-बिहार सरकार राज्य में परिचालित उद्योगों में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने हेतु राजकीय प्रोत्साहन की आवश्यकता को समझती है। तदनुसार बिहार सरकार ने राजकीय प्रोत्साहन पैकेज सूत्रवद्ध किया है जो राज्य के तुलनात्मक लाभों की जानकारी देता है एवं यह प्रोत्साहन राज्य के आगामी औद्योगिक विकास में त्वरित गति प्रदान करेगा।

6.1 मार्गदर्शक सिद्धान्त/सामान्य प्रावधान :-

- (i) इस नीति के तहत सभी ईकाइयों पर सामान्य प्रावधान लागू होंगे।
- (ii) प्रभावी तिथि का मतलब वो तिथि जब से इस नीति के प्रावधानों को लागू किया जायेगा। यह नीति प्रभावी तिथि से पाँच वर्षों के लिये प्रभावी रहेगी।
- (iii) राज्य सभी भावी उद्यमियों/प्रवर्तकों को बैंक से सावधि ऋण की सुविधा प्राप्त करने हेतु एवं निवेश पर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- (iv) वैसी ईकाइयां जो प्रोत्साहन हेतु आवेदन करती हैं वो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ अनुसूचित बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार एग्जल रिपोर्ट के आधार पर प्रोत्साहन हेतु परियोजना लागत की गणना की जायेगी।
- (v) इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत का अर्थ समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकार के द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत होगा। स्वीकृत परियोजना लागत ही प्रोत्साहन की राशि के निर्धारण का आधार होगा।
- (vi) इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत में जमीन का मूल्य कुल प्रस्तावित निवेश के 10% से अधिक नहीं होगा। अतः स्वीकृत परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों के द्वारा परियोजना लागत में उल्लेखित जमीन का वास्तविक लागत या जमीन को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 10% दोनों में से जो कम हो,

- विचार किया जायेगा। यह सिद्धान्त इस नीति के अन्तर्गत सभी निवेशों के परीक्षण/जाँच पर लागू होगा।
- (vii) इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन राशि इकाई के उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद यथा व्यवसायिक उत्पादन की तिथि के बाद वितरित होंगे।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों हेतु सभी प्रकार के प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा (जमीन के अलावे) सभी श्रेणियों के उद्योगों (यथा सुक्ष्म लघु, मध्यम एवं वृहत उद्यम) में अतिरिक्त 15% तक बढ़ जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन-6.4 में उद्धृत है।
- (ix) महिलाओं, विभिन्न दिव्यांग, युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक प्रभावित, थर्ड जेन्डर इत्यादि उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा सभी उद्योगों के श्रेणियों में (जमीन को छोड़कर) 15% अतिरिक्त तक बढ़ा दी जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन-6.5 में उद्धृत है।
- (x) कोई भी इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के बाद या वर्तमान नीति की निर्धारित तिथि के 5 वर्ष समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त कर सकेगी।
- (xi) प्रोत्साहन या तो लागू आवश्यक परिमाण या उपयुक्त अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा। अनुमान्यता अवधि की समाप्ति के उपरान्त अव्यवहृत प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा।
- (xii) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य नीति के तहत कोई और प्रोत्साहन किसी इकाई द्वारा प्राप्त करने पर उस इकाई के लिये कुल उपाार्जित प्रोत्साहन की गणना के लिये विचारार्थ नहीं होगा।
- (xiii) इकाई के स्वामित्व या प्रबंधन में किसी भी बदलाव की स्थिति में इकाई द्वारा समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित सक्षम पदाधिकारी को सूचित करना होगा। आवश्यकता होने पर बचे हुये प्रोत्साहन राशि हेतु इकाई को (नये स्वामी के नाम पर) एक संशोधित या पात्रता प्रमाण पत्र जारी की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में पात्रता अवधि का विस्तार नहीं होगा तथा यह मूल उत्पादन तिथि से ही लागू होगा।
- (xiv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, महिला, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा स्थापित इकाई के शेयरहोल्डिंग के स्वरूप में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के अन्दर किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में नये शेयरहोल्डर उसी वर्ग के होने चाहिए। नये शेयरहोल्डर उस वर्ग के नहीं होने के स्थिति में दी गई प्रोत्साहन राशि देय तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जायेगी।
- (xv) अगर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कोई झूठी घोषणा दी जाती है या वैसे इकाई जो प्रोत्साहन राशि हेतु उपयुक्त नहीं है एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेती है तो दी गई प्रोत्साहन की राशि, देय तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जायेगी। निर्धारित तिथि तक ऐसी राशि के भुगतान नहीं करने की स्थिति में राशि को सूद सहित भूमि राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जायेगी।
- (xvi) बिना किसी पर्याप्त परिचालन कारण के सिर्फ प्रोत्साहन की अधिक राशि प्राप्त करने हेतु इकाई को तोड़ने का प्रयास, विभाजन या विलय तथ्यों की गलत बयानी सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दण्डनीय कार्रवाई का भागी होगा।
- (xvii) पालिसी अवधि के दौरान कोई मौजूदा इकाई या नई इकाई अगर क्षमता का विस्तार, विशाखन अथवा आधुनिकीकरण करती है तो वैसी इकाई को नई इकाई हेतु प्रोत्साहन का जो लाभ है, वह उनके अनुमोदित इन्क्विमेंटल परियोजना लागत पर देय होगा। परन्तु इस लाभ को प्राप्त करने के लिए इकाई के विद्यमान क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण होना अनिवार्य है।
- (xviii) इस प्रोत्साहन पॉलिसी के अंतर्गत वैसी इकाइयों जो प्रोत्साहन के योग्य नहीं हैं, से सम्बन्धित वंचित सूची परिशिष्ट-2 पर परिलक्षित है। वैसे उद्योग/क्षेत्र GST व्यवस्था के तहत भी किसी भी प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं होंगे।
- (xix) सभी तथ्यों की व्याख्या या विवाद का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा और वह निर्णय अंतिम होगा।

6.2 राज्य सरकार उद्यमियों को औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु एक अनुकूल वातावरण एवं आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने हेतु प्रतिबद्ध है ।
उद्यमियों को प्रोत्साहन के निम्न पैकेज प्रदान किये जाएंगे :-

प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
प्रतिपूर्ति स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण	<p>(क) सरकार द्वारा IDA/BIADA को भूमि आवंटन में कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं होगा ।</p> <p>(ख) वैसी सभी नई इकाइयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अथवा इसके बाहर स्थापित होती हैं, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् औद्योगिक भूमि/शेड की लीज/बिक्री/हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय होगी । पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति केवल पहली बार के लिए स्वीकृत की जाएगी । लीज/पट्टा/बिक्री/हस्तांतरण के बाद के चरणों में यह सुविधा लागू नहीं होगी । यह प्रोत्साहन केवल नई इकाइयों के लिए अनुमान्य होगा ।</p> <p>(ग) इकाई द्वारा वांछित भूमि का पूर्ण विवरण DPR में तथा वैसे बैंक या वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्णित होगा ।</p>
भूमि सम्परिवर्तन शुल्क	<p>(क) कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तन के लिए लगाए गए भूमि सम्परिवर्तन शुल्क/भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु लगाए गए शुल्क को इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के पश्चात् शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा ।</p>
ब्याज अनुदान	<p>(क) वैसी सारी उपयुक्त इकाइयाँ, जिसे किसी बैंक के द्वारा या RBI/सेबी के पंजीकृत वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण प्राप्त है, को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा ।</p> <p>(ख) ब्याज अनुदान हेतु ब्याज दर 10 प्रतिशत या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज का दर, जो भी कम हो, होगा । सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत का ब्याज दर अनुदान अनुमान्य होगा ।</p> <p>(ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुदान की समस्त सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 30% होगा । अप्राथमिकता वाले क्षेत्र में इस अनुदान की सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 15% होगा । इस अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी ।</p> <p>(घ) इस अनुदान राशि की विमुक्ति किशतों में की जाएगी । विमुक्ति की किशत सम्बन्धित बैंक या वित्तीय संस्थान, जिसके द्वारा इकाई को अवधि ऋण प्रदान की गई है, के द्वारा पुनः भुगतान के किशतों से जुड़ा होगा । इकाई के प्रवर्तकों के द्वारा किसी भी प्रकार के अंशदान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।</p> <p>(ड.) अगर प्रवर्तक इकाई के लिए कोई सावधि ऋण नहीं लेते हैं तो वे अनुदान की राशि के पात्र नहीं होंगे ।</p>
कर से सम्बन्धित अनुदान	<p>(क) सभी नई इकाइयाँ कर सम्बन्धी लाभ की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं :-</p> <p>(i) अप्राथमिक क्षेत्र :- स्वीकृत परियोजना लागत का 70%</p> <p>(ii) प्राथमिकता क्षेत्र:-स्वीकृत परियोजना लागत का 100%</p> <p>(ख) सभी नई सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को स्वीकृत परियोजना लागत का 30% अतिरिक्त कर में छूट दी जाएगी ।</p> <p>(ग) वैसी सभी इकाइयाँ जो सौर और अक्षय उर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु कार्यरत हैं, को स्वीकृत परियोजना लागत का अतिरिक्त 30% कर का लाभ दी जाएगी ।</p> <p>(घ) सभी नई इकाइयाँ द्वारा राज्य सरकार के खाते में दी गई VAT/CST/प्रवेश</p>

	<p>कर का व्यवसायिक उत्पादन में आने की तिथि से पाँच वर्ष तक 80% प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे (इकाई द्वारा व्यापार से सम्बन्धित करों को छोड़कर)। VAT/CST/प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति सिर्फ उत्पादन देयता कर के विरुद्ध Input Tax Credit के समायोजन के बाद शुद्ध देय कर पर लागू होगा।</p> <p>(ड.) भारत सरकार पूरे देश में समरूप माल एवं सेवा कर (GST) लागू करने की प्रक्रिया में है, अगर ऐसा होता है तो इस नीति के तहत VAT/CST में स्वीकृत प्रोत्साहन के लाभ को राज्य सरकार द्वारा GST व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।</p> <p>(च) सभी नई इकाइयों व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने के पाँच वर्ष तक स्व कार्य हेतु विद्युत उत्पादन या BSPHCL को आपूर्ति उर्जा पर देय विद्युत शुल्क पर शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति का पात्र होंगी। विद्युत शुल्क में छूट उन इकाइयों पर लागू नहीं होगा जो उत्पादित बिजली को BSPHCL के अलावे किसी दूसरी इकाई को आपूर्ति करती है।</p>
--	--

- 6.3 केन्द्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय**।—इस प्रोत्साहन की योजना को केन्द्र सरकार की योजना में समन्वय करने की स्वीकृति दी जा सकती है वशर्त कि एक ही परिसम्पत्ति राज्य एवं केन्द्र सरकार के अनुदान की राशि के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो। अतः किसी भी उद्यमी के द्वारा भारत सरकार की योजना के अंतर्गत किसी इकाई की परिसम्पत्तियों पर स्वीकृत राशि के विरुद्ध अनुदान प्राप्त करता है तो राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की राशि की गणना परिसम्पत्तियों के मूल्य को घटाकर की जाएगी।
- 6.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज**
- 6.4.1** अ.जा. एवं अ.ज.जा. के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जायेगा।
- 6.4.2** अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमी किसी नई इकाई की स्थापना करते हैं तो ब्याज दर के लिये 11.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान या सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में अगर अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती है, ब्याज अनुदान की दर 13.8 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगा, वहीं अनुमान्य होगा।
- 6.4.3** ब्याज अनुदान की कुल रकम अनुमोदित परियोजना लागत की 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र) तथा 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र) होगी। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रुपये होगी।
- 6.4.4** नई इकाई अ.जा./अ.ज.जा. के द्वारा स्थापित की जा रही है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा VAT/CST/प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे (उद्यमी द्वारा भुगतान किये गये किसी भी व्यापारिक कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्नप्रकार होगी :-
- (I) गैर प्राथमिक क्षेत्र – स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत
- (II) प्राथमिक क्षेत्र – स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत
- 6.4.5** राज्य सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जो इकाई की स्थापना एवं संचालन में सहायता देगी।
- 6.4.6** ऐसे उद्यमियों के लिए सामान्य सुविधा के साथ विशेष कलस्टर विकसित किये जायेंगे।
- 6.5 महिलाओं, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज**
- 6.5.1** महिलाओं, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जाएगा।
- 6.5.2** यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार-विण्डो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा नई इकाई की स्थापना की जाती है तो ब्याज अनुदान हेतु ब्याज का दर 11.5 प्रतिशत या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार-विण्डो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर उद्यमी सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थापना करते हैं तो उन्हें ब्याज दर का 13.8 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम हो ब्याज अनुदान देय होगा।
- 6.5.3** छूट की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र के लिए) जो स्वीकृत परियोजना लागत का 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र)। छूट की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रुपये होगी।

- 6.5.4** यदि उन उद्यमियों द्वारा नई इकाई स्थापित की जाती है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए स्वीकृत VAT/CST/प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी (व्यापार संबंधी जमा कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी:-
- (I) **गैर प्राथमिक क्षेत्र** – स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत
- (II) **प्राथमिक क्षेत्र** – स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत
- 6.6 एम.एस.एम.ई. कलस्टर डेवलॉपमेंट सेन्टर के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के साथ डोभ टेलिंग**।- मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सी.एफ.सी. की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों के डोभ टेलिंग की अनुमति होगी। इसके साथ यह शर्त होगी की एक ही एसेट औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं उक्तयोजना द्वारा आच्छादित नहीं होंगे। इस प्रकार इस योजना के तहत सी0एफ0सी0 के किसी विशेष परिसम्पत्ति पर लिये गये/लिये जाने वाले अनुदान की स्थिति उस परिसम्पत्ति को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान की गणना के लिए स्वीकृत परियोजना लागत में नहीं जोड़ा जायेगा।
- 6.7 निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रोत्साहन**।-निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिये जाएंगे। वर्तमान पॉलिसी अवधि के दौरान इस योजना के लिए प्रभावी अंशदान निम्नप्रकार के हैं:-
- (क) किसी भी व्यक्ति/पार्टनरशीप फर्म/एल.एल.पी./कम्पनी एक्ट या सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकती है।
- (ख) पार्क के प्रवर्तक को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। पार्क के लिए भूमि की व्यवस्था में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।
- (ग) प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा (आई.टी.पार्क के लिए 3 एकड़)।
- (घ) पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि प्रवर्तक के पूर्ण रूपेण स्वामित्व में होगा और किसी भी तरह के ऋण भार से मुक्त होगा। यह प्रवर्तक के द्वारा लीज पर नहीं लिया जाना चाहिए।
- (ङ) भूमि का 20 प्रतिशत क्षेत्र सामान्य प्रयोग/आधारभूत संरचना के विकास/हरित क्षेत्र एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (च) औद्योगिक पार्क में कम से कम 5 स्वतंत्र उत्पादन इकाई होनी चाहिए।
- (छ) प्रवर्तक भूमि/प्लॉट्स को स्वतंत्र इकाई के आवंटन हेतु उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- (ज) प्रवर्तक इस औद्योगिक पार्क में आवासीय इकाई निर्मित नहीं करेंगे तथा औद्योगिक पार्क को रीयल एस्टेट परियोजना में परिवर्तित नहीं करेंगे। औद्योगिक पार्क का उपयोग सिर्फ औद्योगिक उपयोग के लिए होगा। सभी निजी औद्योगिक पार्क औद्योगिक भूमि के रूप में अधिसूचित किये जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में निजी औद्योगिक पार्क को औद्योगिक उपयोग के अलावे किसी दूसरे कार्य में नहीं लिया जा सकता है।
- (झ) निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड का दर प्रवर्तक निर्धारित करेंगे। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- (ञ) पार्क के आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रवर्तक एक निधि की व्यवस्था करेंगे जिसे विकास रिजर्व फण्ड के रूप में जाना जाएगा। प्रवर्तक भूखण्ड के आवंटन में प्राप्त राशि में 05 प्रतिशत एवं प्रति वर्ष शुद्ध लाभ से 10 प्रतिशत इस विकास रिजर्व फण्ड में योगदान देंगे। यह विकास सुरक्षित निधि सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। इसके संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रवर्तक या प्रवर्तक के प्रतिनिधि तथा पार्क में सक्रिय इकाई के प्रतिनिधि होंगे। किसी भी समय डी.आर.एफ. का अधिकतम 33 प्रतिशत आधारभूत संरचना के विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रवर्तक पार्क में स्थापित सक्रिय इकाइयों से रख-रखाव हेतु शुल्क ले सकते हैं। उपर्युक्त समिति ही रख-रखाव के माध्यम से एकत्रित किये गए राशि के संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगी।
- (ट) निजी औद्योगिक पार्क 10 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से स्वीकृत परियोजना के 30 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान के पात्र होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी। प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेष निजी औद्योगिक पार्क, (यथा फूड पार्क, लेदर पार्क, टेक्सटाईल पार्क, आई.टी.पार्क इत्यादि) को स्वीकृत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी तक दी जा सकती है। निजी औद्योगिक पार्क के प्रमोटर पार्क के पूरा होने के उपरान्त ब्याज प्रोत्साहन के हकदार होंगे।
- (ठ) उपरोक्त के अलावा निजी पार्क अन्य प्रोत्साहन जिसका विवरण 6.2 में दिया गया है, के पात्र होंगे। ब्याज अनुदान उपर्युक्त कंडिका-(ट) के अनुसार देय होगा।

(ड) निजी औद्योगिक पार्क में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को योग्यता के अनुरूप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन देय होगा।

7. खरीद अधिमानता नीति।—

- (क) खरीद अधिमानता नीति उन एम.एस.एम.ई. फर्म/इकाइयों पर लागू होगी जिनकी विनिर्माण कार्य कलाप द्वारा मूल्य संवर्द्धन किया गया हो। व्यापार और पैकेजिंग इकाइयाँ मूल्य अधिमानता के पात्र नहीं होंगी।
- (ख) राज्य में एम.एस.एम.ई. इकाई द्वारा कोटिंग मूल्य 15 प्रतिशत के अन्दर अन्य बिडरों के न्यूनतम बिडिंग मूल्य की तुलना में हो, तो मूल्य अधिमानता के पात्र होंगे। ऐसी परिस्थिति में एम0एस0एम0ई0 इकाई को कुल कयादेश का 15 प्रतिशत न्यूनतम दर पर ऑर्डर दिया जायेगा। टाई के मामले में राज्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ग) यदि ऐसा होता है कि दो या अधिक राज्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग इकाइयाँ न्यूनतम मूल्य (L1) + 15 प्रतिशत सीमा के भीतर है तो ऐसे सभी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग को समान रूप से न्यूनतम मूल्य (L1) कीमत मूल्य आदेश को स्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा और 15 प्रतिशत अधिमानता वाले इकाई को आर्डर सामान रूप से एम. एस.एम.ई. इकाई में वितरित किया जाएगा।
- (घ) खरीद अधिमानता नीति कन्ट्रैक्टर्स एवं सब कन्ट्रैक्टर्स के लिए भी मान्य होगा अगर कम से कम कुल उत्पाद का 15 प्रतिशत स्थानीय एम0एस0एम0ई0 से अधिप्राप्त हो अगर उत्पाद राज्य में विनिर्मित हो।
- (ङ) कारोबार या फर्म के उम्र तथा टर्न ओवर के प्रतिबंध में बिहार के एम.एस.एम.ई. के लिए 50 प्रतिशत की छूट होगी, बशर्ते वे उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करते हैं।
- (च) उत्पादों की सूची जिसे बिहार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। बिहार के एम.एस.एम.ई. इकाइयों के बीच संबंधित उत्पाद के कय के लिए सिमित निविदा आमंत्रित किया जायेगा।

8. आने वाली नीति में रखने वाले प्रावधान के संबध में।—निम्नलिखित प्रावधान विद्यमान पॉलिसी के अंतर्गत आयेगे :-

- (क) सभी प्रकार की परियोजनाएं, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित है (उद्योग विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं0-128, दिनांक 16.01.2006 द्वारा परिभाषित किया गया है) लेकिन जो नई नीति के प्रभावी तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आयी हैं, उन्हें यह विकल्प दिया जायेगा कि नई नीति या विद्यमान औद्योगिक नीति से आच्छादित होना चाहते हैं। इन इकाइयों को विकल्प के साथ अलग से आवेदन देना होगा अन्यथा ये इकाइयों औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के तहत अच्छादित होगी। वैसी इकाई जो औद्योगिक नीति, 2011 के अंदर आच्छादित होना चाहती है, उन्हें 31 मार्च, 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन में आना होगा या उनके अनुमोदित डी0पी0आर0 मे जो समय सीमा निर्धारित किया गया है (जिनका समय सीमा 31 मार्च, 2017 के बाद का है) वे अपना अनुदान का दावा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत करेंगे। जो इकाई निर्धारित समय सीमा के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आती है, वे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के लिए योग्य नहीं मानी जायेगी, उन्हें नई नीति के तहत पुनः आवेदन करना होगा। इकाइयों जो नई नीति के तहत अच्छादित होना चाहती है उन्हें राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन करना होगा।
- (ख) विद्यमान इकाइयाँ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/दरों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, जबतक इकाई की समय-सीमा एवं/अथवा सीमा समाप्त न हो गई हो। जो इकाई पूर्व के प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त की हैं, वे इस नीति का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं होंगी, जैसा कि ऊपर के प्रावधान में उल्लेख किया गया है।

9. रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास।—औद्योगिक रूग्णता औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूँजी निवेश का अवरूद्ध होना, राजस्व की हानि एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त कदम उठाए जायें, जिससे कि रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास हो सके। सरकार इस संबंध में चिन्तित है तथा रूग्णता को रोकने एवं रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप रूग्ण हुई इकाइयों के पुनर्वास हेतु भी कदम उठाए जायेंगे।

9.1 औद्योगिक पुनर्वास निधि (कॉरपस निधि) :-

रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार, उद्योग संघों एवं अन्य के सहयोग से एक कॉरपस निधि (Corpus Fund) की स्थापना की जायेगी। यह कॉरपस निधि रूग्ण लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों, जिनका पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया गया हो, को संभावित कम-से-कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

9.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) में रूग्णता -

9.2.1 राज्य स्तरीय कमिटी :-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पुनर्वास हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति (शीर्षस्थ संस्था) द्वारा सभी प्रकार के निर्णय लिये जायेंगे।

9.2.2 रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था को पर्याप्त वैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की जायेगी। यह समिति पुनर्वास पैकेज को तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करेगी, जिससे की प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

9.2.3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/सीडवी के दिशा निर्देशों के अनुसार रूग्ण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की पहचान की जायेगी तथा पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करने में सहयोग करेगी, ताकि उपर वर्णित पुनर्वास पैकेज अनुमोदित हो सके।

9.2.4 पुनर्वासित हो रहे रूग्ण इकाईयों को प्रतिवर्ष रूग्णता प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु पुनर्जीवित पैकेज रूग्ण इकाई के पुनर्जीवन की अवधि विनिर्दिष्ट करेगा।

9.2.5 राज्य स्तरीय समिति द्वारा घोषित रूग्ण उद्योग ही पुनर्वास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप बैंक एवं वित्तीय संस्थान से मिलने वाली छूट एवं रियायत के पात्र होंगे। सभी प्रकार के छूट एवं रियायत एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर दिया जायेगा।

9.2.6 रूग्णता की पहचान कर तीन माह की समय-सीमा के अन्दर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जायेगा तथा राज्य स्तरीय संस्थान द्वारा रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा।

9.2.7 वैसी रूग्ण इकाईयाँ जिसने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लाभ उठाया हो, पुनः दुसरी बार इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई रूग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे पूर्व में रूग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि एवं नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि की अन्तर राशि ही देय होगी, परन्तु इस प्रकार की पुनर्वास सुविधा राज्य सरकार के स्तर से गठित संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

9.2.8 पुनर्वास पैकेज में जो तिथि होगी, उसे ही कट-ऑफ-डेट मानते हुए सुविधा का निर्धारण किया जा सकेगा।

9.3 वृहत्त उद्योगों में रूग्णता

9.3.1 प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जो वृहत्त प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले गैर बी0आई0एफ0आर रूग्ण औद्योगिक इकाईयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु यथा आवश्यक एवं नीतिगत वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा यह समिति करेगी एवं अनुशंसाएँ अंतिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष रखी जायेगी।

9.3.2 बी0आई0एफ0आर0 अथवा इस हेतु निर्मित सृजित वैधानिक संस्था यथा बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (बिसिको), बिहार राज्य वित्त निगम (बी0एस0एफ0सी0) तथा बैंक की अन्तर सांस्थिक समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चुनी गई रियायतें एवं सुविधाएँ प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से सरकार की अनुशंसा हेतु रखी जायेगी।

9.3.3 एक रूग्ण इकाई का अर्थ ऐसी इकाई से है, जो औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण पर्षद् (बी0आई0एफ0आर0) से निर्बंधित हो। यद्यपि ऐसी इकाई को सुविधाएँ एवं रियायतें बी0आई0एफ0आर0 द्वारा प्रचारित डी0आर0एस0 (Draft Rehabilitation Scheme) में अंकित कट-ऑफ-डेट से देय होगा।

9.3.4 रूग्ण इकाईयाँ, जिन्होंने पूर्व में औद्योगिक नीति का लाभ उठाया है, को पुनः दूसरी बार भी इस नीति के अन्तर्गत लाभ देय होगा। अगर कोई रूग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे पूर्व में रूग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि एवं नई नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित देय राशि की अन्तर राशि ही देय होगी, परन्तु इस प्रकार की पुनर्वास सुविधा राज्य सरकार के स्तर से गठित संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

10. नीति का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं तत्संबंधी शिकायतें ।—

10.1 नीति का क्रियान्वयन —

10.1.1 एक उच्च स्तरीय औद्योगिक सलाहकार पर्षद का गठन किया जायेगा। इस पर्षद में माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रमुख, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों के प्रतिनिधि, पब्लिक एवं प्राईवेट बैंकों के राज्य प्रधान, अग्रणी व्यवसायी/ राज्य के उद्यमी/परामर्शी संस्थाएँ आदि शामिल होंगे। पर्षद की बैठक वर्ष में दो बार आहूत की जायेगी।

10.1.2 नये व्यवसाय की स्थापना से संबंधित अनुमोदन तथा क्लियरेंस हेतु एक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद गठित की जायेगी। निवेश संबंधी आवेदन को पारित करने हेतु संबंधित विभागों के सक्षम पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। निवेशकों को नीति अन्तर्गत वांछित प्रोत्साहन दावों के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सचिवालय एक मात्र कॉन्टेक्ट प्वाइंट के रूप में कार्य करेगा।

10.1.3 नीति के क्रियान्वयन एवं प्रोत्साहन दावा के निस्तारण हेतु उद्योग विभाग मार्ग—दर्शन के साथ नीति के कार्यान्वयन हेतु एक फ्रेमवर्क जारी करेगा। इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहनों सहित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु संयुक्त आवेदन प्रपत्र (सी.ए.एफ.) का प्रयोग किया जायेगा।

10.1.4 नीति के दिन—प्रतिदिन क्रियान्वयन की देख-रेख राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय द्वारा किया जायेगा। निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग निदेशक, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण एवं निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बियाडा इत्यादि से सम्पर्क स्थापित कर विभाग द्वारा नीति अन्तर्गत उपलब्धि से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जायेगा।

10.2 नीति का अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण :-

10.2.1 नीति के क्रियान्वयन से संबंधी अनुश्रवण तथा अवरोध के उपयुक्त परिवेदना निवारण की पहचान हेतु एक नीति अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।

10.2.2 आवश्यकतानुसार वांछित सहायता एवं मध्यवर्ती सुधार को ध्यान में रखते हुए नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की जायेगी।

10.2.3 निवेशकों एवं राज्य सरकार के बीच प्रत्येक स्तर पर पारस्परिक संवाद हेतु नवीनतम तकनीकी से पूर्ण "Centralized Helpdesk Call Centre" का परिचालन किया जायेगा।

10.2.4 नीति के क्रियान्वयन के क्रम में किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी शब्द की व्याख्या/विवाद के सभी मामलों का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा लिया जायेगा। यह निर्णय सभी संबंधितों के लिए अंतिम और वाध्यकारी होगा।

10.3 सामान्य शर्तें ।—इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु निम्नांकित सामान्य शर्तें लागू होंगी ।—प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के साथ ही 18 प्रतिशत वार्षिक दर से कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट के साथ वसूली की जायेगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू-राजस्व की भांति सूद सहित बकाये की वसूली करेगी।

11. अनुसूची-I में दिए गए परिभाषाएँ इस नीति के अंग माने जायेंगे।

12. अनुसूची-II में वर्णित बंचित उद्योगों की सूची में शामिल उद्योग किसी प्रकार के प्रोत्साहन/अनुदान के योग्य नहीं होंगे।

13. यह नीति निर्गत की तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।

14. यह नीति अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है। इन दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डा० एस० सिद्धार्थ,

प्रधान सचिव।

परिशिष्ट – I

परिभाषाएँ

A. सामान्य परिभाषा I—

1. **औद्योगिक इकाई** — औद्योगिक इकाई/प्रतिष्ठान से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो निम्नांकित श्रेणी में आने वाले विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्योग में संलग्न हो अथवा संलग्न होने वाला हो।
 - (a) समय-समय पर यथा संशोधित उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में सूचीकृत उद्योग।
 - (b) निम्नांकित बोर्डों/अभिकरणों के दायरे में पड़ने वाले उद्योग (i) लघु उद्योग बोर्ड (ii) क्वायर बोर्ड (iii) रेशम बोर्ड (iv) अखिल भारतीय हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड (v) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (vi) औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा गठित कोई अन्य अभिकरण।
 - (c) अन्य श्रेणियाँ —
 - (1) खनन अथवा खनिज विकास।
 - (2) किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा वाहन अथवा नौका अथवा मोटरवोट अथवा ट्रेलर अथवा ट्रैक्टर के रख-रखाव, मरम्मत, जाँच सर्विसिंग।
 - (3) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास की सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेन्टर की स्थापना अथवा विकास।
 - (4) औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट अथवा तकनीकी ज्ञान अथवा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।
 - (5) उद्योग के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय, विपणन अथवा अन्य सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करना।
 - (6) सूचना प्रौद्योगिकी (IT), दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स (सेटेलाइट लिंकेज सहित) तथा दृश्य एवं श्रव्य केबल संचार सहित से संबंधित सेवा प्रदान करना।
 - (7) पर्यटन।
 - (8) स्वास्थ्य सेवा।
 - (9) इस नीति के “प्राथमिकता के प्रक्षेत्र” के तहत परिभाषित कोई कार्य।
2. **औद्योगिक इकाई की श्रेणी I**—वित्तीय प्रोत्साहन पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु परियोजना को निम्नरूपेण वर्गीकृत किया जा सकता है —
 - (a) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज (एम0एस0एम0ई0)** — भारत सरकार के स्तर से घोषित एम0एस0एम0ई0 अधिनियम 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज की परिभाषा को ही बिहार सरकार अनुसरण करती है।
 - (b) **वृहत् औद्योगिक इकाई** — एम0एस0एम0ई0 अधिनियम 2006 अन्तर्गत मशीन एवं संयंत्र के मद में मध्यम इकाई से संदर्भित निवेश राशि से अधिक परन्तु रु0 100 करोड़ से कम निवेश वाली इकाई वृहत् उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
 - (c) **मेगा औद्योगिक इकाई** — रु0 100 करोड़ एवं इससे अधिक के पूँजी निवेश की परियोजना मेगा उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
3. **नई औद्योगिक इकाई** — नई औद्योगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य इस नीति के लागू होने की तिथि से पाँच वर्षों के बीच आरंभ हुआ हो।
4. **विद्यमान औद्योगिक इकाई** — विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य इस नीति के लागू होने से पूर्व प्रारंभ हो गई हो। विद्यमान इकाई के द्वारा उसी परिसर में स्थापित इकाई को ही वित्तीय प्रोत्साहन के संदर्भ में नई इकाई माना जायेगा, जो अलग भवन/ढाँचा में अवस्थित हो, लेखा-जोखा अलग से संधारित करता हो तथा

जिसके द्वारा भविष्य निधि सहित किसी राज्य अधिनियम के तहत निर्धारित कर एवं ड्यूटी अलग से जमा किया जाता हो। विद्यमान इकाई के नये उत्पाद के समावेश की प्रक्रिया को नई इकाई के रूप में मान्यता नहीं होगी।

5. **अनुमोदित परियोजना लागत** – नीति अन्तर्गत अनुदान की गणना के उद्देश्य से अनुमोदित परियोजना लागत का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परियोजना लागत से है। अनुदान की स्वीकृति के निर्धारण हेतु अनुमोदित परियोजना लागत ही आधार होगा।
6. **विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन –**
 - (a) **विस्तार परियोजना** – विस्तार प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना होगा – प्रारंभिक संस्थापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगा।
 - (b) **विशाखन परियोजना** – विशाखन प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना होगा— बिना अवमूल्यन अनुमोदित परियोजना लागत में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा इकाई द्वारा नये उत्पाद दिशा की स्थापना आवश्यक होगा।
 - (c) **आधुनिकीकरण परियोजना** – आधुनिकीकरण प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना होगा :- आधुनिकीकरण के फलाफल के रूप में स्थापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगा।
7. **उत्पादन की तिथि** – किसी औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा, जबसे इकाई द्वारा वास्तव में उस सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया हो, जिसके लिए वह निबंधित की गई हो। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों के संबंध में संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। वृहत् उद्योगों के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उत्पादन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
8. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी** – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमी से तात्पर्य है ऐसे उद्यमी जिसके द्वारा पूर्णतः स्वत्वाधिकारी के रूप में इकाई की स्थापना की गई हो अथवा साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में 100 प्रतिशत स्थिर रूप से अंशदान हो।
9. **महिला उद्यमी** – महिला उद्यमी से तात्पर्य राज्य के महिला निवासी से है जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हो तथा जिन्होंने पूर्ण स्वत्वाधिकारी में इकाई की स्थापना की हो अथवा साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में जिनका स्थिर रूप से अंशदान 100 प्रतिशत हो।
10. **निःशक्तजन उद्यमी** – निःशक्तजन से तात्पर्य राज्य के ऐसे निवासी से है जो भारत सरकार के स्तर से घोषित Right of equal opportunity, Protection and full participation Act 1995 के अनुरूप विकलांग हो तथा जिसे सक्षम प्राधिकार के स्तर से इस हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। निःशक्तजन उद्यमी से तात्पर्य है ऐसे उद्यमी जिसके द्वारा पूर्णतः स्वत्वाधिकारी के रूप में इकाई स्थापित की गई हो अथवा साझेदारी, प्राइवेट लि0 कम्पनी के मामले में 100 प्रतिशत स्थिर रूप से अंशदान हो।
11. **टर्म लोन** – टर्म लोन से तात्पर्य है बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के स्तर से वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत एवं भुगतान किये गये ऋण।
12. **राज्य के निवासी** –राज्य के निवासी से तात्पर्य है, राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर पारिभाषित राज्य के मूल निवासी, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त हो।
13. **बंद औद्योगिक इकाई –**
 1. उद्योग विभाग के स्तर से दिये गये अनुदान, छूट एवं रियायत के परिपेक्ष्य में बंद इकाई से तात्पर्य है, वैसी इकाई जो स्थापित एवं उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकार के स्तर से वाणिज्यिक उत्पादन हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र धारी हो तथा स्थापना के पश्चात् 6 महीने

की अधिक अवधि से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपयुक्त एवं मान्य सूचना दिये बगैर बंद हो।

2. "रूग्ण इकाई" से तात्पर्य है वैसी औद्योगिक इकाई जो Sick Industries companies (Special Provision) Act 1985/National Company Law Tribunal (NCLT) के तहत औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण पर्सद (बी0आई0एफ0आर0) के स्तर से अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य शीर्षस्थ समिति अथवा वृहत्त प्रक्षेत्र हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के स्तर से रूग्ण घोषित हो।

14. **स्थायी नियोजन** – स्थायी नियोजन से तात्पर्य है स्थापित निबंधित उद्योगों के स्तर से प्रबंधकीय/कुशल कारीगर/अकुशल कारीगर की श्रेणी में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों /मजदूरों को सीधे तौर पर वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाना। इसका तात्पर्य है ठेकेदार के स्तर से मुहैया किये गये नियोजन सन्निहित नहीं है।
15. **लैंड बैंक** – लैंड बैंक से तात्पर्य है विनिर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र के बाहर अवस्थित प्राईवेट अथवा सरकारी जमीन का अधिग्रहण।
16. **प्रभावी तिथि** – प्रभावी तिथि से अभिप्राय वह तिथि है जबसे इस नीति के प्रावधान प्रभाव में आये। यह नीति लागू की गई तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

B. परिभाषा – पर्यटन प्रक्षेत्र

1. **पर्यटक स्थल** – नीति के चैप्टर-3 की धारा-3.2 में उद्धृत स्थल (जिला अथवा प्रखण्ड अथवा ग्राम) जो "पर्यटन प्रक्षेत्र" और "हमारे सामरिक लाभ" में उल्लेखित है, इस नीति के तहत पर्यटक स्थल कहलायेंगे।
2. **टूरिज्म सर्विस प्रोभाईडर** – नियमानुसार निबंधित कोई साझेदारी फार्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा निगम जो ट्रेवल एजेन्ट्स, ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स, टिकटिंग एजेन्ट्स, टूरिस्ट गाईड सर्विस प्रोभाईडर्स तथा होम-स्टे-ऑनर सहित यात्रा एवं पर्यटन संबंधी कोई सेवा प्रदान करता हो।
3. **होटल** – होटल परियोजना से अभिप्राय है, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से निर्धारित दिशा-निर्देश के आलोक में सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन प्राप्त जैसे होटल जिसमें एक सितारा से पाँच सितारा श्रेणी की स्थापना के अनुरूप अपेक्षित सुविधाएँ हो।
4. **हेरिटेज होटल** – एक हेरिटेज होटल से तात्पर्य है, एक होटल जो किला, महल, हवेली, गढ़, हंटिंग लॉज में कार्यरत हो अथवा जनवरी 1950 के पूर्व निर्मित धरोहर के रूप में निवास स्थल हो तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो। इस प्रकार के होटल को सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।
5. **मोटल** – मोटल परियोजना अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटल हेतु प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुरूप सभी सुविधाएँ होनी चाहिए। ऐसे मोटल को सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत आवश्यक कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।
6. **एम0आई0सी0ई0/कन्वेंशन सेन्टर** – एक कन्वेंशन सेन्टर अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कन्वेंशन सेन्टर हेतु प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुरूप सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। ऐसे कन्वेंशन सेन्टर को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होनी चाहिए।
7. **रिसोर्ट** – रिसोर्ट परियोजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रचलित दिशा-निर्देश के आलोक में तीन सितारा या उससे अधिक श्रेणी के अनुरूप सुविधायुक्त होना चाहिए। ऐसे रिसोर्ट को सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए।
8. **टेंटेड एकोमोडेशन** – एक टेंटेड एकोमोडेशन परियोजना अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टेंटेड एकोमोडेशन हेतु प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुरूप सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। टेंटेड एकोमोडेशन हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

9. **टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट** – संस्थान द्वारा पर्यटन/हॉस्पिटैलिटी पाठ्यक्रम जो नियामक प्राधिकार के स्तर से मान्यता प्राप्त/प्रमाणित हो, मुहैया कराना आवश्यक है।
10. **मेगा टूरिज्म यूनिट** – वैसी परियोजना मेगा टूरिज्म यूनिट के रूप में अनुमानित मानी जायेगी जहाँ 150 व्यक्तियों से अधिक को नया नियोजन सृजन की क्षमता तथा जिसमें भूमि लागत छोड़कर नया पूँजीनिवेश रु0 75 करोड़ या अधिक हो। वैसी इकाई ही इस श्रेणी अन्तर्गत सक्षम मानी जायेगी, जो नीति की प्रभावी अवधि के दौरान स्थापित हो तथा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करती हो। होटल तथा रिसोर्ट, मल्टीप्लेक्सेस तथा मॉल्स मेगा टूरिज्म इकाई की परिभाषा से बाहर माने जायेंगे।
11. **एम्यूजमेन्ट पार्क** – एम्यूजमेन्ट पार्क कम से कम 40,000 वर्ग मीटर (लगभग 10 एकड़) क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए तथा मनोरंजन सुविधा के रूप में सवारी, खेलकूद इत्यादि की व्यवस्था हो। स्टैंडलोन कॉमर्शियल मल्टीप्लेक्सेस एम्यूजमेन्ट पार्क के रूप में मान्य नहीं होगा।
12. **वाटर पार्क** – वाटर पार्क कम से कम 20,000 वर्गमीटर (लगभग 5 एकड़) क्षेत्र में निर्मित हो जिसमें न्यूनतम तीन वाटर स्लाईड्स हो तथा कम से कम एक साथ 100 स्लाईड्स को संभालने की क्षमता हो।
13. **थीम पार्क** – थीम पार्क एकल अथवा थीम श्रृंखला पर आधारित है जो कम से कम 10,000 वर्गमीटर (लगभग 2.5 एकड़) क्षेत्र में अवस्थित हो। इसके अन्तर्गत एम्यूजमेन्ट राईड्स, वाटर स्लाईड्स, रहने की व्यवस्था (कम से कम 10 लिटेल कमरा), रेस्टोरेन्ट, थियेटर, शॉपिंग क्षेत्र, एक्टीविटी क्षेत्र एवं थीम क्षेत्र हो। यद्यपि उपरोक्त सभी सुविधा एम्यूजमेन्ट पार्क के लिए होना अनिवार्य नहीं है।
14. **एडभेन्चर स्पोर्ट्स (जल क्रीड़ा सहित)** – एडभेन्चर स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा, संयंत्र, प्रशिक्षित कर्मी के साथ-साथ माकूल सुरक्षा सुविधा एवं बचाव की व्यवस्था होना आवश्यक है जो पर्यटक को पर्वतारोहण, नौकायन आदि मुनासिब साहसिक कार्य-कलाप के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसके पूर्व अलग-अलग सक्षम प्राधिकार से सभी प्रकार की आवश्यक अनुमति के साथ-साथ विस्तृत बीमा आच्छादन प्राप्त करना होगा।
15. **वे-साईड एमेनिटिज** – वे-साईड एमेनिटिज अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य उच्च पथ तथा अन्य जिला सड़क पर कम्पलेक्स के रूप सभी प्रकार की सुविधाएँ यथा विश्राम क्षेत्र, शौचालय, कैफेटेरिया, दुकान, प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ, पार्किंग, यादगार (Souvenir) बुथ इत्यादि का होना आवश्यक होगा। यद्यपि उपरोक्त सभी सुविधाओं का होना अनिवार्य नहीं है।
16. **रोप-वे** – वर्तमान अधिनियम/नियम अन्तर्गत स्थापित रोप-वे।
17. **टूरिस्ट लकजरी कोच** – एक टूरिस्ट लकजरी कोच का आशय ऐसे वातानुकूलित कोच से है, जिसमें बैठने की क्षमता कम से कम 13 सीट वाली हो तथा सीट को पीछे खिसकाया जा सके एवं जो सामान्य परिवहन की तरह विभिन्न पर्यटन स्थल के अवलोकन हेतु पर्यटकों को गन्तव्य स्थल तक ले जा सके। इसका संचालन वैध ऑल इंडिया परमिट होल्डर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा हो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूरिस्ट ऑपरेटर्स (आई0ए0टी0ओ0) से मान्यता प्राप्त तथा बिहार सरकार द्वारा निबंधित हो।
18. **कार वैन** – कम से कम 4 विस्तर वाली विशेष रूप से निर्मित वाहन जो किसी राज्य पर्यटन विभाग से निबंधित हो एवं जिसका उपयोग सामूहिक तौर पर अवकाश यात्रा में प्रयोग होता हो।
19. **स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती केन्द्र** – स्पा सेवा यथा मालिश, योग, समाधि तथा शारीरिक युवापन के लिए संबंधित चिकित्सा हेतु अल्प समय के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना ही स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती केन्द्र (हेल्थ एण्ड वेलनेश स्पा) का तात्पर्य है।
20. **क्रूज बोट्स** – कोई नाव/याच्ट जिसके बैठने की क्षमता 4 सीट हो, जो परिवहन विभाग, बिहार सरकार से निबंधित हो तथा भुगतान एवं व्यवहार सुविधा के तहत किसी झील/नदी में परिचालन की क्षमता रखता हो। लेकिन किसी होटल द्वारा अपने मेहमान के मनोरंजन अथवा सामान/कच्चा माल को ढोने हेतु व्यवहृत नाव/याच्ट इस परिभाषा की परिधि में नहीं है।
21. **साईस सेंटर, तारा घर, संग्रहालय** – एक भवन जहाँ एतिहासिक, विज्ञान से संबंधित, कलाकृति एवं सांस्कृतिक संबंधित वस्तु रखी एवं प्रदर्शित की जाती हो तथा टिकट के साथ/बिना टिकट आम नागरिकों के लिये खुला हो।

C. स्वास्थ्य सेवा प्रक्षेत्र

1. **विशिष्ट अस्पताल (Speciality Hospitals)** – विशिष्ट अस्पताल के अन्तर्गत वैसे अस्पताल आते हैं जहाँ कम से कम 60 बेड (विस्तर) हों, जिसमें से कम से कम 30 विस्तर विशेष रूप से विशिष्ट सेवा के लिए हो तथा 30 विस्तर सामान्य विस्तर हो। कुछ श्रेणियों के उदाहरण निम्नांकित हैं –

- कॉर्डियोलॉजी, कॉर्डियोभेसकुलर तथा कॉर्डियोथोरेसिक सर्जरी
- डायलाईसिस तथा लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलॉजी
- ऑर्थो स्कॉपिक सर्जरी तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट सहित ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी
- इमरजेन्सी केयर फॉर ट्रॉमा
- इंडोस्कोपिक सर्जरी
- न्यूरो सर्जरी
- ऑकॉलॉजी/ऑको सर्जरी
- ऑपथेल्मोलॉजी
- आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी
- ई0एन0टी0
- CGHS/MCI/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई विशेष श्रेणी
- सी0जी0एच0एस0 के प्रावधान के आलोक में मेट्रो शहर में 50 विस्तर तथा नॉन मेट्रो शहर में 30 विस्तर।

2. **अति विशिष्ट अस्पताल (Super Speciality Hospitals)** - अति विशिष्ट अस्पताल से तात्पर्य वैसे अस्पताल से है जहाँ निम्नांकित में से कम से कम तीन अति विशिष्ट की चिकित्सा सुविधा के अलावे कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट सर्जरी सहित स्पेसियलाईज्ड ऑर्थोपेडिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे अस्पताल में कम से कम 210 विस्तर होना चाहिए। जिसमें से कम से कम 30 विस्तर प्रत्येक अति विशिष्ट के लिये तथा 30 विस्तर सामान्य के लिये होना चाहिए। श्रेणियों के उदाहरण हैं –

1. कॉर्डियोलॉजी
2. गेस्ट्रो इंटरोलॉजी
3. इंडो क्राईनोलॉजी
4. नियोनेटोलॉजी
5. मेडिकल ऑकॉलॉजी
6. न्यूरोलॉजी
7. नेफ्रोलॉजी
8. पल्मोनरी मेडिसीन
9. न्यूरो रेडियोलॉजी
10. कार्डियो थोरेसिक सर्जरी
11. रियोमेटोलॉजी
12. न्यूरो सर्जरी

13. पैडियाट्रिक सर्जरी
 14. ऑकॉलॉजी
 15. सर्जिकल गैस्ट्रो इंटेरोलॉजी
 16. प्लास्टिक सर्जरी
 17. यूरोलॉजी
 18. सर्जिकल ऑकॉलॉजी
3. **बहु विशिष्ट अस्पताल (Multi Speciality Hospitals)** – बहु विशिष्ट अस्पताल का तात्पर्य वैसे अस्पताल है जो निम्नांकित में से एक से अधिक विशिष्टता प्रदान करता हो तथा जहाँ 90 विस्तर हो, जिसमें से कम से कम 30 विस्तर प्रत्येक विशिष्टता के लिये तथा 30 विस्तर सामान्य के लिये हो। विशिष्ट सेवाओं के उदाहरण हैं –
- कार्डियोलॉजी, कॉर्डियो वैस्कुलर तथा कॉर्डियो थोरेसिक सर्जरी
 - डायलाईसिस तथा लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलॉजी
 - ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी तथा ज्वाईंट रिप्लेसमेन्ट सहित ऑर्थोपेडिक सर्जरी
 - ट्रोमा हेतु इमरजेन्सी केयर
 - इंडोस्कोपिक सर्जरी
 - न्यूरो सर्जरी
 - ऑकॉलॉजी/ऑकों सर्जरी
 - ऑपथेल्मोलॉजी
 - आब्स्टेट्रिक्स तथा गायनेकोलॉजी
 - ई0एन0टी0

परिशिष्ट – II

बंचित उद्योगों की सूची

1. निम्नलिखित इकाईयों इस नीति के अन्तर्गत किसी भी सहायत के पात्र (योग्य) नहीं होंगे:–
 - (a) मादक दवाएँ बनाने वाली इकाईयों।
 - (b) एल्कोहलिक पेय बनाने वाली इकाईयों।
 - (c) तम्बाकू आधारित उद्योग।
 - (d) एसबेस्ट्स निर्माण करने वाली इकाईयों।

उपरोक्त सूची इस नीति के अन्तर्गत बंचित सूची कही जायेगी।
2. कोई भी इकाई नकारात्मक सूची अन्तर्गत आती है या नहीं, पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा तदनुसार उपरोक्त सूची को परिवर्तित किया जा सकता है।
3. व्यापक सिद्धान्त के तौर पर वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उद्योग को राज्य सरकार पूँजीनिवेश के लिए हतोत्साहित करेगी तथा उपर वर्णित नकारात्मक सूची में डाल दी जायेगी।

डा० एस० सिद्धार्थ,
प्रधान सचिव।

No.1822(H)**1st September 2016****Subject:- Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for promoting industrial development in the State**

The Government of Bihar is committed for the inclusive economic development of the State. Though the state is primarily an agrarian state but contribution of secondary sector i.e. industries, in inclusive economic development of the state is of equal importance and therefore can't be ignored. The State Government has taken a series of measures to further improve the investment climate in the state and envisages achieving the industrial development growth rate of 15% per annum. This means, increase contribution of secondary sector in the GSDP to more than 25% in line with the National Manufacturing Policy and "Make in India" initiative.

To achieve this goal the State Government has formulated the Industrial Investment Promotion Policy, 2016. The main strategy for achieving the goals of this policy is to focus on development of support infrastructure, prioritizing core sectors of future development with emphasis on advanced technology, skill development, a modified structured package of assistance and balanced regional development i.e. uniformly extending the benefits of investment to all geographical areas of the State. This policy also focuses on uplifting the socially marginalised groups & women entrepreneurs by offering specialized package of assistance to them. The policy has well-defined provisions for effective implementation, monitoring & grievance redressal for the entrepreneurs. Thus the Industrial Investment Promotion Policy, 2016 has an integrated approach towards industrial development in the state and offers a wide range of benefits to the investors coming to Bihar.

1. Introduction.—Bihar is one of the fastest growing states in India. During the period 2005-06 to 2014-15, the GSDP of Bihar at constant prices grew annually at 10.5 percent, which is one of the highest among all major Indian states. The scale and pace of economic change that Bihar has witnessed over the past few years has been the result of a comprehensive, home-grown reform program initiated by the government. These reforms ranged from changes in managing public finance and reforming government expenditures, public investments in building infrastructure, and most importantly revamping the law and order machinery. All these changes have provided an enabling environment for private investment in the state and greater industry commitment.

Bihar has a unique location specific advantage because of its proximity to the vast markets of eastern and northern India, access to ports such as Kolkata and Haldia and to raw material sources and mineral reserves from the neighbouring states. Bihar is primarily an agrarian state and is one of the largest producers of vegetables and fruits in India. Bihar is endowed with water resources – both ground and surface water– as it receives an average rainfall of 1009 mm each year. Ganga is the main river that flows through the state, joined by tributaries that originate in the Himalayas. Some of the other major rivers are Saryu, Gandak, Budhi Gandak, Bagmati, Kamla and Mahananda. The state has a large base of cost effective, industrial labour, making it an ideal destination for a wide range of industries. Food processing, dairy, manufacturing, healthcare are some of the fastest growing industries in the state. The State has planned initiatives for the development of other sectors such as agricultural implements and small machine manufacturing, tourism, information technology, renewable energy etc.

Bihar is aggressively working on developing supporting infrastructure in the state. In the absence of adequate roads no state can amplify its economic growth. With this background, the State Government has resolved to connect the capital city of Patna to the remotest areas in the state, so that people can reach the capital within a maximum of six hours from any place. In recent years, the State Government has been making endeavours to achieve this goal and, as a result, the network of roads and bridges has expanded at a rapid pace. The State Government has also adopted the Bihar Road Resource Protection Policy, 2013 to ensure better maintenance of the growing road network. The total length of

the State Highways (SH) is 4253 km (in 2015) and approximately 65% of these highways are double-lane roads. The National Highways, on the other hand, have a strategic significance in the state's economic development as they connect Bihar with other states. The total length of National Highways in the state is 4595 km (as of 2015) and efforts are being made to further increase the network at a rapid pace.

Golden Quadrilateral Highway that passes through Bihar is in close proximity to some of the districts, viz. Kaimur, Sasaram, Aurangabad Gaya & Patna. These districts are well connected to this highway via branch roads. This serves as a high logistical advantage in catering to the markets within as well as in the adjoining states of Uttar Pradesh, West Bengal, Orissa, and Jharkhand. It provides connectivity to major industrial, agricultural, and cultural centres of India. The length of Golden Quadrilateral Highway that passes through the State, i.e. 204 km, has been widened.

Eastern Dedicated Freight Corridor passes through the state and would connect Bihar with West Bengal, Jharkhand, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab and is expected to be immensely beneficial for industries in the state. It would facilitate the transport of finished products to ports in Bay of Bengal in lesser time; thereby, bringing down the transportation cost, significantly.

State Government has embarked on an ambitious plan to add substantial electricity generating capacity in the next few years. It is targeting to achieve a total generating capacity of 1330 MW by 2016-17, 3310 MW by 2017-18 and 7270 MW by 2021-22. In order to turn its vision into reality, Bihar State Power Generation Corporation Limited (BSPGCL) has entered into joint ventures with reputed companies in the power sector, like National Thermal Power Corporation (NTPC) and National Hydro Power Corporation (NHPC). Some of the major power sector projects, at different stages of commissioning, are Nabinagar Stage-1 Plant, power projects in Buxar, Bhagalpur, Lakhisarai and Banka. On completion of all these projects, Bihar's dependence on the centre for its power requirements will reduce significantly and the state would become self-sufficient in meeting its power requirements.

For the industrialization of the state, availability of land is an important factor. Consequently, land acquisition assumes greater significance and it necessitated the establishment of a land bank for which a corpus fund with a limit of INR 1500 crore was mooted. Later, this limit was raised to INR 2500 crore to meet the increasing demand of land by industries and other allied sectors. The State Government, in the last few years, have sanctioned a sum of INR 1650+ crore to Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA), for land acquisition to ensure rapid creation of the land bank and industrial areas.

There has been large scale change in industrial environment due to economic liberalization, privatization and globalization. Strong emphasis is being placed on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Cluster based development is being promoted by the State Government and it is in the process of setting up specialized clusters for development of leather, small machinery, plastics, garments, jute & textiles, and food processing to boost the manufacturing sector and well-being of MSME entrepreneurs.

Bihar is progressively adopting practices to create an investor friendly environment in the state, so as to facilitate investments. Some of the key reform measures taken are implementation of UDYOG SAMWAD portal for grievance redressal; effective implementation of single window system, development of an online inspection system; provision for submission of single integrated return under various labour laws; differentiated compliance inspection requirement based on risk profile of industries; provision of synchronized/joint inspection under various labour laws etc.

The present policy aims at creating industry-friendly environment for maximizing investment, especially, in priority sectors i.e. food processing; tourism; , small machine manufacturing; IT, ITeS, electrical and electronic hardware manufacturing; textile; plastic and rubber; renewable energy; leather and technical education sector. The overall objective is to maximize the value addition to state's natural resources by setting up industries across the state, generating revenue and creating employment. This policy has been drafted in consultation with representatives of industries; industry association, investors, subject

matter experts, etc. and efforts have been made to accommodate their views. It is expected that implementation of the policy will facilitate industrialization of the state, generate employment and add to its overall growth.

2. Our Vision, Mission and Strategy.—

2.1. Our Vision.—To establish Bihar as the most preferred investment destination by leveraging the state's comparative advantages and maximizing employment opportunities for attaining a balanced regional and sustainable development.

2.2. Our Mission.—

- Achieve industrial development growth rate of 15% per annum
- Increase contribution of the secondary sector to the GSDP to more than 25% in line with the National Manufacturing Policy and "Make in India" initiative
- Create direct employment opportunities for 5 lakh people across all economic sectors
- Attract on-ground investment of Rs.15,000 crore
- Create high-end infrastructure facilities to attract investments in the state
- Eradicate regional industrial imbalance by uniformly extending the benefits of investment to all geographical areas of the state
- Provide relatively more economic benefits to the priority sections of society such as SC/ST, women, differently abled, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs.
- Ensure that industries facilitate skill development of local people, so as to achieve the target of 15 million skilled youths as per the "Seven commitments" of the State Government.
- Increase the competitiveness of MSMEs and adoption of "Zero Defect Zero Effect" manufacturing practice

2.3. Our Strategy.— We will work with investors who share our vision of the future of Bihar as a vibrant economy, ready to take off on the path of sustained development. In particular, our strategy will consist of:

- Encouraging investments that add value to the farm produce and increase the income of the cultivators through processing and preservation of food crops, particularly vegetables and fruit crops.
- Utilising the traditional skills of artisans by finding a wider market for handloom and handicrafts.
- Investing in skill development and technical education so as to make Bihar the preferred source for skilled manpower - for which an acute shortage has been forecasted not only in different parts of the country but even markets abroad.
- Creating preference for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in view of their limited requirement of land, and their capacity to absorb more labour per unit of capital and energy.
- Encouraging cluster development in MSME sectors.
- Emphasising on industries that rely on local production, local skills, and local consumption.
- Providing preference to low energy and non-polluting industries
- Encouraging large scale industrial units in the proposed Integrated Manufacturing Cluster under the proposed Amritsar-Kolkata-Industrial Corridor (AKIC). While, the State Government will assist investors in finding suitable land for setting up units, they will be

expected to find land on their own for units outside these designated areas.

- Encouraging new investment in developing heritage tourism for which the state offers tremendous opportunities.
- Investments in developing new facilities and/or managing existing facilities under PPP mode will be encouraged.
- Promoting development of ancillary units to cater to the upcoming investments in public and private sector
- Establishing the Udyog Samwad Portal, a one stop platform for investors to resolve problems/ difficulties faced in establishment of industrial projects in the State.

2.4. Scope of Policy.—The policy would be applicable to all the new units in the state, with the following conditions:

- a. Any unit manufacturing any item, wherein the manufacturing activity does not contribute in value addition shall not be considered under this policy. Units involved only in trading activities will not come under the purview of this policy.
- b. Units promoted by individuals/ firms/ companies etc. that at any point in the past were black listed by the government(state or central) will not be eligible to avail the benefits of this policy.
- c. Units promoted by individuals/ firms/ companies etc. that at any point in the past has defaulted on any loan availed from any bank or Financial Institutions (FIs) or has any dues payable to government will not be eligible to avail the benefits of this policy.
- d. Incentives under this policy would be applicable only for the investments made in the state.
- e. Incentives under this policy cannot be claimed as compensation for any loss caused to the unit on account of any kind of natural calamity or business reason.
- f. This policy shall be applicable only for private investment, including foreign investment, but shall not apply to public sector investment by Central or State Governments either alone or in partnership with the private sector.

3. Our Priority Sectors.—Bihar enjoys a natural advantage in some sectors like food processing, leather, tourism, etc. and the State Government would like to leverage upon these advantages to ensure maximum employment generation and improve the standard of living of the people. A brief overview of the priority sectors is presented below:

3.1. Food Processing Sector.—Bihar, fundamentally an agrarian economy, has a large agricultural and animal production base offering abundant supply of raw material to be processed for human consumption. Despite these natural advantages, the level of food processing is very low and there is scope to improve the food processing levels to meet the increasing requirements of the state's growing population, while at the same time offering a sustainable consumption market. Further, the rising income and changing life style in the cities as well as rural Bihar is changing the consumption demand towards processed food. Therefore, the state offers a substantial opportunity for the food processing industry and is expected to play a leading role in the industrialization drive of this state. Some of the strategic advantages in this sector across key product offerings are listed below.

Key Agro Produces	Our Strategic Advantage
Food-grains (Cereals and	(a) The production level of cereals in the state has grown annually at 5.65% in the last 5 years i.e. 2010-11 to 2014-15. Total cereal

Key Agro Produces	Our Strategic Advantage
pulses) and oilseeds	<p>production of the state was 143.21 lakh tonnes in 2014-15 which is one of the largest in the country.</p> <p>(b) Some of the major products of the state are-Rice: 82.41 lakh tonnes; Wheat: 35.70 lakh tonnes; Maize: 24.78 lakh tonnes Pulses: 4.28 lakh tonnes; and Oilseeds: 1.27 lakh tonnes.³</p> <p>(c) Bihar has the highest maize productivity amongst all the Indian states.</p>
Fruits (Mango, Guava, Litchi and Banana) & Vegetable (Potato, Cabbage, Cauliflower, Okra)⁴	<p>(a) Bihar ranks first among all the Indian states in terms of vegetable production. The total vegetable production in the state was 144.99 lakh tonnes in 2014-15.</p> <p>(b) Some of the major vegetables produced in the state are Potato: 63.46 lakh tonnes; Onion: 12.47 lakh tonnes; Cauliflower: 10.03 lakh tonnes; and Tomato: 10.46 lakh tonnes. Other vegetables such as cabbage, okra, carrot, and pea are also grown in the state which can be used for commercial processing.</p> <p>(c) Some of the major fruits produced in the state are-Banana: 15.27 lakh tonnes; Mango: 12.72 lakh tonnes; Guava: 3.7 lakh tonnes; and Litchi: 1.98 lakh tonnes.</p> <p>(d) The state is well known- in India and in international markets - for its litchi produce, which presents a potential opportunity to set up units for litchi pulp, juice, pulp slab, nectar, jam, jelly, etc.</p>
Makhana	<p>(a) Makhana/Gorgon Nut is an exclusive offering of the state and has a strong potential to be placed in the wellness food category and can fetch premium pricing if marketed, appropriately.</p> <p>(b) Makhana/ Gorgon Nut is quite nutritive and compares well with fish/ mutton in terms of protein content. In China, raw makhana seed powder is considered to be an essential ingredient of baby food.</p>
Animal Products(Milk, Meat, Fish, Eggs, Honey)	<p>(a) The total livestock population in the state is 329.38 lakh and it is expected to grow significantly⁵.</p> <p>(b) Approximately 52% of the total livestock population is that of milch animals, with a cow population of 122.31 lakh, goat population of 121.53 lakh and buffalo population of 75.67 lakh.</p> <p>(c) Milk is one of the most important food product of the state with an average production of 79.172 lakh tonnes/ day, and this presents a sizeable processing opportunity</p> <p>(d) Large population of buffalo, goat and poultry presents a significantly large opportunity for meat processing</p> <p>(e) The state has a total water area of 10, 71, 000 hectares or 26, 77, 000 acres. This includes ponds (95,000 hectares), oxbow lake (9,000 hectares), reservoirs (26,000 hectares) and wetland (9.41 lakh hectares). The total river length in the state is approximately 3,200 km. The huge water wealth of the state presents gainful opportunity for fresh fish processing facilities/units. In 2014-15, the average fish production in the State from various water bodies was 5 lakh tonnes/ annum.</p> <p>(f) Bihar is the 4th largest producer of honey in the country and</p>

³ All figures are annual production in FY 2014-15;

⁴All figures are annual production in FY 2014-15;

⁵ According to livestock census 2012;

Key Agro Produces	Our Strategic Advantage
	produces approximately 6,500 tonnes per annum. Honey is becoming an important ingredient in today's world and is placed in the wellness food category. This product has the potential to be the first choice amongst the 1 st generation entrepreneurs due to low investment requirement and higher revenue potential.

Priority sectors in the food processing sector

The food processing units discussed below shall be considered under the priority sectors for the purpose of availing the incentives under this policy.

Sectors	Investment Opportunities
Food-grain (Cereal and pulses) and oilseed processing	<p>(a) Maize processing units with installed capacity of more than 100 TPD, including units for manufacturing starch and cattle and/or poultry feed</p> <p>(b) Any other cereal processing/flour/starch/dough mixes, breakfast food manufacturing unit with installed capacity more than 100 TPD.</p> <p>(c) Pulses processing unit</p> <p>(d) Modern unit for oilseeds processing or extraction from raw materials obtained locally; like Vanaspati oil manufacturing from rice bran and vegetables like soya-bean, safflower/sunflower, mustard, ground nut, etc. as well as fats and oils extracted from bovine/sheep/goat/fish/marine animals, etc. Unit for solvent extraction for edible oils with or without integrated refining facility.</p> <p>Note: Processing units purely for sorting, cleaning, and packaging that do not generate any substantial value addition shall not be considered under the priority sector.</p>
Fruits & Vegetable (F&V) Processing	<p>(a) All kinds of F&V processing units (including units for manufacturing dehydrated and frozen F&V items using IQF/Blast Freezer/Spiral Freezer, etc.)</p> <p>(b) Dehydration and powdering of vegetables like onions, mushrooms, etc.</p> <p>(c) Unit for processing litchi (e.g. units for manufacturing litchi pulp, juice, pulp slabs, jam, jelly, beverage, nectar, candies, powder, etc.)</p> <p>(d) Unit for processing local variety of mangoes into pulp, juice, pulp slabs, jam, jelly, beverage, nectar, candies, powder, etc. (units using mango pulp imported from other states or countries shall not be considered under the priority sector.)</p> <p>(e) Unit for banana processing (e.g. banana chips, pulp, powder, baby food, jam, jelly, banana flower vegetables, banana trunk vegetables & pickles, etc.)</p> <p>(f) Unit for makhana processing (e.g. unit for producing makhana pops, making flavoured and/or roasted makhana snacks, RTC kheer, baby food etc.)</p>
Milk Processing and Dairy Product Manufacturing	<p>(a) Milk processing units with installed capacities of more than 50 thousands litres per day</p> <p>(b) Units for manufacturing pasteurized milk, milk powder, ice cream powder, condensed milk, infant food, milk cream, butter, butter milk, lassi, yogurt, cheese, ghee, khoya, ice-cream, kulfi, flavoured milk and other dairy products.</p> <p>(c) Units that manufacture products out of milk powder imported from other states or countries shall not be considered under the</p>

Sectors	Investment Opportunities
	<p>priority sector. Only products manufactured from milk procured or milk powder manufactured by another unit within the state shall be considered under the priority sector.</p> <p>Note: For consideration under the priority sector, procurement of milk by the units shall not be carried out in areas where dairy co-operatives formed by COMFED are already in operation.</p>
Honey Processing	Natural honey processing unit
Meat, Poultry and Fish Processing	<p>(a) Meat, poultry and fish processing units (e.g. fresh, chilled, and frozen fish; fish fillets and pieces; fish cured or smoked and fish meal fit for human consumption; fresh and chilled meat of bovine animals such as sheep or goat; meat & edible offal of poultry meat; dried eggs; etc.)</p> <p>(b) Modern slaughter house & abattoir</p>
Spice and herbs Processing	<p>(a) Modern processing unit for spices (for e.g. extracts essence & concentrates of spices, powder and paste manufacturing etc.)</p> <p>(b) Unit for extraction of food flavors, colours, oleoresins, etc.</p> <p>(c) Health and wellness food supplements made from herbs</p>
Tea Processing	Modern tea processing units
Other edible preparation	<p>(a) Modern unit for manufacturing of biscuits/ cookies, etc.</p> <p>(b) Modern bakery unit (e.g. bread, pastries and cakes manufacturing)</p> <p>(c) Modern unit for manufacturing ice-cream</p> <p>(d) Modern unit for manufacturing chocolate & non-chocolate based confectionery items</p> <p>(e) Unit for manufacturing of frozen or non-frozen and packaged ready to eat (RTE) meals and snacks, ready to cook (RTC) food, powdered energy concentrate, instant drink concentrate, etc.</p>
Sugarcane Processing	<p>(a) Manufacture of sugar</p> <p>(b) Manufacture of ethanol</p>
Warehousing	<p>(a) Fruit ripening chambers</p> <p>(b) Controlled atmosphere (CA)/modified atmosphere (MA) chambers, cold rooms/ deep freezers/ pre-cooling chambers</p> <p>(c) Multiple cold storage facilities/infrastructure including pre-cooling chambers, ripening chambers, CA/MA chambers, cold rooms, deep freezers, bulk chillers, etc. including cold chain logistic arrangements</p> <p>(d) Modern grain silos</p>
General/ Business Development Services	<p>(a) Research & development facilities, quality control laboratories/ testing laboratories, training / incubation centres/skill development centres, etc. related to the food processing sector</p> <p>(b) Food machinery manufacturing</p> <p>(c) Irradiation unit</p>

Notes:

1. The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.
2. Units/ enterprises set up for the purpose of packaging/ repackaging of food items imported from other states or countries shall not be considered under the priority sector.
3. If a unit/ enterprise is setting up two or more kinds of facilities in an integrated manner/for captive use purpose, the facilities would be treated as a single project

- and combined cost of the facilities would be considered for grant calculation purposes. The classification of the units/ enterprises into priority or non-priority would be as per the nature of the main/mother facility, i.e. the core facility.
4. In case a unit migrates from non-priority sector to priority sector through capacity expansion and/or facility addition etc., it would enjoy the incentives as per the priority sector for the portion that falls under the priority sector.
 5. Units for manufacturing any food item fit for human/ animal consumption which does not contain any grain, F&V or any processed/preserved items (like pulp concentrate, extract .) made from grain/F&V as its main ingredient would be considered under the non-priority sector.
 6. Unit established for processing of by-products of the main food processing facility will be considered for a grant under the non-priority sector if the end product resulting from the processing of the by-product is not a food product fit for human/ animal consumption (with any exceptions defined above). If the final product is fit for human/ animal consumption it would be categorized as per the above list.

3.2. Tourism Sector.—Bihar has a potential for tourism in view of its rich cultural heritage, religious and historical monuments. Bihar's great competitive strength from tourism point of view is its ancient and yet living civilization that gave rise to two of world's great religions, namely Buddhism and Jainism. Bihar has been the centre of religious activities of Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs and Muslims. Endowed with a rich cultural and religious heritage, Bihar was a seat of power of the vast and powerful Magadh Empire. This is a land of ancient universities of Nalanda and Vikramshila, which spread knowledge far and wide through students coming from different countries of the world. The remnants of these two ancient universities, the antiques and artefacts attract tourists in huge numbers. The state has a rich tapestry of product offerings across its strengths of culture, heritage, nature, wildlife, wellness, as well as other unique products. Some of the key products offered by the state that attract travellers are:

Tourism Segments	Our Strategic Advantage
Spirituality	<p>Tourism in Bihar has traditionally thrived upon travellers visiting places of spiritual interest. Some of the identified tourism circuits focussing on this aspect are:</p> <p>(a) Buddha Circuit – Bodh Gaya (Gaya), Rajgir (Nalanda), Nalanda, Vaishali, Lauriya Nandangarh (East Champaran) , Lauriya Arreraj (East Champaran), Kesaria (East Champaran) Vikramshila (Bhagalpur), Jehanabad;</p> <p>(b) Sufi Circuit – Manersharif (Patna), Khankah mujibia (Patna), Mittan Ghat (Patna), Hajipur Karbala (Vaishali), Hasanpura (Nalanda), Bibi Kamal Shahib (Jehanabad), Badi Dargah (Nalanda), Chhoti Dargah (Nalanda);</p> <p>(c) Jain Circuit—Vaishali, Rajgir (Nalanda), Pawapuri (Nalanda), Nathnagar (Bhagalpur), Mandar Hill (Banka), Champanagar (Bhagalpur), Kundal Gram (Nalanda), Samosaran (Nalanda) and Lachhuar (Jamui);</p> <p>(d) Ramayan Circuit – Valmikinagar (West Chaparan), Pret Shila (Gaya), Ahilya Asthan (Darbhanga), Sitamarhi, Kako (Jehanabad), Sita- kund (Sitamarhi), Shingheshwar (Saharsa), Ramshila (Gaya), Buxar, Giddheshwar (Jamui);</p> <p>(e) Shakti Circuit – Mundeshwari Asthan (Kaimur), Chandi Asthan (Munger), Ugratara Asthan (Mahishi, Saharsa), Aami (Saran), Thave (Gopalganj), Tarachandi Asthan (Rohtas), Bakhorapur (Bhojpur), Shyamakali (Darbhanga), Bhagwati Asthan (Nayanagar, Madhepura),</p>

Tourism Segments	Our Strategic Advantage
	<p>Badi Patan Devi (Patna), Chhoti Patan Devi (Patna), Matsyagandha Rakt kali Temple (Saharsa), Uchchait (Madhubani);</p> <p>(f) Sikh Circuit – Patna Sahib (Patna city, Patna), Bal lila Sahib (Patna), Guru Teg Bahadur Gurudwara (Gaighat, Patna), Gurunanak Kund (Rajgir, Nalanda), Ara, Katihar, Gaya and Sasaram, Bhagalpur, Guru ka Bagh (Patnacity, Patna), Gurudwara Pacci Sangat (Munger), Gurudwara Handi Sahib (Danapur, Patna) ;</p> <p>(g) Gandhi Circuit – Motihari (East Champaran), Bettiah (West Champaran), Bhitiharwa Aashram (West Champaran), Vrindavan (West Champaran), Sadakat Aashram (Patna), Gandhi Sangrahalaya (Patna);</p> <p>(h) Shiv Circuit- Guptadham (Kaimur), Baijudham (Gaya), Koteswardham (Gaya), Singheshwardham (Madhepura), Kusheshwar Asthan (Darbhanga), Siddheshwar Asthan (Jehanabad), Ajgaibinath (Sultanganj, Bhagalpur), Ashok dham (Lakhisarai), Garibnath (Muzaffarpur), Mahendranath (Saran), Bramheshwarnath (Buxar) ;</p> <p>(i) Mandar and Ang Circuit – Munger, Bhagalpur and Banka;</p> <p>(j) Kanwariya Route-Sultanganj (Bhagalpur) to Banka;</p>
Culture & Heritage	<ul style="list-style-type: none"> • Bihar has a vast array of protected monuments, world heritage sites and several other sites, like the ruins of Nalanda and Vikramshila (oldest universities in the world), which have the potential of being world heritage sites. • Special heritage zones with converted heritage buildings and suitable activities can be developed, while retaining the originality of the structures • Development and promotion of museums in co-ordination with ASI and other State Government departments to promote our culture. The newly inaugurated “Bihar Museum” is an important attraction. • With a view to promote handloom and handicrafts of Bihar, “Shilp Grams” (Craft villages) and handicrafts market is being promoted near tourist places.
Rural/ Village	<p>Art and crafts of Bihar could help develop and promote rural tourism and extend the socioeconomic benefits of tourism to rural areas. For example, villages engaged in Tehta (Jehanabad), Nepura (Nalanda), Ranti and Jitwarpur (Madhubani), Patharkatti (Gaya), Nathnagar (Bhagalpur) etc. could be targeted for development of rural tourism.</p>
Wellness	<p>“Wellness Tourism” based on yoga and aqua therapy using sulphur water from hot water springs in Rajgir and Munger can be promoted. This has the potential to be Bihar’s most unique tourism offering, with holistic healing and rejuvenation of the individual from every dimension-physical, mental, and spiritual.</p>
Eco and Wildlife	<p>Eco-Tourism could be promoted through integration of wildlife sanctuaries to offer a potential tourist places. Some of the identified tourist places are: Rajgir (Nalanda), Bhimbandh Sanctuary (Munger), Kaimur Sanctuary (Kaimur), Gautam Budhh Sanctuary (Gaya), Naktidham (Jamui), Gogabill Sanctuary (Bhagalpur), Kanwar lake (Begusarai), Ghora Katora Lake (Nalanda), Kakolat Waterfall (Nawada), Telhar Waterfall (Rohtas), Gangetic Dolphin Sanctuary (Bhagalpur) and Valmiki National Park (West Champaran).</p>
Ganga Based	<ul style="list-style-type: none"> • The Ganga has a unique value in terms of tourism and could be

Tourism Segments	Our Strategic Advantage
	<p>leveraged by introducing a cruise along the river, connecting historical sites near its banks such as Patna, Bhagalpur, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dolphin watching is another unique tourism product offered by the state that could be further strengthened.
Adventure	Water sports such as river rafting, para sailing, etc. could be developed to create more economic opportunities.
Fairs & Festivals	Bihar has unique events, fairs and festivals like Sonepur fair, Chath festival, Saurat Sabha, Rajgir festival and Boudh festival, all of which have the potential to attract domestic as well as international tourists, upon development of adequate facilities.
Cinematic	Film shootings at tourist destinations in Bihar should be further encouraged through single-window clearances along with necessary incentives, as provided for under the relevant government notifications.
Cuisine Based	<ul style="list-style-type: none"> • The gourmet trails of Bihar can be promoted to showcase the rich culinary heritage of the state. • The unique cuisines of the state, like khaja, lai, belgrami, tilkut, litti-chokha, sattu, makhana preparations etc. have the potential to generate economic opportunities upon being promoted through organisation of food festivals.

These identified products and circuits, at present, stand largely as green fields for various kinds of infrastructural and service related investments. Apart from these identified circuits there are many other geographical areas of the state which can be developed as future destinations from tourism point of view. Looking at the existing and prospective investment potential, and future growth opportunity along with the capacity to generate large number of employments in various sub-sectors of the tourism industry, the State Government has considered it as one of the thrust areas for the purpose of promotions and facilitations under its investment promotion policy. The policy, therefore, has made provisions to facilitate and incentivize private investment in the sector.

Priority sectors in the tourism sector

The priority sectors of investment in the tourism sector value chain are as follows:

Sectors	Investment Opportunities
Transportation	<ul style="list-style-type: none"> • Taxi operators at tourist places • Cab aggregators/ radio taxis at tourist places • Luxury coaches & cars plying on tourist circuits • Air taxis and helicopter services for the tourist circuits • Special tourist trains, boats, steamers, etc.
Accommodation	<ul style="list-style-type: none"> • Hotels, motels, resorts, guest houses, homestays, etc. within 10 km radius of the identified tourist circuits • Caravans, camping facilities/ tent accommodations, heritage homes, etc.
Tours & Travels	Travel agencies, tour operators, tourist taxis, etc. at tourist places
MICE facilities	Meeting hubs, convention centres, exhibition centres, event organizers, etc. at the tourist places.
HRD Institutions	Hotel management institutes, food craft institutes, travel & trade institutes, manpower training centres, tourist guide training centres, management institutes providing tourism sector related education and trainings, etc.
Souvenir shops	Handicraft shops, souvenir shops, ethnic boutiques, traditional jewellery shops etc. at tourist places

Sectors	Investment Opportunities
Wayside amenity (On the National Highways and State Highways)	Wayside amenity centres, wayside restaurants, snack bars, dhabas, pay-and-use toilets, utility shops, parking areas and shops of handloom and handicraft items produced in the state at tourist places.
Wellness centres	Ayurveda centres, wellness spas, treatment centres, yoga university, etc. at tourist places
River Attraction	Cruise, floating restaurant, floating cottages, water sports (like river rafting, para sailing), recreational facilities (like fishing, dolphin watching) etc.
Entertainment	Amusement parks, water parks, theme parks, craft village, ropeway, science center, museum, planetarium, etc. at tourist places
Cinematic	Film city

Notes:

1. Tourist places under this policy shall mean the places (districts or blocks or villages) mentioned in the above table that lists the various “Tourism segments” and “Our strategic advantage”.
2. Any units (mentioned above) under the tourism sector located in the metropolitan area of Patna shall be excluded from the priority sector related benefits.
3. The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.3. Small Machine Manufacturing Sector.—Agriculture is the mainstay of the economy of Bihar. However, high cost of agricultural practices and low productivity of crops has been an issue. The relationship between agricultural output and input, as compared to many other states of the country/ world and their averages, has been problematic. Among others, provision of irrigation facilities, use of high yielding variety of seeds, use of pesticides and insecticides, use of fertilizers and better techniques of farming, use of modern agricultural machinery and implements, etc. play a vital role in increasing the productivity of agriculture. Thus optimal level of mechanization is an imperative for ushering in the regime of low-cost agriculture in Bihar.

In the recent past, the modern agriculture implements have registered a sharp increase in their presence in the fields of Bihar. The State Government has been providing incentives -- over and above the incentive provided under the centrally sponsored schemes-- for power tillers, tractors, sprayers, winnowing machines, power weeders and power threshers. The focus is on zero tillage machines which are more suitable for farmers with small and marginal land holdings. Because of easy availability of incentive and progressive outlook of the farmers, use of latest equipment is now becoming common in the state. The increase in electrification has led to increase in usage of electrical pumps and electricity based farm equipment. The agricultural implements market in the state is now witnessing a high growth which is poised to further growth in the time to come. Looking at this growing domestic consumption market and the lack of investment in this sector in the state till date, Government of Bihar has categorized the small machine manufacturing sector related to agriculture as one of the priority sectors in the industrial investment promotion policy.

Priority sectors in the small machine manufacturing sector

The priority sectors of investment in the value chain of the small machine manufacturing are as follows:

Sectors	Investment Opportunities
Land/ Seed bed preparation	Tractors, power tillers, levelers, ploughs, harrow, rotavator, cultivator, ridger, dozers, scrapers
Seeding/ planting/ sowing	Drill, seeders, planters, dibblers, trans-planters, seed cum fertilizer drills, zero tillage machines
Spraying and dusting Equipment	Weeders, conoweeders, tillers, sprayers, dusters, mist blowers
Harvesting	Harvesters/ combine harvesters, threshers, potato diggers, reapers, sheller, sickles/ straw reapers,
Post-harvest Equipment	Seed extractors, de-huskers, hullers/ de-hullers, cleaners, graders, dryers, winnowers, trailers, grain bins
Irrigation	Diesel pumps, electric pump-sets, solar pump sets, sprinklers, drip irrigation equipment, HDPE irrigation pipes, etc.
Small machines and components	Ancillary units for automobiles and automobiles components, diesel and electric locomotives related ancillary units, cycle manufacturing
General/ Business Development Services	Research & development facility, quality control laboratory/ testing laboratory, design studio/ prototyping facility, training centre/ incubation centre/skill development centre

Notes:

- The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.
 - Units manufacturing parts/ components that are directly used in other small machines would also be considered under priority sector.
- 3.4. IT, ITeS, Electrical and Electronic Hardware Manufacturing Sector.**—Globally, the IT & ITeS industry, along with the hardware manufacturing sector, is the largest and fastest growing industry in the world. It is expected to reach around USD 2.4 trillion by 2020. The demand in the Indian market is poised to reach more than USD 400 billion by 2020. The importance of IT/ITeS sector is not that of a standalone sector, rather as an integral part of other industries. It has a significant penetration in to all walks of life. It has been established now that the growth in IT/ITeS sector would spur further growth in the fields of agriculture, education, healthcare, energy, telecommunication, rural development, tourism, textile, etc. The sector is yet to take off and move in the desired direction with a pace that offers potential for many entrepreneurial ventures and start up units. The availability of educated youth and cheap labour in the state pose a clear advantage to the investment in this sector, in the state. The State Government has also notified land for two IT Parks at Bihta(Patna) and Rajgir.

Priority sectors in the IT, ITeS, electrical and electronic hardware manufacturing sector

The priority sectors for investment identified by the State Government in this sector are as follows:

Sectors	Investment Opportunity
IT & IT enabled Services	<ul style="list-style-type: none"> IT products, Software and services ITeS such as back office operation/ business process outsourcing (BPO)/ knowledge process outsourcing (KPO),

Sectors	Investment Opportunity
	call centres, digital content development / animation etc.
Electronic Hardware Manufacturing	<ul style="list-style-type: none"> • Computers • Computer peripherals and other office equipment • Server and storage devices • Networking • Automotive electronics • Medical Electronics • Industrial Electronics
Other Electronics Manufacturing	<ul style="list-style-type: none"> • Mobiles, DTH, televisions, radios and consumer electronics.
Electrical Goods	<ul style="list-style-type: none"> • Motors, pumps, fans, consumer durables, UPS etc.

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.5. Textile Sector.—The textile sector plays a key role in the Indian economy by way of significant contribution to GDP, manufacturing output, employment generation, and export earnings. The sector contributes 14% to industrial production, 4% to India's GDP and constitutes 13% of the country's export earnings. The textile sector is one of the largest source of employment generators in India; it employs over 4.5 crore people, directly.

Bihar has ample potential to house textile units and other value chain activities. Silk is the focus product in Bihar, for textile units. Bihar has been famous for the production of silk. Bhagalpur district of Bihar has been a centre of silk fabric manufacturing. Tassar silk of Bhagalpur is an exclusive product of Bihar which has the potential to fetch premium prices. Bihar had produced around 60 tonnes silk during 2014-15.

Jute is another fibre product produced in the state. Bihar produced around 1420 thousand tonnes of jute in 2014-15. A jute park is being establishing in Maranga, Purnea with an investment of INR 42.36 crore, by registered SPV M/s Punrasar Jute Park Ltd. Under PPP mode, the State Government has provided 44.30 acres land as equity and INR 2 crore as a grant. In the jute park, at present, two units M/s Tirupati Commodities Private Ltd. & M/s Punrasar Jute Park Training Centre have been established and are functional. They are producing jute yarn, jute twin, jute cloths and other jute products.

There are 14,000 power-looms in Bihar concentrated mainly in Bhagalpur, Gaya, and Banka districts. Their main products are staple chadar/bed sheets, furnishing clothes, etc. There is a training centre at Nathnagar (Bhagalpur), run by the Ministry of Textiles, where 120 power-loom weavers are trained each year.

Textile industry is a highly labour-intensive industry. Bihar is home of around one lakh weavers for whom manufacturing and dealing with fabric and garment is their livelihood. The presence of weavers' community is, therefore, an important asset base in terms of availability of skilled and semi-skilled workers for textile units. Apart from the regular weaver community, a large number of youths (especially, the female youth) in the state can be employed in the textile manufacturing units which can offer conducive employment opportunities such as sewing, stitching, cutting, and other tailoring requirements.

Priority sectors in the textile sector

The priority sectors for investment identified by the State Government in this sector are as follows:

Sectors	Investment Opportunity
Fibre Production/ Spinning/ Weaving/ Knitting/ Processing	(a) Cotton/ jute/ silk / banana and other natural fibre production (b) Production of man-made fibre and filament (c) Yarn Spinning (d) Powerloom and knitting (e) Yarn and fabric processing
Production of apparel and home textile	(a) Woven and knitted apparel manufacturing (b) Hosiery products manufacturing (c) Saree (d) Carpets and other home textiles
Manufacturing of Technical textile	Production of items under following categories: (a) Agrotech (agriculture, horticulture and forestry etc.) (b) Buildtech (building and construction etc.) (c) Clothtech (technical components of shoes and clothing etc.) (d) Geotech (geo-textiles and civil engineering etc.) (e) Hometech (components of furniture, household textiles & floor coverings etc.) (f) Indutech (filtration, cleaning and other industrial usage etc.) (g) Meditech (hygiene and medical etc.) (h) Mobiltech (automobiles, shipping, railways and aerospace etc.) (i) Oekotech (environmental protection etc.) (j) Packtech (packaging etc.) (k) Protech (personal and property protection etc.) (l) Sporttech (sport and leisure etc.)
Post Processing of Handlooms and Khadi Textile Products	Post production facilities using the handloom and khadi cloth

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.6. Plastic and Rubber Sector.—Plastic and rubber are versatile products used for everything from packaging other products to life sustaining equipment used in hospitals. Accelerated globalization, rapid change in technology and growing consumerism have brought with it sweeping changes and abundant opportunities for plastic industry to grow domestically. A major percentage of the population in Bihar has been engaged in agriculture. Though the land is very fertile, the farmers are affected with problems of low productivity and low return on investment, primarily, due to high dependence on monsoons. Plasticulture applications have the potential to offer them the much needed solution to improve productivity and reduce dependence on monsoons and therefore, drive the demand for plastics. The increase in electricity supply has led to increase in usage of electric pumps and irrigation systems. The distribution pipes for these electric water pumps have increased the demand for plastic pipes. Beyond this, plasticulture offers various benefits like increase in the yield, reducing water losses, cleaner produce due to reduced soil contact, etc. As

per industry estimates, 35-40% of the food products produced in India are wasted due to deficient infrastructure and lack of food processing capabilities. Plastic has applications in packaging which protects the longevity and quality of food. This sector also offers significant potential for growth leading to increase in demand for plastic. The State Government's programme to connect every household with piped water supply would require plastic pipes for distribution of water. This implies that there is potential of growth for the plastic and rubber industry in the state.

Priority sectors in the plastic and rubber sector

The priority sectors for investment identified by the State Government in this sector are:

Sectors	Investment Opportunities
Irrigation Products	Manufacturing of ISI standards PVC/CPVC pipes, emitting pipes, drippers, emitters, valves, fittings, nozzles, UV films, plant protection nets, crates, Hoses etc.
Packaging & Food Storage Products	Packing/ wrapping products for food items like tetra packs, containers, bags, etc.
Water Supply Products	Manufacturing of ISI standards PVC/ CPVC pipes
Electrical Fittings	PVC pipes and electrical fittings.
Automobile Products	Plastic automobile parts
Medical Supplies	Disposable syringes, gloves, blood storage pouches, catheters/ pipes, etc. and plastics used in medical field.
Building Construction	Plastic and rubber components for building construction
Sports and leisure	Manufacture of plastics and rubbers items for sports and leisure
Plastic Testing	Plastic testing laboratories accredited with ISO/IEC-17025 standards

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.7. Renewable Energy Sector.—Bihar, with approximate peak deficit of 669 MW of electricity⁶is significantly dependent on the power supplied by the central generation stations as of now. Currently, the state is majorly dependent upon the conventional sources for electricity generation. The deficit of electricity poses an enormous constraint for all future development including industries. The per capita electricity consumption of the State is approx. 203 kWh⁷, which is still below the national average and the demand will be much higher in the foreseeable future. The state realizes the importance of electricity on the overall economic growth and has initiated steps to address this gap by implementing large power projects which are primarily based on conventional sources, and are in various stages of implementation. These large power projects have long gestation period, while the demand continues to rise; therefore, the state has a unique opportunity to meet this requirement through rapid deployment of modular RE system. Bihar has RE potential of more than 12.559 GW (solar: 11.2 GW,

⁶ In 2014-15

⁷ In 2014-15

biomass gasifier/ co-generation: 619 MW, bagasse co-generation: 300 MW, wind power: 144 MW, waste to energy: 73 MW etc.)⁸which is yet to be harnessed. Further, there is a potential consumption market for solar off-grid applications such as SPV pumps, solar water heaters, solar street lights, etc. This presents an enormous opportunity to the industries, for setting up units for RE modular product manufacturing, RE projects, etc.

Priority sectors in the renewable energy sector

The following kinds of facilities/ units would be considered under the priority sector:

Sectors	Investment Opportunities
Solar Power	Solar photovoltaic and Solar Thermal Power Generation, Solar Hybrid Systems and Solar applications in Domestic and Industrial Sector.
Bio-mass	Biomass and Biogas projects, Biomass Hybrid Systems and biomass applications in Domestic and Industrial Sector.
Hydel Power	Small Hydropower projects (up to 25 MW)
Others	<ul style="list-style-type: none"> Co-generation in sugar and other industries, Waste to Energy projects including municipal solid waste, industrial waste etc. based energy projects, Wind power projects, RE modular product manufacturing

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.8. Healthcare Sector.—Bihar is the third most populous state in India, with a population density of 1,106 persons per sq. km. The major health & demographic indicators of the state, like the infant mortality rate (42), maternal mortality rate (219), total fertility rate (3.5), etc. are much higher than the all India levels and presents an enormous opportunity to the investors to play a major role in improving these indicators. The public health facilities in Bihar are already overburdened and are in the process of being strengthened in terms of infrastructure and essential health requirements like manpower, equipment, drugs and consumables. Hence, these facilities are not adequate to cater to the health care requirements of the population, at present. An overview of the healthcare related infrastructure requirement and gaps is presented in the table given below:

Particulars	Required	In position (Functional)	Shortfall
Medical colleges and hospitals	40	9	31
District hospitals	38	36	2
Sub-divisional hospitals	212	44	168
Referral hospitals	70	57	13
Community health centres	838	0	838
Primary health centres	3,314	533	2,781
Additional primary health centres	2,787	1,350	1,437
Health sub centres	20,997	9,729	11,268

Besides, there are very few private hospitals in the state; most of the organised private healthcare infrastructure is confined to the capital town, Patna. Patients seeking secondary & tertiary healthcare services have to go to Patna or move to other states for treatment. Also, most of the healthcare needs of the state are being provided by the nursing

⁸ MNRE Annual Report, 2015-16

homes, run mostly by individual private practitioners, which mostly cater to the general healthcare needs of individuals. Very few of these provide speciality services. Therefore, there is a great need and substantial opportunity for private sector interventions in healthcare industry of the state.

Priority sectors in the healthcare sector

To reinforce the State Government’s vision to improve accessibility to affordable, quality healthcare services and promote medical tourism in the state, the following components have been identified as priority sectors:

Areas	Investment Opportunities
In-patient Health Care Facilities	Specialty hospitals, super-specialty hospitals, multi- specialty hospitals, ultra-modern trauma centres
Emergency Medical Services	Mobile medical units, blood banks
HRD/Skill Development Services	HRD/ skill development centres (hospital services, bio-medical equipment maintenance etc.)
Manufacturing Units	Medicines
Manufacturing Units-Equipment & Supplies	<ul style="list-style-type: none"> • Medical equipment like patient monitors, anaesthesia machine, surgical microscope, electro-surgical equipment etc. • Service equipment like blood collection tubes, gloves, catheter, urology disposable products, mouth piece for endoscopes, etc.
Hospital Waste Management services	Bio-medical waste management units
Educational Institutes	Grade A Nursing Colleges

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.9. Leather Sector.—Leather sector has a massive potential for employment, output growth and export. In India, the sector is one of the top foreign exchange earners. Bihar has a huge potential for investment in the leather sector. On account of large raw material base (in terms of hides and skins produced in the state), plenty of cheap as well as skilled and semi-skilled labour, and a huge domestic market for consumption, it offers both comparative and competitive advantage to a prospective investor in this sector. Our strategic advantages in this sector across factors of production are as follows:

Key Factors	Our Strategic Advantage
Availability of Raw hides and skins	<p>(a) Bihar has approximately 8% of the country's total bovine population. According to the livestock census of 2012, the total livestock population in Bihar was 329.38 lakh. As per the census, the cow population was 122.31 lakh and that of buffalo was approx. 75.67 lakh. The goat population stood at 121.53 lakh. Bihar accounts for nearly 12% of the country's total goat population, ranked 3rd in the country. These figures will improve when a new census would take place in 2017.</p> <p>(b) According to a recent survey conducted by the Central Leather Research Institute (CLRI), Chennai, Bihar annually produces 2.64 million bovine hides and 5.09 million bovine skins. The state is known for best quality goat skins, cow hides and buffalo’s calf skins.</p>

Key Factors	Our Strategic Advantage
	<p>Goat skins are smaller in size and the best material for the production of glazed kid's leather products, which are mostly exported.</p> <p>(c) According to a rough estimate, 3 trucks loaded with 7-8 thousand pieces of goat skins and 2-3 thousand pieces of cow hides are transported from Muzaffarpur to other destinations, daily. The leather units in the state export raw materials to Kolkata, Kanpur and Chennai, depriving Bihar of the benefits.</p>
Availability of Labour	<p>(a) Leather industry is a highly labour intensive industry. The small scale, cottage and artisan sectors account for over 75% of the total production from this industry and a majority of them belong to the unorganized sector. The main strength of these unorganized small cottage units has been the availability of the cheap labour, mostly from the weaker sections of the society. Women employment is predominant in leather industry with about 30% share.</p> <p>(b) Bihar, on account of its large, growing population is one of the largest labour base in the country.</p> <p>(c) At present, there are existing pockets in the state, in the districts of Patna, Gaya, Nalanda/ Biharsharif, Muzaffarpur, etc. where artisans are involved in the production of leather footwear. Thus, there is availability of skilled labour who can be readily employed in the leather units.</p>
Availability of Domestic Market	<p>Almost all the goods produced by the leather sector are daily use items. Thus, the consumption rate of these products is very high. The large population of Bihar comprising of growing middle class, in both urban and rural areas, creates a significant local demand for the products. A leather unit established in the immediate neighbourhood of such big markets would, therefore, enjoy both the advantage of scale and cost cuttings.</p>

Priority sectors in the leather sector

The leather industry mainly includes units that are involved in production of finished or semi-finished leather and manufacturing of various kinds of leather goods. The state govt. has a clear focus to promote all the facilities in the value chain, from raw material processing to finished-goods manufacturing. The following kinds of facilities/ units would be considered as under the priority sectors:

Sectors	Investment Opportunities
Manufacturing of leather products	<p>(a) Manufacturing of leather shoes, leather chappals, and other footwear items of leather</p> <p>(b) Manufacturing of leather footwear components</p> <p>(c) Manufacturing of leather garments</p> <p>(d) Leather for upholstery</p> <p>(e) Manufacturing of leather goods (for e.g. labels, tags, belts, bags, purses hand gloves & other accessories and fashion items)</p> <p>(f) Manufacturing of upholstery for automobile (cars, etc.) & furniture</p> <p>(g) Manufacturing of saddlery and harness items</p>
Storage/Warehousing	<p>Modern warehouses for storage of raw hides and skins with or without temperature control/ refrigeration arrangements, finished and semi-finished leather and other leather goods</p>
Business Development Services	<p>R&D facilities, design studios/ facilities for prototyping, quality testing, labs, etc.</p>

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

Apart from these, the GoB would strive for the promotion of rural technologies developed by CSIR-CLRI. Units using these technologies would be treated as apriority sector for incentivising purposes. Following is the list of important rural technologies developed by the CSIR-CLRI.

- Leather Mojari/Jooti footwear
- Leather Kolhapuri footwear
- General footwear (shoes)
- Leather footwear (sandals/chappals)
- Leather puppets manufacturing
- Leather goods
- Leather board
- Collection of fallen carcasses and their utilization

Note: The above list is only indicative and the State Government may take suitable decision with regard to inclusion of any other kind of technology in the list.

3.10. Technical Education Sector.—Bihar, at present, has 13 universities along with 262 government colleges and 231 local body colleges affiliated to the State Government However, the number of institutes for technical education are limited and there are only 10 colleges for engineering and technical education. Because of lack of institutes of higher education and learning in Bihar, thousands of students migrate from the state to other states like Delhi, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Punjab and Rajasthan to pursue their college and university education. This leads to missed opportunities for the state as a hub for higher education. As many as 25 districts out of 38 in Bihar are educationally backward.

Govt. of India has pegged the target for GER at 30% for higher education, by 2017. This would drive massive investments in the sector. At present, Bihar has a GER of 13%. According to an estimate, the state needs 373 general colleges (arts, science and commerce), 236 engineering colleges, 139 medical colleges, 253 education colleges and 163 polytechnics to attain the national levels of enrolment in higher education. It is, therefore, obvious that there is potential for newer institutes of higher learning in the state. Despite the high poverty levels in Bihar, most of the families, even in rural areas, send their children outside of Bihar for higher education and bear the additional financial burden of outstation travel and accommodation. Hence, if more institutes come up in the state, there would be enough demand for them to flourish. The education sector would also help in employment generation in the state as most of the higher education institutes would result in establishment of educational townships with facilitation of daily needs of its residents. Hence, there would be creation of many opportunities for small business owners and young entrepreneurs.

Priority sectors in the technical education sector

In the technical education sector, the following facilities/ units would be considered under the priority sector:

Sectors	Investment Opportunities
Technical Education	Engineering colleges and polytechnic institutes (registered under the AICTE Act)
Skill Development	Technical skill development centres imparting training with high end equipment and empanelled by BSDM or Department of Industries,

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

4. Ease of Doing Business Reform

4.1. Introduction.—The Government of Bihar is committed to establish a conducive environment for the entrepreneurs in the state, in order to attract investments and create substantial jobs opportunities. A series of measures have been taken up to improve the ease of doing business in the state and the emphasis has been on simplification and rationalization of the existing rules/procedures for hassle free entry & operation of business units across the state. A brief summary of some of the key ‘ease of doing business’ reforms is given below:

4.1.1. Availability of Information

- a) The ‘**Udyog Samwad Portal (www.udyog.bihar.gov.in) – A one stop platform for investors**’ provides information on acts/rules/policies/ circulars/notices/notifications published by all relevant departments of the state.
- b) Detailed procedures/ guidebooks covering all applicable steps, from application submission to application approval, have been published online to facilitate investors in their application process
- c) A comprehensive checklist of all the documents that need to be submitted as part of the application has also been made available on the websites.

4.1.2. Institutional strengthening to catalyse industrial development

- a) The Udyog Samwad Portal (www.udyog.bihar.gov.in) – A one stop platform for investors, also facilitates grievance redressal. This platform provides an option to directly interact with the Principal Secretary, Department of Industries.
- b) Empanelled professional project management agencies (PMAs) in the food processing sector could facilitate speedy project appraisal and clearances
- c) Defined punitive actions on non-compliance of services are covered under Bihar Right to Public Service Act
- d) Application process and documentation requirement along with reduced timelines for various clearances such as electricity connection, VAT registration, professional tax registration, etc. have been simplified.

4.1.3. Labour related reforms.—Some of the key labour related reform measures undertaken by the State Government are:

- a) Online application for registration and licenses (including renewal) under the Factory Act & other labour laws.
- b) Application tracking facility & clear timelines mandated for issue of registration certificates and licenses including online facility to download the registration certificate & other licenses
- c) Single joint inspection and single annual return for various labour laws
- d) Online facility for verification of registered and licensed units
- e) Well defined inspection procedures, including online risk based differential compliance inspection of registered units including automatic allocation of inspectors, etc.

4.1.4. Tax Related Reforms.—Some of the key tax related reform measures undertaken by the State Government are: -

- Online application for Value Added Tax, Professional Tax, Entry Tax, Entertainment Tax& Luxury Tax registration

- Application tracking facility & clear timelines mandated for issue of registration certificates
- Online facility to download registration certificates and enquiry reports
- Online facility for verification of registered and cancelled dealers
- VAT refund to the dealers account within 60 days
- Computerized system to identify dealers for audit (based on publically notified risk parameters)

4.1.5. Environment Related Reforms.—Some of the key environment related reform measures undertaken by the State Government are:

- Online consent management system for Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under Water & Air Act; authorization under Hazardous Waste Rules
- Application tracking facility & clear timelines mandated for issue of CTE/CTO/authorization certificates including online facility to download certificates
- Industries under Green category exempted from obtaining CTO & CTE
- Validity of CTO increased from 3 years to 5 years
- Lowered compliance inspection requirement—Green: once in 5 years, Orange: once in 3 years & Red: once in a year)

4.2. Way forward.—Reform measures will be taken to streamline procedures across departments so that the investors would be able to obtain statutory clearances and approvals in a transparent and time-bound manner. The following steps will be taken to facilitate ease of doing business in Bihar:

- **Single Window Clearance System:** A new and simplified system of single window clearances will be put in place with suitable changes in the legislative framework. The online system will also provide facility for online application, adjustment and reimbursement of incentives.
- **Provision of Common Application Form (CAF):** A Common Application Form (CAF) will be introduced which will ensure coordination among all agencies involved in providing clearance. CAF will be web-based and will gradually be aligned to the Government of India's e-biz portal (www.ebiz.gov.in) so that prospective investors can obtain all clearances from one source.
- **Provision of Programme Management Agency (PMA):** The DoI will empanel PMA(s) to provide technical assistance as well as secretarial services to the competent committee in finalising the investment proposals for the approval including monitoring and reporting the progress. The PMA(s) will be the single point of contact for the investors to coordinate with the government for their investment proposals.
- **Amendment in the BIADA Act:** The GoB will review the existing Bihar Industrial Area Development Authority Act, 1974 and amend it to further strengthen the legal framework for planned development of industrial areas.
- **Inclusion of industry related services under the Bihar Right to Public Services Act, 2011:** In order to ensure accountability for timely processing of requests, additional investor-related services will be included under the Bihar RTPS Act.
- **Provision of Self certification:** The new single window system will have provisions for self-certification with random check by the statutory authorities after commencement of production.
- **Rationalisation of rules & regulations:** Considerable rationalization of labour law compliances has been implemented in the

state. However, a further review in order to possibly ease compliances will be conducted, in consultation with industry representatives.

- **Monitoring & Grievance Redressal System:** The grievance redressal in regard to this policy will be done under the purview of the Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhikar Adhiniyam, 2015. Additionally the DoI will strengthen the existing web based interaction mechanism (www.udyog.bihar.gov.in) where suggestions and complaints can be directly addressed to the Industrial Development Commissioner/Principal Secretary, Industries Department.

5. **Enabling Infrastructure for Industrial Investment**

- 5.1. **Introduction.**—Facilitation of high-end quality infrastructure facilities, including developed industrial land, availability of quality power, efficient transportation network, etc., is the prime focus of the current policy. These infrastructure facilities are keys to the growth of business and industry in the state. Following is the brief of the existing infrastructure in the state.

Particulars	Description of Existing Infrastructure
Industrial Land	<p>(a) Bihar is one of the largest states of the country in terms of land area. Its total geographical area is around 93.6lakh hectares. Because of its topographical nature, the proportion of total land put to agricultural use is high as compared to other states of India. Out of the total land area of the state, around 57% is under agriculture. Looking at the facts that agriculture is the mainstay of the economy and that the population of the state needs land for residential and other uses, it has been a challenge for the government to be able to carve out land for industrial uses or to convert open lands to industrial lands.</p> <p>(b) BIADA is the key agency for allotting lands/ industrial plots to the prospective units in Bihar. BIADA has four regional offices at Patna, Darbhanga, Muzaffarpur and Bhagalpur. At present, there are 50 Industrial Areas (IA)/ Industrial Estates (IE)/ Large Industrial Estates (LIE)/ Growth Centres (GC)/ Mega Industrial Parks (MIP) under the purview of BIADA.</p> <p>(c) Up to Dec. 2015, BIADA had acquired a total of 5851 acres of land, of which 3324 acres have been allotted to the investors. After allocating the land for infrastructure, 182 acres of vacant land is available at various industrial areas. BIADA to preferably allot lands to manufacturing units.</p> <p>(d) BIADA allots the land in an industrial area after developing necessary infrastructure like roads, power, water and drainage facilities, etc. As on Dec. 2015, 1544 industrial units were in operation in various industrial areas.</p> <p>(e) The State Government has given approval to setting up of industrial units in parks that have industrial plots available for allotment to investors. These are:</p> <p>a. Pristine Mega Food Park.—The Park is coming up in Khagaria district. It is spread over an area of 98 acres. The park is likely to be operational by this financial year.</p> <p>b. Punraser Jute Park.—This is the country's only jute park. It is situated in Purnea district. It is spread over an area of 44.30 acres. The park is operational at present.</p> <p>c. IT, ITeS and Electronic Manufacturing Park.—The State Government has earmarked around 100 acres in Rajgir and 25 Acres in Bihta (Patna) for an IT, ITeS and Electronic Manufacturing Park.</p>

Particulars	Description of Existing Infrastructure
	<p>d. Leather Cluster.—It is situated in Muzaffarpur with about 11 acres of land.</p> <p>e. Garment Manufacturing Park.—It is situated in Bihta (Patna) having 25 acres of land.</p> <p>All these parks have well developed infrastructural facilities for setting up of an industrial unit.</p>
Power	<p>(a) The installed power capacity in Bihar was 3704.63 MW in March, 2015. Out of this, 83.5 percent is coal based thermal power, 14.12 percent is hydro power, and the remaining 2.3 percent is renewable energy.</p> <p>(b) In terms of ownership, central sector has the largest share, i.e. 77.9%, followed by the private sector/ IPPs (14.7%) and the state sector (7.4%).</p> <p>(c) The State Government has entered into short term, medium term and long term contracts for power purchases so that power availability does not remain a problem for the state. Due to increased availability of power, the per capita consumption of power in Bihar has risen from 145 kWh in 2012-13 to 203 kWh in 2014-15, implying a growth of about 40% in two years, which is the highest among states in the country.</p> <p>(d) There are 13 minor hydel projects that are currently operational in the state, with a total installed capacity of 54.3 MW. Presently, Bihar State Hydroelectric Power Corporation (BSHPC) is also engaged in exploring the possibilities of bringing up more such minor hydel power projects in the state. There are 17 schemes under which exploration work is in progress.</p> <p>(e) The GoB has allowed open access for purchase of power in the state. It has also allowed the net metering arrangement for grid connected solar rooftop photovoltaic systems and has made regulations in this regard. Further, it has also notified the provisions for banking of solar power for captive use, group captive use, and for third party sale.</p>
Road	<p>(a) At present, the total road length in Bihar is around 2.26 lakh km. Out of this, the total length of NH is around 4595 km. Approximately 68% of NHs are double and multiple lane roads and the rest 32% single and intermediate lane roads.</p> <p>(b) The total length of the State Highways (SH) in Bihar is around 4253 km. Out of this approx. 65% is double-lane, 20% is single-lane and 15% is intermediate-lane road.</p> <p>(c) The state has a vast network of district roads also. The total length of Major District Roads (MDR) in the state is around 10,634 km with a major portion (54%) having a width of 3.75 meters. Out of the total length of MDR, 4897 km have been converted into intermediate or 2-lane width. Those roads which are yet to be converted into wider roads, have undergone surface renewal or repair work. The State Government is making endeavours to upgrade 5175 km of MDR to a minimum standard of intermediate lane with 5.50 meters width.</p> <p>(d) At present, the state has around 2.07 lakh Km. of rural roads. All the rural roads are being gradually upgraded to pucca roads, under different schemes like Mukhya Mantri Gram Sampark Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Grameen Tola Sampark Nischay Yojna.</p>

Particulars	Description of Existing Infrastructure
Railways	<p>(a) Bihar has an extensive railway network of 3,638.73 km. All the districts of the state are well connected to the rail network. Almost all the districts of the state are connected with major cities of the country through the rail network.</p> <p>(b) There are two major rail routes passing through the state:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Delhi –Guwahati Rail Route via Chapra-Barauni-Katihar ii. Delhi-Kolkata Rail Route via Ara, Buxar, Patna, including Grand chord line via Gaya <p>(c) Hajipur in Bihar is the HQ of the ECR. The ECR commands a vast network of 5230 track kilometres and 3624 route kilometres spread across the states of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.</p> <p>(d) Quite recently, 3 major projects for rail-cum-road bridge have been commenced in Bihar at an estimated cost of INR 7000 crore. These rail-cum-road bridges would contribute in consolidating the transportation across the state.</p> <p>(e) The state is also speeding up on execution of the Patna metro rail project. State Government has already prepared the detailed project report (DPR) for the metro rail project and has also given it the in-principle approval.</p>
Air way connectivity	<p>(a) Bihar has one domestic airport in Patna and one international airport in Bodh Gaya. Several domestic airlines connect Patna to Delhi, Kolkata, Mumbai, Lucknow, Bengaluru, Hyderabad and Ranchi.</p> <p>(b) The number of aircraft movement in Bihar has increased to 11054 in 2014-15. Over the past two years, the number of passengers increased from 10.5 lakh to 12.0 lakh and freight also increased from 4849 tonnes to 5198 tonnes.</p>

5.2. Measures for creation of enabling infrastructure during the policy period.—In order to strengthen the existing infrastructure situation in the state, the government has proposed the following measures during the policy period:

5.2.1. Allotment of vacant industrial land for priority sector projects.—During the policy period, BIADA would strive to allot all the available vacant land (around 182 acres) at the various industrial areas to the prospective and eligible projects. In this regard the meeting of “Project Clearance Committee of BIADA” will be convened in a time bound manner. These vacant lands shall be allotted to the manufacturing units. The Government would also put efforts to facilitate the allotment of lands in the industrial parks to manufacturing units.

5.2.2. Establishment of new industrial areas and expansion of existing industrial areas by BIADA

(a) BIADA would strive to develop new industrial areas as well as expand existing industrial areas across the various districts of the state. It is envisaged that a total of 5000 acres of land would be acquired and developed by BIADA over the next 3 to 5 years/ during the policy period. For this, government land from the land bank would be alienated and transferred to BIADA. Appropriate budget provisions would be made for the development of the new industrial areas. BIADA would develop the land suitable for industrial manufacturing units and notify the final rates at which the land would be available to industrial units.

- (b) As a policy decision, lands in industrial area controlled by BIADA shall be used only for the allotment to the manufacturing units. BIADA has notified the objective criteria for the allotment of land in the industrial areas. It has also issued a notification for earmarking industrial areas on the basis of criteria like type of industries and pollution level. The State Government may notify from time to time the kind of industry that can be allotted land in the industrial area controlled by BIADA.
- (c) As a policy decision, 25% of the land in a newly established industrial area by BIADA would be allotted to the MSME units. Out of these 25% allotted to MSME units, 75% will be for Micro & Small enterprises and 25% will be for Medium enterprises.
- 5.2.3. Recovery of land from Sick/ Closed units.**—Wherever feasible, the Govt. would strive to recover land from sick and locked out industries, more so in the existing industrial areas. BIADA may also formulate a suitable “One time Settlement” process for this.
- 5.2.4. Promotion of private participation for increasing availability of industrial land: “Aao Bihar” Scheme**
- (a) “Aao Bihar” Yojana is a flagship scheme of the Government of Bihar to facilitate private buyers and sellers of land in respect of setting up of industrial units in the state. The scheme was launched in 2011.
- (b) Under this scheme any person/ group of persons, who own 2 acres or more land and want to sell their land for establishment of industries or institutions, can enlist their land details on the “Aao Bihar” Portal. The information shall be made available to prospective buyers on the website. Entrepreneurs interested in buying land can locate the land on the portal. The State Government through its machinery shall help the entrepreneur to verify the title and ownership of the land so as to enable the buyer to buy the land.
- (c) The role of govt. would be that of a facilitator only. It would not have any role in fixing the rates of the land and in the allotment of the land.
- 5.2.5. Establishment of Air cargo complex.**—An air cargo complex has been proposed in the state in Patna/ Gaya for products of export oriented industrial units and transportation of perishable agriculture goods from the state. The government would strive for its establishment during the policy period.
- 5.2.6. Container Freight Terminal.**—There are two container freight terminals in the state at Fatuha & Bihta. The GoB would pursue to upgrade the facilities available at these terminals.
- 5.2.7. Promotion of Amritsar Kolkata Industrial Corridor & IMCs.**—The Government of India has proposed to develop the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor along the Eastern Dedicated Freight Corridor. The proposed AKIC passes through three districts of the state viz Gaya, Jamui and Banka. The GoB would pursue to develop the influence area as an industrial hub. For this, the GoB would assess the infrastructural needs in the influence area and formulate a suitable intervention plan. As of now, GoB has shortlisted a location near, Dobhi, Gaya District for an IMC.
- 5.2.8. Increase in the availability of quality/reliable power supply**
- (a) At present, the work is in progress for four more generating units in Bihar that have been listed below. On completion of all these projects, the dependence of Bihar on the central sector for power will be lessened.

- i. **Nabinagar Stage-1 Plant.**—This project is located in Aurangabad district of Bihar. For this power project, construction works of three units of 660 MW each is in progress.
 - ii. **Power Projects in Buxar, Bhagalpur and Lakhisarai.**—An agreement has been signed with Satluj Hydro Electric Corporation for the construction of power project at Chausa (Buxar), having two units of 660 MW, each. In addition, an agreement has also been signed with NHPC and NTPC for the construction of two thermal power plants of 660 MW, each. The plant in Pirpainti (Bhagalpur) will be constructed by NHPC and that in Kajara (Lakhisarai) by NTPC.
 - iii. **Ultra-Mega Power Project (Banka).**—A proposal has been sent for the establishment of a power project in Banka (approximately 4000 MW), for which 2500 acres of land has been identified.
 - iv. **Mathauli Hydel Power Project (West Champaran).**—The construction work for this power project is nearing completion. It would have a capacity of 800 KW.
- (b) Efforts will be made to ensure availability of 24 hours of uninterrupted power supply to the industries situated in all industrial areas. All the industries getting electricity supply from 132/220 KVA feeders, will be exempted from power cuts, until necessary for safety of the grid. For this purpose, generation and distribution systems will be adequately upgraded.
 - (c) All such feeders of 33/11 KVA substations, which have more than 75 per cent industrial load, would be recognized as industrial feeders and exempted from power cuts. If consumers of other categories are connected to these feeders, then steps would be taken to separate them.
 - (d) **Open Access Policy.**— The State Government shall allow power under the Open Access Policy as per the Electricity Act, 2003. This shall allow large users of power — typically having connected load of 1 megawatt (MW) and above —to buy cheaper power from the open market. It would help industry buy power at competitive rates and be competitive in the market.

5.2.9. Establishment of gas pipeline network.—To ensure availability of natural gas as clean energy for industrial development, a gas grid will be developed in the state; necessary steps will be taken to ensure the supply of natural gas according to industrial and domestic demand in the state.

The Government of Bihar would coordinate with GAIL and other oil companies engaged in laying the proposed natural gas pipeline network from east coast of the country. Efforts would be made to make gas available through pipelines to maximum areas, especially to industrial locations. MoUs have been signed between GoB- IOC and GoB- GAIL to establish a gas pipeline network in the state. The main gas pipeline of GAIL shall pass through Gaya, Aurangabad, Rohtas and Kaimur districts of Bihar.

5.2.10. Promotion of MSME Clusters – Establishment of CFCs.—

- (a) The current industrial policy adequately recognizes the importance of the development of the MSME clusters; therefore, intends to promote them. There are several existing and potential MSME clusters in the state. For e.g.
 - i. Brass and Bronze Metal Utensils Industry Cluster, Pareb, District- Patna
 - ii. CFL & LED Bulb, Patna city, District- Patna

- iii. Leather Footwear, Patna city, District- Patna
 - iv. Makhana, Located in four district (Darbhanga is the key center)/ Darbhanga
 - v. Leather Products Cluster, District- Chappra
 - vi. Agarbati Manufacturing Cluster, District- Gaya
 - vii. Lahathi (lac) Cluster, District- Muzaffarpur
 - viii. Leather Shoes and Chappal Cluster, District- Muzaffarpur
 - ix. Brass & German Silver Utensils Cluster, District- West Champaran
 - x. Rice Milling Cluster, District- East Champaran
 - xi. Rice Milling Cluster, District Lakhisarai
 - xii. Copper Bronze Alloy Utensil Cluster, District Vaishali
 - xiii. Leather Shoes and Chappal Cluster, District-Nalanda
 - xiv. Readymade Garment Cluster, Patna city, District- Patna
 - xv. Silaw ka Khaja Cluster, District- Nalanda
 - xvi. Sweet and Namkin Khaja Cluster, District-Madhepura
 - xvii. Bamboo Works Cluster, District Madhepura
 - xviii. Handloom and Khadi (Post processing) Clusters
 - xix. Handicraft Clusters
 - xx. Small Machines and tools manufacturing Cluster in Aurangabad and Raxaul, East Champaran
- (b) None of the existing, new or potential clusters have adequate facilities. Primarily, in terms of CFC. The cluster actors are also technologically poor and there is a dire need of technology and skill upgradation in these clusters.
 - (c) In order to promote the cluster, the GoB had launched a special scheme named “Chief Minister MSME Cluster Development Scheme” in the year 2013. The Government would strive to implement this scheme effectively during the current policy period.
 - (d) The State Government would also extend all necessary support to a cluster of industries under the relevant schemes of Government of India viz Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme of Ministry of MSME and Industrial Infrastructure Upgradation Scheme of Department of Industrial Policy & Promotion, GoI.

5.2.11. Promotion of Private Industrial Parks.—

- (a) The current policy adequately recognizes the role of private participation in order to develop industrial plots/ land and other basic infrastructure facilities in the state.
- (b) To encourage private participation, the Government of Bihar had launched the “**Policies for Private Industrial Park**” in 2013. This policy would be treated as an integral part of the current industrial policy and the government would strive to implement this scheme effectively during the current policy period subject to certain revisions/ amendments. The government would also encourage the establishment of sector specific parks, especially, for the priority sectors (e.g. food parks, leather parks, IT parks, textile parks, etc.)
- (c) Under this policy, the Government of Bihar would provide incentives to the promoters of private industrial parks. A detail guideline about the incentives available to the private industrial parks and terms & conditions are furnished in chapter 6 (Section 6.7).

6. General Package of Incentives.—Government of Bihar recognizes the need of fiscal incentives to improve the competitiveness of the units operating in the state. Accordingly, Government of Bihar has formulated a customized package of fiscal incentives

which takes into cognizance state's comparative advantages and will trigger the next round of industrial growth in the state.

6.1. Guiding Principles/ General Provisions

- (i) These general provisions shall be applicable to all units eligible under this policy.
- (ii) Effective date means the date on which the provisions of this policy come into force. This policy will remain in force for 5 years from the effective date.
- (iii) The state would encourage the prospective promoters to avail term loan facility from the scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI for setting up a unit and availing incentive on the investment.
- (iv) Unit applying for incentives shall provide a Detailed Project Report (DPR) accompanying the Bank Appraisal Report prepared by the scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI, which is supposed to extend the term loan to the unit. The appraisal report prepared by the bank/ financial institute shall form the basis for ascertaining the project cost for calculation of incentives.
- (v) For the purpose of calculation of incentives under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the competent authority as defined by the Department of Industries from time to time. The approved project cost shall be the basis for determining the incentives.
- (vi) In the approved project cost considered for incentive calculation under this policy, the cost of land shall not exceed a limit of 10% of the total proposed investment other than the land. Thus in the approved project cost either the actual cost of land mentioned in the project report assessed by the bank/ financial institutions or 10% of the total proposed investment excluding the land, whichever is less, will be considered. This principal shall be followed for examining all investments under this policy.
- (vii) All incentives mentioned under this policy shall be provided post-production i.e. after the date of commercial production/ operations.
- (viii) In case of SC/ ST entrepreneurs, the maximum limit of all kinds of incentives (except for land) shall be increased by additional 15% across all categories (i.e. MSME & large units). For more details, please refer to Section 6.4.
- (ix) In case of women, differently abled entrepreneurs, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the maximum limit of all kinds of incentives (except for land) shall be increased by additional 15% across all categories (i.e. MSME & large). For more details, please refer to Section 6.5.
- (x) A unit will not get any incentive beyond a period of 5 years from the date of commencement of commercial production or 5 years from the date of end of this policy, whichever is earlier.
- (xi) The incentives will cease either on the exhaustion of the applicable quantum or on the completion of the eligible period, whichever is earlier. Any unutilized incentive at the end of eligibility period shall lapse.
- (xii) Any incentive under any other scheme/policy of the State Government or Central Government availed by a unit will not be considered for calculating the total accruable incentives to the unit.
- (xiii) In the event of change in ownership or management of a unit, the same shall be intimated by the unit to the competent authority as defined by the Department of Industries from time to time. If

- required, a revised Letter/ Eligibility Certificate shall be issued to the unit (in the name of new owner) for balance incentives. The eligibility period shall not be extended under any circumstances and shall continue to be defined with effect from the original date of production.
- (xiv) In the event of any change in the shareholding pattern of a unit promoted by SC/ST/ women/differently abled persons/ war widows/ acid attack victims/ third gender entrepreneurs within 5 years of start of the commercial production, the new shareholders should be from the same category. In case the new shareholders are not from the same category, the amount of incentive extended to such units shall become liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum.
 - (xv) If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if any incentives are availed for a unit that was not eligible, the amount of incentives are liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.
 - (xvi) Any attempt to break/ divide or merge units only for the sake of availing higher amount of incentive without substantial operational reasons shall be treated as misrepresentation of facts and will attract penal action as decided by the competent authority.
 - (xvii) Any existing or new units, expanding its capacity, diversifying, or modernizing during the policy period will be given the benefits as applicable to new units on their incremental approved project cost. To avail the benefits, there must be a capacity expansion/modernisation of at least 50% of the capacity of the existing unit.
 - (xviii) Negative list of industries/sectors which shall not be eligible for any incentives under this policy are stated in“Annexure II - Negative list of industries”. These industries/sectors shall not be eligible for any incentive, including under the GST regime.
 - (xix) All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Industrial Development Commissioner/ Principal Secretary, Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final.

6.2. Package of incentives.—State Government is committed to encourage the process of industrialization by assuring an entrepreneur-friendly regime and an attractive package of incentives for the entrepreneurs. The following package of incentive will be made available to the entrepreneurs:

Type of Incentive	Salient Features
<p>1. Reimbursement Stamp Duty/ Registration</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) No stamp duty to be paid in respect of land allotted by the government to IDA/ BIADA. b) 100% reimbursement of stamp duty/registration fees levied on lease/ sale /transfer of industrial land/shed as also those outside the jurisdiction of Bihar Industrial Area Development Authority would be available to all the new units after the unit commences the commercial production. This reimbursement of stamp duty and registration fees will be granted only for the first time and will not be applicable in subsequent stages of lease/sale/transfer. This incentive will be available to new units only. c) The area of land required by the unit shall be fully described in the DPR and the Bank Appraisal Report prepared by the bank

	or financial institution which is supposed to extend the term loan to the unit.
2. Land Conversion Fees	a) 100% reimbursement of “land conversion fees”/ “change in land use” fees being levied for conversion of agricultural land after the unit commences the commercial production.
3. Interest Subvention	<p>a) State shall extend “Interest Subvention” to all the eligible units on the term loan availed by the unit from a scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI.</p> <p>b) Rate of interest for interest subvention will be 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower. For micro and small units, there shall an interest subvention of 12%.</p> <p>c) The overall limit of this subvention for priority sector units will be 30% of the approved project cost. The subvention limit for non-priority sector units shall be 15% of the approved project cost. The upper limit of this subvention shall be Rs.10 crore.</p> <p>d) Disbursement of the subvention amount would be in instalments linked with the term loan repayment schedule stipulated by the concerned bank/financial institutions which extends the term loan to the unit. Interest shall not be paid on promoter’s contribution in any form in the unit.</p> <p>e) In case the promoters do not avail any term loan for the unit, they would not be eligible for this incentive.</p>
4. Tax related incentive	<p>a) All new units can avail tax related benefits with a maximum limit as defined below:</p> <p style="padding-left: 20px;">i. Non-priority sector: 70% of the approved project cost</p> <p style="padding-left: 20px;">ii. Priority sector: 100% of the approved project cost</p> <p>b) All new micro and small units will be given tax benefits by additional 30% of the approved project cost.</p> <p>c) All units engaged in generation of solar and/ or renewable energy for commercial purpose will be given tax benefits by additional 30% of the approved project cost.</p> <p>d) All new units will be entitled to avail 80% reimbursement against the admitted VAT/ CST/ Entry Tax deposited in the account of the State Government (excluding strictly any tax paid by them arising out of a purely trading business), for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. The VAT/Entry Tax/CST reimbursement shall be applicable only to the net tax payable, after adjustment of input tax credit against the output tax liability.</p> <p>e) Government of India is in the process of introducing a uniform Goods & Services Tax (GST) regime throughout the country. In case GST becomes effective, the tax related benefits will be suitably modified.</p> <p>f) All new units shall be eligible for 100% reimbursement of the electricity duty on power including captive power consumed by the same unit or exported to the BSPHCL from the date of commencement of commercial production for a period of 5 years subject to the overall limit defined above. Electricity duty exemption will not be available on captive power exported to entities other than BSPHCL.</p>

- 6.3. Dovetailing with Central Government policies and schemes.—** Dovetailing of incentives with the Central Government schemes would be allowed under this policy subject to the condition that the same asset should not be covered under both the State and Central Government schemes. Thus, in case of grant availed/ to be availed by the promoter on a particular asset of the unit under any scheme of GoI, the approved project cost for the purpose of calculation of incentive under state policy will be arrived at by deducting the value of that asset.
- 6.4. Special Incentive Package for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Entrepreneurs**
- 6.4.1. Efforts shall be made to promote entrepreneurship among the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).
- 6.4.2. In case of a new unit established by a SC/ ST entrepreneur, the rate of interest for interest subvention will be 11.5% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower (except for Micro and Small units). In case of micro and small units being established by a SC/ ST entrepreneur, the rate of interest for interest subvention will be 13.8% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.
- 6.4.3. The overall limit of this subvention will be 34.5% of approved project cost (for priority sector projects)/ 17.25% of approved project cost (for non-priority sector projects). The upper limit of this subvention shall be INR 11.5 crore.
- 6.4.4. In case of a new unit established by a SC/ ST entrepreneur, she/ he will be entitled to avail 92% reimbursement against the admitted VAT/ CST/ Entry Tax deposited in the account of the State Government (strictly excluding any trading related taxes paid by them), with a maximum limit as defined below:
- i. **Non-priority sector:** 80.5% of the approved project cost
 - ii. **Priority sector:** 115% of the approved project cost
- 6.4.5. The State Government will provide Project Management Consultancy support to SC/ST entrepreneurs to facilitate the establishment and operation of units.
- 6.4.6. Special clusters shall be created for such entrepreneurs with common facilities.
- 6.5. Special Incentive Package for Women, Differently abled persons, War widows, Acid attack victims and Third gender entrepreneurs**
- 6.5.1. Efforts shall be made to promote entrepreneurship among the women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third genders.
- 6.5.2. In case of a new unit established by women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the rate of interest for interest subvention will be 11.5% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower (except for Micro and Small units). In case of micro and small units being established by women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the rate of interest for interest subvention will be 13.8% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.
- 6.5.3. The overall limit of this subvention will be 34.5% of approved project cost (for priority sector projects)/ 17.25% of approved project cost (for non-priority sector projects). The upper limit of this subvention shall be INR 11.5 crore.
- 6.5.4. In case of a new unit established by the entrepreneur, he/ she will be entitled to avail 92% reimbursement against the admitted VAT/ CST/ Entry Tax deposited in the account of the State Government (strictly excluding any tax

paid by them arising out of a purely trading business), with a maximum limit as defined below:

- i. **Non-priority sector.**—80.5% of the approved project cost
- ii. **Priority sector.**—115% of the approved project cost

6.6. Dovetailing with State Government Schemes for MSME Cluster Development.—Dovetailing of incentives under the Chief Minister Cluster Development Scheme for the establishment of the CFCs would be allowed

under this policy. It would however be subjected to the condition that the same asset should not be covered under both the industrial investment promotion policy and the said scheme. Thus, in case of incentives availed/ to be availed by the promoter on a particular asset of the CFC under the said scheme, the approved project cost for the purpose of calculation of incentive under industrial investment promotion policy will be arrived at by deducting the value of that asset.

6.7. Incentive for Private Industrial Park.—Incentives shall be made available for setting up of Private Industrial Parks. The effective guidelines of the scheme during the current policy period would be as follows:

- (a) The private industrial park can be established by an individual promoter/ partnership firm/ LLP/ company or any entity registered under the Companies Act/ Societies Act.
- (b) The promoter of the park has to arrange for the land. The State Government would not have any role in arranging the land for the park.
- (c) The minimum area of the proposed private industrial park should be 25 acres (3 acres in case of IT parks).
- (d) The land proposed for the park should be under the absolute possession of the promoter and should be free from any encumbrances. It should not have been obtained/owned by the promoter on leasehold basis.
- (e) At least 20% of the land would be earmarked for the general use/development of basic infrastructure/ green area and future requirements.
- (f) The industrial park shall have a minimum of 5 independent production units.
- (g) The promoter would be responsible for the allotment of land/plots to the individual units. The State Government would not have any role in this.
- (h) The promoter shall not create residential units in the industrial park or convert the industrial park into a real estate project. The industrial park shall only be used for industrial use. All private industrial parks shall be notified as industrial lands. Under no circumstances a private industrial park shall be put into any other use other than for industrial purposes.
- (i) The rates for the industrial plots in the private industrial park would be ascertained by the promoter. The State Government would not have any role in this.
- (j) The promoter of the park would create a fund called “Development Reserve Fund (DRF)” for the development of external infrastructure of the park. The promoter would contribute 5% of the fund collected through land allotment and 10% of the Annual Net Profit in the DRF. The DRF would be maintained in the form of a fixed deposit. A committee would be constituted for the operation of the DRF. The committee would consist of promoter/ representatives of the promoter and units operating in that park. At any point of time, a maximum of 33% of DRF can be used for the development of the

appropriate infrastructure. Further, the promoter would charge a maintenance fee from the operating units in the park. The same committee would be responsible for the operation of the fund created from the maintenance fee collected.

- (k) A private industrial park would be eligible for an interest subvention at the rate of 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower, to the extent of 30% of the approved project cost subject to a limit of INR50 crore. A sector specific private industrial park for the priority sector units (for e.g. food parks, leather parks, textile parks, IT parks etc.) would be given an interest subvention to the extent of 35% of the approved project cost subject to a limit of INR 50 crore. The promoter of the private industrial park shall be eligible for the interest incentive after the completion of the park.
- (l) In addition to the above, the private industrial park would also be eligible for the incentives mentioned under Section 6.2. Interest subvention shall be payable as per clause (k) above.
- (m) All the units set up in a private industrial park would be eligible to avail incentives under the industrial investment promotion policy, based on their eligibility.

7. ***Preferential purchase policy***

- (a) The purchase preference policy shall apply to only those MSME firms/units wherein the manufacturing activity results in significant value addition. Simply trading and packaging units shall not be eligible for price preference.
- (b) MSMEs quoting prices within 15% of the lowest eligible price bid of other bidder(s) shall be eligible for purchase preference in the state. In such cases the MSME unit shall be given an order of 15% of the total order value on the lowest eligible price bid. In case of a tie, the state based MSME units will be given the preference.
- (c) If it happens that two or more state based MSME units are within L1 + 15% range, all such MSMEs will be given an opportunity to accept the L1 price and the 15% of the total order value will be equally distributed amongst these MSME units.
- (d) The preferential purchase policy shall also apply to contractors and sub-contractors where at least 15% of the products should be procured from the local MSME units in case the product is manufactured in the State.
- (e) The criteria of turnover or age of the firm shall be relaxed by 50% for the MSME units based in Bihar if they meet the technical specifications of the products.
- (f) A list of products to be procured only from MSME sector in Bihar shall be notified by the State Government. Limited tenders amongst the MSME units based in Bihar shall be invited for the purchase of such products.

8. *Carry forward of the existing policy.*—The following are the provisions with respect to carrying forward the existing policy:

- (a) All projects which have been approved by the competent authority (as defined vide Circular No. 128, dated 16.01.2006 of Department of Industries, Government of Bihar) but have not commenced commercial production as on the effective date of the new policy will be given a choice between the existing policy and the new policy. These units shall have to apply separately with their choice or else they will be covered under the Industrial Investment Promotion Policy, 2016 by default. Those units which opt to be governed under

Incentive Policy, 2011 shall continue to be governed under that policy by the Department of Industries provided they shall commence Commercial Production/Operations by 31st March, 2017 or they shall complete the implementation and commence operations as per the timeline in the approved DPR (in case the approved timeline is beyond 31st March, 2017). Units that do not commence commercial production/operations till 31st March, 2017 shall not be eligible for any incentives under the Incentive Policy, 2011, subject to all existing conditions of the Department of Industries. Such units shall have to apply afresh under the current policy. Further, units which opt to be governed under this policy shall apply afresh to the competent authority as may be notified by the State Government.

- (b) Existing unit will continue to draw the incentive at rates and conditions of the Incentive Policy, 2011 till their limit is exhausted or on completion of the eligible period, whichever is earlier. A unit which has availed any incentive under the previous incentive policy shall not be eligible to apply under this policy, subject to the above mentioned clause.

9. Rehabilitation of Sick Units.—Industrial sickness is a part of the process of industrialization. It leads to unemployment, blockage of capital, loss of state revenue and non-utilization of assets. Hence it is necessary to take proper steps in order to rehabilitate the sick industries. The State Government is anxious about this and would take the following steps to check the sickness and to revive sick industries. Besides, steps will be taken for rehabilitation of such sick units, which have become sick due to natural calamities.

9.1. Industrial Rehabilitation Fund (Corpus Fund).—In order to revive the sick industry, a corpus fund will be created with the cooperation of the commercial banks, the State Government, industry associations and others. This corpus fund will provide financial assistance, in the least possible time, to sick micro, small and medium industrial enterprises for which the rehabilitation package has been approved.

9.2. Sickness in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) units

9.2.1. State Level Committee: All decisions for the rehabilitation of micro, small and medium enterprises will be taken by the state level committee (apex body) constituted under the chairmanship of the Director of Industries.

9.2.2. The State Level Committee would be empowered with necessary statutory powers in order to rehabilitate the sick industry. This committee will select an agency for preparing a rehabilitation package that enables effective implementation.

9.2.3. The guidelines of the Reserve Bank of India / SIDBI would be relied upon to identify sickness in micro, small and medium units and provide assistance towards selecting an agency for preparation of the rehabilitation package, so that the above mentioned rehabilitation package is approved.

9.2.4. The sick industries being revived will not require sickness certificate on an annual basis, instead the revival package shall specify the period of revival of sick units.

9.2.5. The industry declared sick by the state level committee would be eligible to receive relief and concessions from banks and financial institution as per the guidelines of RBI. These reliefs and concessions will be considered within a fixed time frame.

9.2.6. After the identification of sickness, rehabilitation package would be prepared within a timeline of 3 months and the state level institutions would monitor the rehabilitation process of sick industries.

9.2.7. The sick units that have availed the benefits of any Industrial Policy in the past may avail the facilities under this policy for the second time. If any sick unit wants to avail the benefits under the Industrial Policy for the second time it will avail only the difference between the prior availed amount and the proposed amount under new policy. But this facility for rehabilitation to the unit will be made available only on the

recommendation of the concerned committee constituted by the State Government. Such facility to the unit can be made available a maximum of two times only.

9.2.8. The date mentioned in the rehabilitation package will be considered as the cut-off date to determine the facilities.

9.3. *Sickness in Large Industries*

9.3.1 A committee would be constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Department of Industries to explore the possibility and to determine remedies for the revival of large scale industries and Public Sector Undertakings (PSUS) which are sick, not referred to the BIFR, and have a potential for revival. The committee will recommend the required relief provisions and concessions necessary for its rehabilitation, while considering the policy statement. The recommendations will be placed for final approval before the State Level High Powered Committee, under the Chairmanship of the Chief Secretary.

9.3.2 The rehabilitation package envisaged by BIFR or any statutory body constituted for this purpose such as BICICO/ BSFC / State Level Inter Institutional Committee of Bank shall be placed before the committee under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry for consideration of selected relief and concessions and the same will be placed for government recommendation through the existing State Level High Powered Committee under the chairmanship of the Chief Secretary.

9.3.3 A sick industry means such industry, which has been registered by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). However, the relief and concession to the unit will be provided from the cut-off date mentioned in the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) circulated by BIFR.

9.3.4 Those sick units which have availed the benefits of any Industrial Policy in the past may avail the facilities under this policy even a second time. If any sick unit wants to avail the benefits under the Industrial Policy for the second time it will avail only the difference between the prior availed amount and the proposed amount under new policy. But this facility for rehabilitation to the unit will be made available only on the recommendation of the concerned committee constituted by the State Government. Such facility to the unit can be made available a maximum of two times only.

10. *Policy implementation, monitoring & grievances*

10.1. *Policy Implementation*

10.1.1. A high profile Industrial Advisory Council would be constituted. The council may comprise of the Hon'ble cabinet ministers, chief secretary, principal secretaries of various concerned departments, head of various concerned government agencies, representatives of the state and national level business associations, state chiefs of public & private sector banks and leading businessmen/entrepreneurs of the state/ consultancy organization(s) etc. The council would meet bi-annually.

10.1.2. A State Investment Promotion Board (SIPB) will be constituted for providing approvals and clearances on setting up of new businesses. The competent officials from the various concerned departments would be deputed to clear the applications for investment. The Secretariat of the State Investment Promotion Board would act as the single contact point for the investors regarding claims of eligible incentives under the policy.

10.1.3. The Department of Industries would issue a framework containing detailed guidelines for the implementation of policy and disposal of claims for incentives. Common Application Form (CAF) will be used to provide all necessary clearances including the incentives under this policy.

10.1.4. The Secretariat of the State Investment Promotion Board will look after the day to day implementation of the policy. The Department in consultation with the office of the Director, Technical Development, office of the Director, Industries, office of the Director Food Processing, office of the Director Handloom and Sericulture, BIADA, etc. would publish a quarterly report on the achievements under the policy.

10.2. Policy Monitoring & Grievance Redressal

10.2.1. A policy monitoring committee would be constituted to monitor the implementation and identify the hurdles/bottlenecks for appropriate grievance redressal.

10.2.2. The implementation of the policy will be periodically reviewed for necessary facilitation and mid-course correction, wherever necessary.

10.2.3. A state-of-the-art “Centralized Helpdesk Call Centre” would be made operational to handhold the investors at each stage of interaction with the government.

10.2.4. All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Industrial Development Commissioner/ Principal Secretary, Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final and binding for all concerned parties.

10.3. General Conditions.—Following general conditions shall be applicable for availing the incentives under this policy:

If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of condition of this policy, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.

11. The definitions given in the Annexure-I to this policy shall be treated as part of this policy.

12. Industries mentioned in the negative list in Annexure - II would not be eligible for any incentive / subsidy.

13. This Policy will come into effect from the date of issue of this notification and will remain in operation till 5 years.

**By order of Governor of Bihar,
DR. S. SIDDHARTH,
Principal Secretary.**

Annexure I - Definitions

A. General Definitions

1. **Industrial Unit**.—Industrial units mean any unit / establishment engaged or to be engaged in manufacturing/processing/servicing industry under the following categories:

- a) Industries listed under the first schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as amended from time to time.
- b) Industries falling within the purview of the following boards/agencies: (i) Small Industries Board, (ii) Coir Board, (iii) Silk Board, (iv) All India Handloom and Handicraft Board, (v) Khadi and Village Industries Commission, (vi) Any other agency constituted by the Government of India or Government of Bihar for industrial development.
- c) Other categories:
 - (1) Mining or development of mines
 - (2) The maintenance, repair, inspection or servicing of any type of machinery of any description or vehicles or vessels or motorboats or trailers or tractors.
 - (3) The setting up or development of industrial area, industrial estate, integrated infrastructure development facility, export promotion industrial park, export promotion zone or growth centre.
 - (4) Providing special or technical knowledge or other services for the promotion of industrial growth.
 - (5) Providing engineering, technical, financial, managerial, marketing or other services or facilities for industry.
 - (6) Providing services relating to information technology (IT), telecommunication or electronics including satellite linkage and audio or visual cable communication.
 - (7) Tourism
 - (8) Healthcare
 - (9) Any activity defined under the priority sector of this policy

2. **Industrial Unit Category**.—For the purpose of administration of fiscal incentives, the projects can be categorized as follows:

- a) **Micro, Small and Medium Enterprise (MSME)**.—Government of Bihar follows the MSME definition laid out by Government of India as per MSMED Act, 2006 (as updated from time to time).
- b) **Large Industrial Unit**.—Large project is a unit in which the investment in plant and machinery is more than the investment threshold for Medium Enterprises as in MSMED Act, 2006 and is less than INR100 crore.
- c) **Mega Industrial Unit**.—Project with an investment of INR100 crore or more will be accorded Mega Industry status.

3. **New Industrial Unit**.— New Industrial unit means an industrial unit, in which commercial production has commenced within five years from the effective date.

4. **Existing Industrial Unit**.—An existing industrial unit means an industrial unit which has started their commercial production before commencement of this policy. An existing industrial unit which sets up a new unit in the same premises shall be considered as a new unit for administration of fiscal incentives if it is located in a distinct building/structure, maintains separately identifiable books of accounts, and separately deposits the taxes and duties that can be levied under any state act including the Provident Fund. Inclusion of new product in existing industrial unit will not be considered in the category of new units.

5. Approved project cost.—For the purpose of calculation of incentive under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the State Government. The approved project cost shall be the basis for determining the incentives.

6. Expansion/ Modernization/ Diversification

a. Expansion Project.—Projects which undertake expansion shall satisfy the following conditions: There shall be a minimum 50% increase in the initial installed production capacity.

b. Diversification Project.— Projects which undertake diversification shall satisfy the following conditions:- There shall be a minimum 50% increase in the approved project cost with respect to the original value without depreciation and establishment of new product line by the unit.

c. Modernization Project.—Projects which undertake modernization shall satisfy the following conditions: There shall be a minimum 50% increase in the installed production capacity as a result of modernization.

7. Date of Production.—The "Date of Production" of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually commences commercial production of the item for which the unit has been registered. As regards the date of production of Micro, Small and Medium units, the certificate issued by the respective General Manager, District Industries Centre or Managing Director, Bihar Industrial Area Development Authority would be valid. For large industries, the certificate issued by Director Technical Development will be acceptable. In case of any dispute regarding the date of production, the decision of the Principal Secretary, Department of Industries shall be final.

8. Scheduled Caste / Scheduled Tribe Entrepreneurs.—Scheduled Caste/Scheduled Tribe entrepreneurs mean such entrepreneurs who have established units as sole proprietor or invariably have a 100% share in partnership/private limited companies.

9. Women Entrepreneur.—Women entrepreneur means such domicile women of the state who are 1st generation entrepreneurs and who have established units as sole proprietor or invariably have a 100% share in partnership/private limited companies.

10. Differently Abled Entrepreneur.—Differently abled means such domicile of the state who comes under the purview of the Persons with Disabilities (Right of equal opportunity, Protection and Full Participation) Act, 1995 of the Government of India and holds certificate for such purpose, issued by competent authority. Differently abled entrepreneurs mean such entrepreneurs who have established units as sole proprietor or invariably have a 100% share in partnership/private limited companies.

11. Term Loan.—Term Loan means term loan sanctioned and disbursed by banks/financial institutions for financing.

12. Domicile of the State.—Domicile of the State means those who have been defined by the State Government, from time to time, as original domiciles of the state and who hold the certificate issued for this purpose by the competent authority.

13. Closed Industrial Unit

- i. In cases of incentive, exemptions and concessions given by the Department of Industries, the closed industrial unit means such unit which is established and holds Commercial Production Certificate issued by the competent authority of the Department of Industries and after the establishment of the industry, is closed for more than 6 months, without communicating any appropriate and acceptable reason to the General Manager, District Industries Centre.
- ii. "Sick unit" means an industrial unit declared sick by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industries

Companies (Special Provision) Act, 1985 / National Company Law Tribunal (NCLT) or by the State Level Committee for micro, small and medium industries headed by the Director of Industries or the High Level Empowered Committee headed by the Chief Secretary for large sector.

14. Permanent Employment.—Permanent Employment means direct salary/wages given by industrial unit to officers / employees / labours in category of management/skilled labour/ unskilled labour in the registered established industries it means that the employment provided through contractors is not included.

15. Land Bank .—Land Bank means private and government land acquired outside industrial areas for the purpose of projects related to manufacturing.

16. Effective date .—Effective date means the date on which the provisions of this policy come into force. This policy will remain in force for 5 years from the effective date.

B. Definition-Tourism Sector

1. *Tourist Places.*—Tourist places under this policy shall mean the places (districts or blocks or villages) mentioned in the table placed in section 3.2 of chapter 3 of this policy document that lists the various “Tourism segments” and “Our strategic advantage”.

2. *Tourism Service Provider.*—Any partnership firm or private limited company duly registered under law and providing any service related to travel and tourism, including that of a travel agent, transport operator, ticketing agent, tourist guide, or a home-stay owner.

3. *Hotel.*—Hotel projects should have facilities expected of establishments in the one to five star categories, as per the prevailing guidelines of hotels laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such hotels should also obtain necessary category certification from the competent authority.

4. *Heritage Hotel.*—A heritage hotel is a hotel run in a fort, fortress, palace, haveli, castle, hunting lodge or residence with heritage features, built prior to January 1950 and approved by the Ministry of Tourism, Government of India. Such heritage hotels should also obtain necessary category certification from the competent authority.

5. *Motel.*—A Motel project should have facilities conforming to the prevailing guidelines for motels laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such motels should also obtain necessary category certification from the competent authority.

6. *Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE)/Convention Centres*
A convention centre should have facilities as per the prevailing guidelines for convention centres, as laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such convention centres should also obtain necessary category certification from the competent authority.

7. *Resort.*—Resort projects should be of three-star category or above with facilities as per the prevailing guidelines of Ministry of Tourism, Government of India. Such resorts should also obtain necessary category certification from the competent authority.

8. *Tented Accommodation.*—A tented accommodation project should have facilities as per the prevailing guidelines for tented accommodation, as laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such tented accommodations should also obtain necessary category certification from a competent authority.

9. *Tourism & Hospitality Training Institute.*—An institute that offers tourism/hospitality courses that are recognized/ certified by regulatory authorities.

10. *Mega Tourism Unit.*—Projects capable of creating new employment for more than 150 persons with new investment of Rs. 75 crore and above (excluding the cost of

land) will be construed as mega tourism units. Units which are set up and which commence commercial operations during the operative period of this policy only will be eligible under this category. Hotels and resorts, multiplexes and malls shall be excluded from the definition of a mega tourism unit.

11. Amusement Park.—Amusement Park should have entertainment facilities such as rides, games, etc. built over a minimum plot area of 40,000 sq.m.(about 10 acres). Standalone commercial multiplexes shall not be treated as amusement parks.

12. Water Park.—Water Park should have a minimum of three water slides with a plot area of at least 20,000 sq.m. (about 5 acres) and a capacity to handle at least 100 sliders simultaneously.

13. Theme Park.—Theme Park should be based on a single or series of themes having a plot measuring at least 10,000 sq.m. (about 2.5 acres). It may have amusement rides, water slides, accommodation (at least ten lettable rooms), restaurant, theatre, shopping area, activity area and theme areas. It is, however, not mandatory for an amusement park to have all these features.

14. Adventure Sports (including water sports).—Adventure Sports should have the requisite infrastructure, equipment and trained staff, along with appropriate safety-and-rescue set-up, that will provide tourists with an opportunity to undertake permissible adventure and such other activities like mountaineering, river rafting, etc. All requisite permissions from various competent authorities as also a comprehensive insurance cover will have to be obtained beforehand.

15. Wayside Amenities.—Wayside amenities would be a complex comprising resting areas, toilets, cafeteria, shops, first-aid facilities, parking, souvenir booths, etc. located on National/State Highways and other district roads. It is, however, not mandatory to have all these features.

16. Ropeway.—A ropeway established under the prevailing act and rules.

17. Tourist Luxury Coach.—A tourist luxury coach is an air-conditioned coach with push back seats, used for normal transportation of tourists to different tourist destinations and for sightseeing of various tourist places, with a minimum seating capacity of 13 seats. It should be operated by valid All India Permit holder Tourist Transport Operators, recognized by Indian Association of Tour Operators (IATO) and registered in the state of Bihar.

18. Caravan.—A specially built vehicle, registered with any state transport department, which is used for the purpose of group oriented leisure travel and has at least 4 beds.

19. Health and Wellness Spa.—A health and wellness spa is a short-term residential/lodging facility with the purpose of providing spa services such as massages, yoga, meditation and other related treatments for rejuvenating the body.

20. Cruise Boats.—Any boat/yacht with a minimum seating capacity for 4 persons, which is licensed by the Transport Department, Government of Bihar, and has the capacity to operate in lakes/rivers of the state for pay-and-use facilities. Boats/yachts used by hotels to transport or entertain their guests and/or goods/raw materials will not be covered under this definition.

21. Science Centres, Planetariums, Museums.—A building in which objects of historical, scientific, artistic or cultural interest are stored and exhibited and is open for general public with or without ticket

C. Healthcare Sector

1. *Specialty Hospitals.*— Specialty hospitals are hospitals which have minimum 60 beds, out of which at least 30* beds are specifically for specialty services and at least 30 other beds for non-specialty services. The examples of speciality services are:

- Cardiology, Cardiovascular and Cardiothoracic surgery.
- Urology including Dialysis and Lithotripsy.
- Orthopaedics Surgery including Arthroscopic surgery and Joint Replacement.
- Emergency care for trauma.
- Endoscopic Surgery.
- Neurosurgery
- Oncology/Oncosurgery.
- Ophthalmology.
- Obstetrics & Gynaecology.
- ENT
- Any other specialization approved by CGHS/MCI/State Govt.

*As per CGHS norms, 50 beds in metro cities and 30 beds in non-metro cities

2. *Super-specialty Hospitals .*—Super Specialty hospitals are hospitals that offer at least three of following super specialty services, in addition to cardiology & cardio-thoracic surgery and specialized orthopaedic treatment facilities that include joint replacement surgery. These hospitals should have minimum 210 beds with at least 30 beds for each super-specialty and 30 non specialty beds. The examples are:

1. Cardiology	2. Gastroenterology
3. Endocrinology	4. Neonatology
5. Medical Oncology	6. Neurology
7. Nephrology	8. Pulmonary Medicine
9. Neuro Radiology	10. Cardio Thoracic Surgery
11. Rheumatology	12. Neuro Surgery
13. Paediatric Surgery	14. Oncology
15. Surgical Gastroenterology	16. Plastic Surgery`
17. Urology	18. Surgical Oncology

2. *Multi-Speciality hospitals.*—Multi-Speciality hospitals are hospitals that offer more than one of the following speciality services, along with a minimum of 90 beds out of which at least 30 beds are for each speciality and minimum 30 non-specialty beds. The examples of speciality services are:

- Cardiology, Cardiovascular and Cardiothoracic surgery
- Urology including Dialysis and Lithotripsy
- Orthopaedics Surgery including Arthroscopic surgery and Joint Replacement.
- Emergency care for trauma
- Endoscopic Surgery
- Neurosurgery
- Oncology/ Oncosurgery
- Ophthalmology
- Obstetrics & Gynaecology
- ENT

Annexure II - Negative list of industries

1. The following units will not be eligible for any support under this policy:
 - a. Units manufacturing narcotic drugs
 - b. Units manufacturing alcoholic beverages
 - c. Tobacco based industries
 - d. Units manufacturing asbestosThe above list will be called the negative list under the policy.
2. The State Government shall have the right to decide whether a unit falls under the negative list and can modify the above list accordingly.
3. As a general principle, any industry which impacts the environment adversely will be discouraged by the State Government for investment. Such industries will not be eligible for any incentive under this policy and be placed in the above mentioned negative list.

DR. S. SIDDHARTH,
Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 12-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>